राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • शुक्रवार • 31 जनवरी • 2025
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

सब से अधिक आनंद इस भावना में है कि हमने मानवता की प्रगति में कुछ योगदान दिया है। भले ही वह कितना कम, यहां तक कि बिल्कुल ही तुच्छ क्यों न हो
-डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन

अनहोनी हो ही गई

प्रयागराज महाकुंभ में जुटे श्रद्धालुओं के महासंगम ने अपने ही कुछ साथी श्रद्धालुओं की बलि ले ली। सरकारी ने चाक-चौबंद व्यवस्था की थी। कुंभ प्रबंधन को उच्चतम तकनीकी प्रणालियों से जोड़ा गया था। कबीले सरकार चप्पे-चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बलों की तनाती थी। मौनी अमावस्या से पूर्व मकर संक्रांति का पहला अमृत स्नान बिना किसी अप्रिय घटना के शांति से गुजर गया था। प्रतिदिन आने वालों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही थी। समूचा मीडिया मेला प्रबंधन का प्रशस्ति गान किया जा रहा था। श्रद्धालुओं की बाइटें चलाई जा रही थीं जिनमें वह मेले में आकर स्वयं को कृतार्थ बता रहे थे और मोदी योगी के जय-जय के नारे भी लगा रहे थे। व्यवस्था को पूरी तरह

श्रद्धालु हितैषी तथा अवरोध एवं व्यवधान रहित होने का इतना प्रचार कर दिया गया था कि किसी भी अनहोनी की आशंका की जगह नहीं बची थी। मीडिया और कुंभ के प्रचारक-समर्थक मौका मिलते ही आह्वान कर देते थे कि कुंभ आएं और पुण्य के भागी बनें। इस अति उत्साह में उन कमियों, परेशानियों और श्रद्धालुओं की कठिनाइयों की पूरी तरह अपेक्षा कर दी गई जो मीडिया और सोशल मीडिया के कुछ कोनों से बताई जा रही थी। अब सवाल उठता है कि जब मेला प्रबंधन को यह पूर्वानुमान था कि 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज पहुंचेंगे तो क्या सचमुच उन्होंने अपनी हर आशंका को निर्मल कर लिया था। भगदड़ का कारण यह था कि संगम किनारे शुभ मुहूर्त प्रारंभ होने के साथ ही डुबकी लगाने का पुण्य लेने के आशय से बड़ी संख्या में जाकर वहां सो गए थे। जब अनियंत्रित भीड़ का रेला बेरिकेड तोड़ता हुआ पहले डुबकी लगाने की मंशा से आगे बढ़ा तो पहले से वहां विश्राम कर रहे श्रद्धालु उनके पैरों तले आकर कुचलने लगे। कोई संदेह नहीं कि घायलों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई फिर भी यह सवाल उठता है इतनी अधिक अनियंत्रित भीड़ संगम स्थल पर तमाम व्यवस्थाओं के रहते कैसे पहुंची। और बेरिकेड तोड़ सकी। इस प्रश्न का उत्तर मेला प्रबंधन को अपनी कमियों में झांक कर ही तलाशना पड़ेगा। घटना के कुछ समय बाद कुंभ यथावत चलने लगा हो, लेकिन श्रद्धालुओं की मौत का दाग इस कुंभ पर लग ही गया। लिहाजा ऐसे मुद्दे पर अपेक्षा की जानी चाहिए कि लोग राजनीति के बजाय अधिक संवेदनशील होंगे।

पवित्रता पर छींटें

दो हिन्दुओं के बीच विवाह पवित्र बंधन है, जिसे विवाह के साल भर के भीतर नहीं तोड़ा जा सकता। चाहे इसके लिए दोनों पक्ष पारस्परिक रूप से सहमत क्यों न हों। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला देते हुए कहा जब तक असाधारण मुश्किल और असाधारण अनैतिकता न हो, जैसे कि हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 14 में वर्णित है। अदालत का कहना है, विवाह को भंग नहीं किया जा सकता। पीठ ने निर्णय दिया, तलाक की अर्जी दाखिल करने के संबंध में धारा 14 में विवाह की तिथि से एक साल की सीमा की व्यवस्था है। इस मामले में दोनों पक्षों ने हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा13-बी के तहत पारस्परिक सहमति से विवाह भंग करने की अर्जी दाखिल

की थी, जिसे सहारनपुर की कुटुम्ब अदालत ने अर्जी दाखिल करने की न्यूनतम अवधि पूरी न होने के चलते इसे खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने इस निर्णय का समर्थन करते हुए कहा, धारा14 के तहत कोई असाधारण स्थिति नहीं है। हालांकि अदालत ने उन्हें एक साल बाद फिर से आवेदन करने का विकल्प भी दिया। यह सच है कि समाज में विवाह की पवित्रता अभी भी अक्षुण्ण है, जिसे सीमित परिस्थितियों में ही कानूनन तोड़ा जाता है। अपने यहां अभी भी सामाजिक, पारिवारिक व आर्थिक परिवेश में तलाक लगभग अस्वीकार्य है। कुछ महीनों के साहचर्य के बाद अलग होने का निर्णय निश्चित रूप से जल्दबाजी या आवेश में लिया गया फैसला हो सकता है। हालांकि वयस्क और शिक्षित दंपति साथ न रहने का फैसला किन्हीं विशेष कारणों से ले रहे हों तो जबरन साथ रखने का दबाव डालना उचित नहीं कहा जा सकता। मात्र अनबन या आपसी झगड़ों के कारण ही दंपति अलग नहीं होते बल्कि अहंकार के टकराव के चलते भी वे साथ रहने को राजी नहीं होते। विवाह बंधन की पवित्रता को बरकरार रखने के लिए जरूरी नहीं है कि जबरन साथ रहने को मजबूर किया जाए। हालांकि अदालत ने वक्त देकर पुनर्विचार का मौका दिया है। इस दरम्यान यदि उन्हें गलती का अहसास होता है या आपसी सहमति बन जाती है तो बेहतर। वरना बुरे या बिगड़ते रिश्ते को ढोते रहने या असहनीय परिस्थितियों में जबरन जीने के बजाए संबंध विच्छेद करना मानसिक सेहत के लिहाज से भी उचित हो सकता है।

उपलब्धि/राजेश कुमार चौहान

विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ता भारत

हमारा देश विज्ञान के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सूरज-चांद तक नये-नये आविष्कार करने की ओर अग्रसर हो गया है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने श्रीहरिकोटा से 100वीं प्रक्षेपण अपने सुपरपावर राकेट जीएसएलवी 15 के जरिए एनवीएस सैटेलाइट को कामयाबी के साथ लांच किया। इस सफलता ने दुनिया को बता दिया कि हमारा देश विज्ञान के क्षेत्र में भी काफी विकास कर रहा है और देश के वैज्ञानिक भी किसी दूसरे देशों, अमेरिका, चीन आदि उन देशों से कम नहीं है, जो तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में अपने आपको सुपर पावर मानते हैं।

23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 को चांद पर इसरो ने सफलता उतारकर देश का मान बढ़ाया था, चंद्रयान 3 को संचालित करने में हमारे देश की महिला वैज्ञानिक और इंजीनियर ने जो चंद्रयान3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई उसने एक तो उन लोगों को आईना दिखाया जो बेटियों को कमजोर समझते हैं, दूसरा चंद्रयान 3 की लैंडिंग के समारोह में जो इन वैज्ञानिकों ने देश की संस्कृति के अनुसार पहनावा पाया था और श्रृंगार किया था उसने सारी दुनिया को देश की संस्कृति से भी परिचय कराया। इससे पहले भारत मूल की बेटी कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में कदम रख अपने माता-पिता के साथ भारत का भी मान दुनियाभर में बढ़ाया था। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थीं। इसके बाद 2 सितंबर, 2023 का दिन भी हमारे देश के लिए एतिहासिक दिन बन गया था, क्योंकि इस दिन इसरो ने पहले सूर्ययान आदित्य-एल1 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था।

वर्ष 2024 का पहला ही दिन हमारे देश के लिए खुशी लेकर आया था, क्योंकि हमारे देश ने विज्ञान के क्षेत्र में पहले ही दिन एक ओर कदम आसमान की ओर बढ़ाया था। इसरो ने विश्व का दूसरा और देश का पहला ऐसा सैटेलाइट लांच किया था जो अंतरिक्ष में रेडिएशन, आकाशगंगा, पल्सर और ब्लैक होल का अध्ययन कर इसके बारे जानकारी जुटाएगा। अगर सरकारें विज्ञान की पढ़ाई को देश में दुरुस्त करने के लिए गंभीरता दिखाए तो हमारा देश विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया के सभी देशों को पीछे छोड़ दे। भारत में विज्ञान के अनमोल हीरे हैं, लेकिन जरूरत है उन्हें तराशने की।

सत्ता, सियासत और समाजवाद

सामयिक
प्रेम प्रकाश

बीते एक दशक में भारत में कई परिवर्तन एक साथ हुए हैं। इन दस वर्षों में जहां एक खास विचारधारा की सरकार लगातार तीसरी बार चुनकर केंद्र में आई, वहीं इतिहास को लेकर हमारी दृष्टि का कंपास भी खासा घूम गया। पर इन तमाम परिवर्तनों के बीच कुछ खास सबक और आजादी के बाद के भारतीय सामाजिक-राजनीतिक चिंतन का एक बड़ा हासिल लगातार विमर्श के दायरे से बाहर भी होता गया है। विरासत और राजनीति की साझी चहलकदमी के दुर्ग में चिंतन और विकास का जो कोर खासतौर पर छूट गया है, वह है देश में समाजवादी चिंतन और विचारधारा की राजनीति। इतिहासकार और अपने स्तंभलेखन से लगातार चर्चा में बने रहने वाले रामचंद्र गुहा ने इस ओर ध्यान दिलाया है।

गुहा कहते हैं कि विचार क्षेत्र में अचानक कूद पड़े गाफिलों को भले लगता हो कि देश में समाजवादी परंपरा आज मृत्युशैय्या पर है। पर यह सच्च और विचार के गतिशील साझे को न देख-परख पाने की तंगनजरी है। सच्चाई इससे बिल्कुल जुदा है। हां, यह जरूर है कि समाजवादी विचार और परंपरा का प्रसार अब पहले की तरह नहीं है, पर यह आज भी भारतीय राजनीति के बीच सबसे बड़े नैतिक और रचनात्मक उपस्थिति के रूप में बरकरार है। इस संबंध में वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ होने वाले इतिहास लेखन पर भी अनुभव और विवेक के साथ बात होनी चाहिए।

खुद गुहा यह चर्चा छेड़ते हुए कहते हैं कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट, क्षेत्रीय दलों, आंबेडकरवादियों और खासकर हालिया वर्षों में जनसंघ व भाजपा, सभी के पास अपने इतिहासकार और उपलब्धियों का बखान करने वालों की अपनी-अपनी फौजें हैं, लेकिन समाजवादियों के साथ ऐसा नहीं है। समाजवादियों की वैचारिक मुखरता की तरह इतिहास लेखन के उनके नजरिए और रचनात्मक कार्य को अपेक्षित आकांक्षव वैल्यू नहीं मिला। अलबत्ता मौजूदा वक्त भारतीय राजनीति की सुदृढ़ता में समाजवादियों की भूमिका को रेखांकित करने के लिहाज से खासा मुफीद है। यह भी कि समाजवादी धड़े के शीर्ष प्रतिनिधियों में से एक मधु दंडवते की जन्म शताब्दी का यह वर्ष है। बात समाजवाद की करें तो विहार इस विचार परंपरा को सबसे ज्यादा संबल प्रदान करने वाला सूबा है। यह अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है मीडिया और अभिव्यक्ति के डिजिटल दौर में बिहार की इस खासियत और विलक्षणता पर चर्चा न के बराबर है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में वहां दो दशक से राजनीतिक स्थिरता ही नहीं, बल्कि समाजवादी विचार और नैतिकता की सुदृढ़ परंपरा भी सत्ता

के संतुलन को साधती रही है। बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री के राजनीतिक मूल्यांकन के लिए यह जरूरी है कि हम समाजवादी विचार के उत्स के साथ बिहार के साथ उसके संबंध को तारीखी तौर पर देखें-समझें।

आज यह बात लोगों को याद दिलाने की जरूरत है कि अशोक मेहता, मीनू मसानी, गंधु लिमये, जॉर्ज फर्नांडीस से लेकर शरद यादव तक किसी की पैदाइश बिहार की नहीं रही है। पर बिहार की जनता ने समाजवादी आंदोलन के इन दिग्गजों को संसद तक पहुंचाया। यह इस राज्य की राजनीतिक या लोकतांत्रिक समझ की एक ऐसी मिसाल है जो आज इस सूबे की पहचान से जुड़े कई पूर्वाग्रहों को न सिर्फ खंडित करती है, बल्कि एक नई बोधदृष्टि से उसे देखने की दरकार पेश करती है। बिहार की प्रयोगधर्मा धरती एक बार फिर नये सियासी प्रयोग को लेकर चर्चा में है। दिलचस्प है कि इस बार यह प्रयोग गांधी के नाम पर हो रहा है, सत्याग्रह के रूप में दिए गए अहिंसक संघर्ष के विचार सूत्र के साथ हो रहा है। यह पहली बार हो रहा है कि गांधी के बाद उनके रास्ते को सीधे-सीधे चुनावी राजनीति में आजमाने का कोई राजनीतिक जमात दावा कर रहा हो। बिहार में जनसुराज पार्टी और उसके सूत्रधार प्रशांत किशोर का दावा ऐसा ही है। इस दावे का सच तो आगामी विधानसभा चुनाव नतीजे के बाद ही साफ होगा पर नैतिक, सैद्धांतिक और तथ्यात्मक रूप से इस सियासी प्रयोग को लेकर कुछ बातें तो अभी से समझने की हैं। जिस नीतीश कुमार के आब्लास और दल में साथ रहकर प्रशांत किशोर ने बिहार की मौजूदा राजनीति का गुणधर्म देखा-समझा; आज वे इससे यह कहते हुए पल्ला झाड़ रहे हैं कि उनका यह साथ चुनावी रणनीतिकार के तौर पर था। अच्छा है कि सियासी पंडित या रणनीतिकार होने की उनकी छवि ही लोगों के बीच है। नहीं तो फिर यह समझने में भूल होती कि पदयात्रा और सत्याग्रह का रास्ता गांधी के अहिंसक संघर्ष का तो रास्ता हो सकता है, पर यह महज सत्ता तक पहुंचने का शार्टकट नहीं। यह अलग बात है कि वे इन दिनों इसी शार्टकट पर यकीन कर रहे हैं।

आज की तारीख में बिहार की राजधानी में गंगा के किनारे जनसुराजियों की पूरी जमात सत्याग्रह की बात कहते हुए तंबू-शामियाने के साथ कैंप कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम को एक साथ रखकर देखने पर कुछ सवाल स्वाभाविक तौर पर खड़े होते हैं। पहला सवाल तो यहीं कि इतिहास के किसी बड़े प्रयोग को लंबे समय के बाद क्या फिर से उसी प्रभाव के साथ रिक्रिएट किया जा सकता है। कला की भाषा में जिस रॅप्लिका की बात होती है, वह एक बड़े कलात्मक प्रयोग का हूबहू नकल होता है, पर असल कलाकृति के सामने उसकी कलात्मक कीमत बहुत कम आंकी जाती है। आमतौर पर इतिहास के बड़े घटनाक्रमों को अक्सर भी ऐसा ही माना जाता है कि उनकी स्मृति और प्रेरणा को जीवंत बनाए रखने के लिए हम भले जो भी करें पर उसके स्वरूप और प्रभाव का दोहराव मुश्किल है।

दरअसल, राजनीति को चुनावी स्टंट बना देने वाले माहिर आज कुछ करें न करें, बिहार की राजनीतिक विरासत और अस्मिता से जरूर खेल रहे हैं। बिहार की राजनीति के साथ जुड़ी समाजवादी विरासत को रौंदकर न तो व्यवस्था परिवर्तन का कोई मंसूबा संभव है, और न ही उस समाजवादी विरासत और नेतृत्व की अवहेलना जिसके एक छोर पर खड़े होकर नीतीश कुमार बीते दो दशक से बिहार में सत्ता की राजनीति का संतुलन साध रहे हैं। दरअसल, पद और पद त्याग के साथ प्रतिरोध की राजनीति की समाजवादी विरासत की अवहेलना भारत की समृद्धि राजनीतिक परंपरा का तिरस्कार तो है ही, यह बिहार की राजनीतिक अस्मिता के साथ भी खिलवाड़ है।

(लेख में विचार निजी हैं)

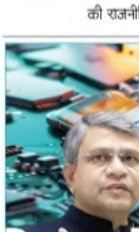

केंद्रीय रेलवे एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश के निर्यात में स्मार्टफोन दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। चार साल पहले यह 14वें पर था। स्मार्टफोन का निर्यात बढ़ना प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम का परिणाम है

वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, देश में इकोसिस्टम तेजी से विकसित हो रहा है। भारत के शीर्ष पांच निर्यातों में मोटर वाहन ऑइल ईंधन, स्मार्टफोन, विमानन ईंधन, हीरे और मोटर गैसोलीन शामिल हैं

क्रेडिट : मीडिया इनपुट्स

वाइडन की विरासत : पहले अफगानिस्तान, फिर बांग्लादेश और आखिर में सीरिया जहाद परस्त के रूप में उभरे। और आज एचटीएस टेररिस्ट आर्मी के चीफ, जिसके सिर पर 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम है, ने सीरिया के संविधान को नष्ट कर दिया और स्वयं को सीरिया का राष्ट्रपति घोषित कर दिया।

ब्रह्म चेलानी, सामरिक चिंतक
@Chellaney

आत्मोत्कर्ष
श्रीराम शर्मा आचार्य

सृष्टि के मुकुटमणि कहे जाने वाले मनुष्य का गौरव इसमें है कि उसकी चेतना व्यापक क्षेत्र में सुविस्तृत हो। शरीर और परिवार का उचित निर्वाह

करते हुए भी श्रम, समय, चिंतन और साधनों का इतना अंश बचा रहता है कि उससे परमार्थ प्रयोजनों की भूमिका निबाही जाती रह सके। आत्मीयता का विस्तार होने से शरीर और कुटुम्बियों की ही तरह सभी प्राणी अपनेपन की भावश्रद्धा में बंध जाते हैं और सबका दुःख अपना दुःख और सबका सुख अपना सुख बन जाता है। वसुधैव कुटुम्बकम की विश्व परिवार की आकांक्षा सर्वभूतेषु की भावनाएं बलवती होने पर मनुष्य का स्वार्थ-परमार्थ में परिणत हो जाता है। जो अपने लिए चाहा जाता था वही सब को मिल सके ऐसी आकांक्षा जगती है। जो व्यवहार, सहयोग दूसरों से अपने लिए पाने का मन रहता है। उसी को स्वयं दूसरों के लिए देने की भावना उमड़ती रहती है। लोक-मंगल की-जन-कल्याण की-सेवा साधना की इच्छाएं जगती हैं और योजनाएं बनती है। ऐसी स्थिति में पहुंचा हुआ व्यक्ति ससीम न रह कर असीम बन जाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाओं को पैरों तले कुचल कर फेंक देते हैं। अपनी आवश्यकताओं को घटाते हैं और निर्वाह को न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करने के उपरांत अपनी सत्प्रयोजनों में लगाये रहते हैं। देश, धर्म, समाज, संस्कृति के उत्कर्ष के लिए किए गए प्रकल्पों में उन्हें इतना आनन्द आता है जितना स्वार्थ परायण व्यक्तियों को विपुल धन प्राप्त करने पर भी नहीं मिल सकता। संसार के इतिहास में-आकाश में महामानवों के जो उज्ज्वल चरित्र झिलमिला रहे हैं वे सभी इसी आत्म-विकास के मार्ग का अवलम्बन करते हुए महानता के उच्च शिखर पर पहुंचे थे। संत, सुधारक, शहीद यह तीन सामाजिक जीवन के सर्वोच्च सम्मान है। महात्मा, देवात्मा और परमात्मा यह अध्यात्म जीवन की समग्र प्रगति के परिचायक स्तर हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए आत्मविकास के सिवाय और कोई मार्ग नहीं। व्यक्तिवाद को समूहवाद में विकसित कर लेना विश्वशांति का आधार माना गया है। अपनेपन को हम जितने व्यापक क्षेत्र में विस्तृत कर लेते हैं उतने ही विश्वासपूर्वक यह कह सकते हैं कि मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का सुनिश्चित मार्ग मिल गया।

रीडर्स मेल

सराहनीय फैसला

सर्वोच्च न्यायालय ने 21 जनवरी के फैसले में स्पष्ट रूप से आदेश पारित किया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत पुलिस के द्वारा कोई भी नोटिस व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के माध्यम से दिया जाना न्याय की परिधि में नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय से पुलिस की कार्यप्रणाली में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब पुलिस विभाग न तो व्हाट्सएप के माध्यम से धमकी दे सकता है और ना ही कोई आदेश भेज सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को कहा है कि इस आदेश को सुनिश्चित और स्पष्ट रूप से पालन करने के लिए राज्य सरकारों के द्वारा पुलिस महकमे के लिए आदेश पारित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आरोपित व्यक्ति के लिए एक बड़ी राहत की बात है। आए दिन इस बात की खबर आती थी कि वेबजह के तकनीकी संदेश से लोगों को काफी तनाव से गुजरना पड़ता था। पुलिस बिना वजह से अभियुक्त और आरोपियों को परेशान नहीं करेगी और कानूनन नोटिस जारी करेगी। इस निर्णय से देश में नकली अधिकारियों द्वारा पीड़ित नागरिक अपने रिपोर्ट दर्ज करा सकेंगे और बिना वजह इन नकली पुलिस वालों से आम आदमी डरेगा नहीं।

वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

संतुष्टि सबसे बड़ा धन

पुराणों में कहा गया है, गोधन, गज धन, बाजि धन, वाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। अर्थात सबसे बड़ा धन संतोष धन है। दिन-रात हम भौतिक सुखों को पाने की दौड़ लगा रहे हैं। हम इसे ही अपनी सुख-शांति मानते हैं, लेकिन स्थिति इसके उलट हो रही है, हमें सुख-शांति के बजाय दुःख और अशांति मिल रही है, इसका मतलब कहीं-न-कहीं हम सब गलत हैं और यह गलती है हमारी सोच की, हमारे विचारों की। संत-महात्माओं ने हमेशा से कहा है कि हमें सुख-शांति-संतुष्टि को तुम चाहते हो, वह तो सदैव तुम्हारे अंदर है, बस अंतर्मुख होने की जरूरत है। ज्ञान द्वारा हमारा चिंतन, हमारी सोच अंतर्मुखी हो सकती है। ज्ञान-चिंतन से वैराग्य, अपरिग्रह, ईश्वर के प्रति प्रेम व समर्पण का भाव जागता है, जिससे सहज ही संतोष धन की प्राप्ति होती है।

संदीप कुमार, मधुपुर, झारखंड

दर्दनाक घटना

महाकुंभ मेला में थोड़ी सी लापरवाही में तीस श्रद्धालुओं की मौत एवं दर्जनों के घायल होने की खबर हृदयविदारक है। मौनी अमावस्या की पावन वेला में संगम में डुबकी लगाने के लिए करोड़ों श्रद्धालु जमा हो गए थे। प्रशासन के निर्देशों को अनदेखा करते हुए अनेकों श्रद्धालु संगम तट पर शुभ घड़ी के इंतजार में विश्राम कर रहे थे। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उमड़ती भीड़ के दबाव में बैरीकेट टूट गई और चारों ओर अव्यवस्था फैल गई एवं विश्राम कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलते हुए भीड़ आगे बढ़ने लगी। भीड़ तंत्र को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को विशेष प्रशिक्षण देना चाहिए, एवं सभी की जिम्मेदारी निर्धारित होनी चाहिए। श्रद्धालुओं को भी आस्था के साथ अनुशासन का पालन करना चाहिए। जनसहयोग के अभाव में कोई भी व्यवस्था सफल नहीं हो सकती है। सभी लोगों को समझदारी से ही इस आयोजन की सफलता सुनिश्चित होगी।

हिमांशु शेखर, गया
letter.editorsahara@gmail.com

उपलब्धि/रजनीश कपूर

आयोजन से लें सबक

बीते कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ जैसे भव्य और जटिल आयोजन के सफल प्रबंधन को लेकर मीडिया में खबरों की भरमार थी। सोशल मीडिया में भी तमाम विशिष्ट व्यक्तियों और जानीमानी हस्तियों के वीडियो भी वायरल हो रहे थे। राज्य सरकार भी इस आयोजन को लेकर बड़े-बड़े दावे कर रही थी। इतने बड़े आयोजन का बिना किसी हादसे के सफल होना न केवल गर्व की बात है बल्कि इससे राज्य सरकार की प्रबंधन क्षमता का प्रमाण भी मिलता है, परंतु महा कुंभ में मौनी अमावस्या को हुई भगदड़ ने इस कार्यक्रम की कई कमियों की पोल खोल दी।

राज्य में सरकार किसी भी दल की क्यों न हो यदि इतने बड़े स्तर पर होने वाले आयोजन किए जाएं तो इससे प्रदेश सरकार की संगठनात्मक दक्षता, प्रशासनिक क्षमता और आपातकालीन स्थितियों से निपटने की तत्परता की परीक्षा भी होती है। यदि कोई भी अप्रिय घटना न घटे तो यह निःसंदेह प्रशंसनीय कार्य होता है। वहीं यदि कोई छुट-पुट घटना भी घट जाए तो हर कोई आयोजकों की बुराई करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। करोड़ों श्रद्धालुओं की उपस्थिति, बुनियादी सुविधाओं का प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन, यातायात नियंत्रण, और सुरक्षा प्रबंध, प्रदेश के प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में इतने बड़े स्तर पर होने वाले कार्यक्रम में 'बीआईपी' को झेलना प्रशासन के लिए एक बड़ी समस्या बन जाता है, परंतु सोचने वाली बात यह है कि जो सरकारी तंत्र आम जनता के लिए इतने बड़े स्तर पर आयोजन करती है, उसी तनाव के बीच यदि उसे बीआईपी कंधोवस्त भी करना पड़े तो उनके हाथ-पांव फूलना असाधारण नहीं माना जाएगा। ठीक इसी तरह यदि वही सरकारी ढांचा उसी दक्षता और इच्छाशक्ति से आम जनता की सेवा में भी उत्साहित दिखाई दे तो शायद किसी भी बीआईपी को भीड़ को चीरते हुए आगे निकलने की जरूरत ही न पड़े, लेकिन क्या ऐसा होता है? क्या वही तत्परता और तेजी जनता की समस्याओं, जैसे भ्रष्टाचार, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, और असमानता को हल करने में उपयोग की जाती है? यदि ऐसा हो तो देश का हर राज्य वहां के विकास में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। कुंभ में हुई भगदड़ की गहराई से जांच होने पर ही असल कारण का पता

चलेगा, परंतु यहां सवाल उठता है कि यदि इतने बड़े स्तर पर आयोजन किए गए तो क्या प्रशासन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि मेले में इतनी ज्यादा भीड़ आएगी? यदि शुरुआती दौर में इस बात का अंदाजा नहीं था तो जब कुंभ में इतनी ज्यादा भीड़ आने लगी तो प्रशासन ने इस दिशा में क्या कदम उठाए? विपक्षी पार्टियों का प्रश्न है कि क्या पूरा प्रशासन केवल बीआईपी कंधोवस्त में ही लगा था? यदि प्रशासन को यह पता था कि इस ऐतिहासिक आयोजन में करोड़ों श्रद्धालुओं के अलावा सैकड़ों बीआईपी भी आएंगे तो इस स्थिति से निपटने के लिए क्या इंतजाम किए गए? इन सभी बिंदुओं पर जवाबदेही को तय करना भी अनिवार्य होना चाहिए। ये सब तभी कामयाब होंगे जब इनमें जन भागीदारी भी बढ़ेगी। जिस तरह कुंभ जैसे आयोजन में सीमित समय और संसाधनों का कुशल उपयोग किया गया। यही मॉडल देश में गरीबी और बेरोजगारी के समाधान में भी लागू किया जा सकता है। इसके लिए कौशल विकास केंद्र बनाए जाएं जहां युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। कुंभ के आयोजन में जिस प्रकार जागरूकता अभियान चलाए गए, उसी तरह अशिक्षा के खिलाफ भी आंदोलन चलाया जा सकता है। इसके लिए प्रत्येक गांव और कस्बे में ऐसे स्कूल खुलें जो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में डिजिटल शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाए। कुंभ के दौरान सीमित बजट में बड़े आयोजन को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। यही रणनीति महंगाई और आर्थिक असमानता को दूर करने में उपयोगी हो सकती है। इसके लिए सरकार को मूलभूत वस्तुओं की सस्ती उपलब्धता पर जोर देना चाहिए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और मजबूत करना चाहिए।

आशावादी होना अच्छा है। महाकुंभ के प्रबंधन ने यह साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन किसी भी बड़ी चुनौती से निपटने की क्षमता रखता है। अगर यही इच्छाशक्ति और कुशलता भ्रष्टाचार, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, और असमानता जैसी जन समस्याओं को हल करने में लगाई जाए, तो उत्तर प्रदेश एक नये युग की शुरुआत कर सकता है। यह समय है कि कुंभ प्रबंधन से सीखे गए सबकों को जनहित में लागू किया जाए और एक ऐसा समाज बनाया जाए, जहां हर व्यक्ति को समान अवसर और सुविधाएं प्राप्त हों। जन समस्याओं का समाधान केवल एक प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक सामाजिक कर्तव्य है। इसके लिए सरकार को जनता का और बदले में जनता को सरकार का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो तभी एक नया उदाहरण स्थापित होगा। यदि एक प्रदेश में ऐसा हो सकता है तो संपूर्ण भारत में ऐसा होने में देर नहीं लगेगी।

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, स्काई लार्क, नवांग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - राजेश मिश्र ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
वर्ष-34, अंक 165
आर.एन.आई. सं. 53469/91 पंजीकृत संख्या UP/HR/GZB. 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कलमें पाठकों के लिए उपयोगी

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। शुक्रवार, 31 जनवरी 2025

सही निकला भारत

कनाडाई आयोग की रिपोर्ट ने आखिरकार दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। मंगलवार को आई इस रिपोर्ट में यह साफ कर दिया गया कि कनाडा में जून 2023 में हुई खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निजर की हत्या में विदेशी हाथ का कोई सबूत नहीं है। जाहिर है, इसके बाद कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोप मुंह के बल गिरे नजर आ रहे हैं।

ट्रूडो : आरोप झूठे निकले

ट्रूडो का झूठ | कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जब अपने देश की संसद में यह आरोप लगाया था, तब भी उनके उस कृत्य को गैरजिम्मेदाराना माना गया था। भारत ने आरोपों को बेतुका बताते हुए उनसे सबूत मांगे थे जो वह कभी दे नहीं पाए। और अब उनके ही देश के आयोग की रिपोर्ट बताती है कि उनका वह बयान सफेद झूठ पर आधारित था।

रिश्तों में गिरावट | जस्टिन ट्रूडो के झूठे आरोपों के बाद स्वाभाविक ही दोनों देशों के रिश्तों में गिरावट आई। भारत ने ट्रूडो के बयानों को राजनीति से प्रेरित बताया था। लेकिन कड़ा भारत विरोधी रुख भी घरेलू राजनीति में उनकी खास मदद नहीं कर पाया। आखिर उन्हें अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा करनी पड़ी। अब वह नया नेता चुने जाने तक के लिए इस पद पर हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल | अब जब निजर हत्याकांड से जुड़े कनाडा के आरोप पूरी तरह खारिज हो चुके हैं, तब भारत विरोधी तत्वों को खुली छूट देने के मसले पर नए सिरे से बात होनी चाहिए। भारत पहले से कहता रहा है कि कनाडा और अन्य यूरोपीय देशों में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अलगाववादी तत्व जिस तरह की भारत विरोधी गतिविधियां खुलेआम चला रहे हैं, उन पर प्रभावी रोक लगाने की जिम्मेदारी उन देशों की है। कनाडा सरकार को तो उस पर काम करना ही चाहिए, अन्य देशों को भी इस पहलू पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।

रिश्तों पर हो पुनर्विचार | चूंकि कनाडा में इसी साल चुनाव होने हैं, इसलिए दोनों देशों के पास मौका है कि अतीत की गलतियों को पीछे छोड़ते हुए रिश्तों को पटरी पर लाने की नए सिरे से कोशिश की जाए। अगर कनाडा सरकार अपनी भूल समझते हुए अहम मसलों पर अपने रुख में पॉजिटिव बदलाव लाती है तो द्विपक्षीय रिश्तों को बेहतर भविष्य देना मुश्किल नहीं होगा।

रोज़-ब-रोज़

रुकना नहीं है

शैलेंद्र पांडेय

बस, ट्रेन और फिर सुबह से पैदल... संदीप देवलिया चलते ही जा रहे हैं। नैनीताल से संगम तक का सफर तय करने में लगभग 24 घंटे का समय लग गया उन्हें। न ट्रेन में रिजर्वेशन था और न कुंभनगरी में उनके पास ठहरने की कोई जगह है। इसके बाद भी चेहरे पर कोई शिकन नहीं। इतनी मेहनत का फल जो मिल चुका है, संगम में डुबकी लगा ली है उन्होंने।

मौनी अमावस्या पर जिस जगह हादसा हुआ, उसी जगह और उस मनहूस वक्त के करीब 20 घंटे बाद संदीप से मुलाकात हुई। उन्हें भगदड़ की खबर थी, फिर भी वह चले आए। क्यों? 'क्योंकि इसी के लिए तो घर से चले थे।' संदीप आगे बढ़ जाते हैं। कुछ घंटों की नींद के बाद उन्हें फिर वापसी का सफर करना है। उनके हटने से घाट पर जो जगह खाली हुई थी, वह तुरंत ही भर गई। किसी त्रासदी से मिले जख्म भी ऐसे ही भरते हैं। दुख और आघात को हमारा दिमाग कैसे झेलता है और कैसे उससे उबरता है, इस पर अमेरिकन ब्रेन फाउंडेशन की लिसा एम. शुलमैन ने एक किताब लिखी है। नाम है, **'Before and After Loss: A Neurologist's Perspective on Loss, Grief and Our Brain'**। इसके मुताबिक, किसी भी तरह के दुख, पीड़ा, संकट को हमारा दिमाग एक खतरे की तरह लेता है। उस समय दो ही रिएक्शन होते हैं, लड़ो या फिर भागो। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और दिल तेजी से धड़कने लगता है। तनाव हावी हो जाता है और दिमाग नए नर्व कनेक्शन बनाना शुरू कर देता है। लेकिन, यह स्थिति पलट भी सकती है, थेरेपी, माइंडफुलनेस या किसी रचनात्मक काम से।

आस्था हमारे लिए ध्यान का ही काम करती है। हमारा अटूट विश्वास किसी भी दुख में हमें देर तक डूबे नहीं रहने देता। विश्वास कि, अब जो होगा, अच्छे के लिए होगा और पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ना ही समझदारी है। कुंभनगरी में जुटे करोड़ों श्रद्धालु भी यही कर रहे। शुलमैन कहती हैं कि अगर हम दुख को समझ कर उस पर ठीक से काम नहीं करेंगे, तो वह जीवन में रुकावट डालता रहेगा। और रुकना अच्छा नहीं होता है। गंगा-यमुना लगातार बह रही हैं, श्रद्धालुओं का सैलाब बह रहा है, संदीप को भी लगातार बढ़ना है।

एकदा

जान से बढ़कर पेड़

उन दिनों की बात है जब थार रेगिस्तान में होने के बावजूद बिश्नोई गांवों में बहुत हरियाली थी। यहां खेजड़ी के पेड़ों की संख्या बहुत अधिक थी। खेजड़ी की लकड़ी बहुत अच्छी तरह से जलती थी। इसलिए अक्सर जलाने के लिए इस लकड़ी का उपयोग किया जाता था। एक दिन मारवाड़ जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के सैनिक लकड़ी काटने के लिए उस ओर आए जहां खेजड़ी के पेड़ बहुत अधिक थे। अमृता बिश्नोई अपनी तीन बेटियों के साथ घर पर थी। उसे जैसे ही यह सूचना मिली कि सैनिक खेजड़ी के पेड़ों को बेरहमी से काट रहे हैं, वह तुरंत उस ओर भागी। वह उस पेड़ से लिपट गई जिसे सैनिक काटने जा रहे थे। सैनिक चिल्लाए, 'पागल हो क्या? अपनी जान को क्यों न्यौता दे रही हो? एक झटके में तुम्हारा गला कुल्हाड़ी से कट जाएगा।' अमृता बिना डरे बोली, 'सिर साटे, रुख रहें तो भी सस्ता जांण' यानी जान की कीमत पर एक पेड़ बचाया जाता है तो सही है। सैनिकों ने अमृता की बातों पर ध्यान नहीं दिया। अचानक एक सिपाही से कुल्हाड़ी चल गई और अमृता की जान चली गई। सैनिक उल्टे पांव भाग गए। जब राजा को यह बात पता चली तो वह दौड़े-दौड़े बिश्नोई परिवार के पास गए। उनसे माफी मांगी और कहा कि आगे से पेड़ों को नहीं काटा जाएगा। वर्ष 1983 में खेजड़ी के पेड़ को राजस्थान का राजकीय वृक्ष घोषित किया गया। अमृता बिश्नोई और बिश्नोई समाज को देश के पहले पर्यावरणविद के तौर पर जाना जाता है।

Subrata Char

संकलन : **रेनू सैनी**

कार्यकाल की शुरुआत दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के साथ हुई थी, अब अंत पर हैं निगाहें

BJP प्रेजिडेंट नड्डा का आखिरी शॉट !

राज कुमार सिंह

BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से जगत प्रकाश नड्डा की विदाई वेला निकट है। उनका कार्यकाल पिछले साल फरवरी, 2024 में ही पूरा हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव और फिर राज्यों के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बढ़ाया जाता रहा। BJP के संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले 50% राज्य इकाइयों का संगठनात्मक चुनाव होना अनिवार्य है। इस प्रक्रिया में विलंब हुआ। फिर नए अध्यक्ष के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहमति भी जरूरी है। अब संकेत हैं कि फरवरी के मध्य तक BJP को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा।

शुरुआत हार से | यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या नड्डा जाते-जाते BJP को दिल्ली जिता पाएंगे? यह सवाल इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि नड्डा के पूर्णकालिक अध्यक्ष काल की शुरुआत में हुए फरवरी, 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा था। वह जून, 2019 में BJP के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे, लेकिन पूर्णकालिक अध्यक्ष जनवरी, 2020 में ही बने। इस तरह फरवरी, 2020 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव नड्डा की अध्यक्षता की पहली चुनावी परीक्षा थी, लेकिन BJP के हिस्से हार ही आई।

मिले-जुले परिणाम | राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा का पूरा कार्यकाल पार्टी के लिए मिले-जुले परिणाम वाला रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को लगातार दूसरी बार बहुमत मिलने पर तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह को केंद्रीय गृह मंत्री बनाए जाने के बाद नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके तुरंत बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए। हरियाणा में बहुमत से वंचित BJP को नई बनी क्षेत्रीय पार्टी JJP से गठबंधन कर सरकार बनानी पड़ी, लेकिन पांच साल बाद 2024 के चुनाव में सत्ता की 'हैट्रिक' से पार्टी ने सारी भरपाई कर ली। महाराष्ट्र में BJP और शिवसेना में तकरार के चलते सरकार बनने-बिगड़ने का खेल लंबा चला। लेकिन 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में BJP नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन की एकतरफा जीत ने उसके तमाम प्रयोगों पर कामयाबी की मुहर लगा दी।

कहीं जीत की खुशी, कहीं हार का गम

- महाराष्ट्र के प्रयोगों पर जीत का ठप्पा
- झारखंड में गंवाई सत्ता, वापस न मिली
- संघ से रिश्तों पर बयान को लेकर विवाद

कई राज्यों में लगे झटके | नड्डा के अध्यक्ष काल में झारखंड में गंवाई अपनी सत्ता BJP पांच साल बाद 2024 के चुनाव में भी हासिल नहीं कर पाई। दक्षिण भारत में अपने एकमात्र गढ़ कर्नाटक और नड्डा के गृह राज्य हिमाचल प्रदेश में भी BJP सरकारें उन्हीं के अध्यक्ष काल में सत्ता से बेदखल हुईं। बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के जरिये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड को तीसरे नंबर पर धकेलते हुए BJP सबसे बड़ा दल जरूर बनी। लेकिन इस भितरघात से खफा नीतीश NDA छोड़ कर RJD और कांग्रेस के महागठबंधन में चले गए। वह मुख्यमंत्री बने रहने में भी सफल रहे। हालांकि नड्डा के ही अध्यक्ष काल में नीतीश पिछले साल के शुरू में फिर पाला बदल कर NDA में लौट भी आए।

सबसे बड़े राज्य में जीत | देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में BJP लगातार दूसरी बार बहुमत पाने में सफल हुई। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी नड्डा के अध्यक्ष काल में ही जीत मिली। 2018 के आखिर में हुए विधानसभा चुनावों में इन तीनों राज्यों की सत्ता से BJP को कांग्रेस ने बेदखल कर दिया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया के दल बदल से BJP एमपी में तो 2020 में ही सरकार बनाने में सफल हो गई, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए उसे 2023 के आखिर में हुए विधानसभा चुनावों का इंतजार करना पड़ा।

बहुचर्चित बयान | लोकसभा चुनाव में BJP की सीटें 303 से घटकर 240 भी नड्डा के अध्यक्ष काल में ही हुईं। फिर भी लोकसभा चुनाव के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाबत दिए गए एक इंटरव्यू के अलावा उनका कार्यकाल निर्विवाद माना जाता है। उस इंटरव्यू में नड्डा ने कहा था कि जब BJP नई और कमजोर थी, तब उसे संघ की मदद की जरूरत थी, अब BJP बड़ी और समर्थ हो गई है। वैसे नड्डा के अध्यक्ष काल के बाबत कहा जाता है कि ज्यादातर फैसले नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने ही लिए, जिन पर मुहर लगाने का काम जेपी नड्डा ने किया। नड्डा पर मोदी और शाह के विश्वास का ही प्रमाण है कि अध्यक्ष काल समाप्त होने से पहले ही उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाकर स्वास्थ्य और रसायन सरीखे दो महत्वपूर्ण विभाग सौंप दिए गए।

कैसी होगी विदाई | फिर भी नड्डा की ख्वाहिश होगी कि अध्यक्ष पद से उनकी विदाई दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के साथ हो। बेशक यह आसान नहीं, पर असंभव भी नहीं। इतना तो लगभग तय माना जा रहा है कि BJP 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में 2015 और 2020 से बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

रुपये के गिरने से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता

नीलांजन बानीक

13 जनवरी को रुपये ने पिछले दो वर्षों में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट देखी। यह उस रोज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 86.62 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर बंद हुआ। रुपये की इस गिरावट से कई जानकार फिक्रमंद हैं। असल में, रुपया कमजोर होता है तो दूसरे देशों से सामान खरीदने की लागत बढ़ जाती है। इससे चालू खाता घाटा (करेंट एकाउंट डेफिसिट या CAD) बढ़ता है। जब यह घाटा बढ़ता है तो कच्चे तेल की ऊंची लागत के कारण भारत में महंगाई दर पर दबाव बढ़ता है। इसका जिक्र इसलिए क्योंकि भारत अपनी जरूरत का दो तिहाई से अधिक कच्चा तेल आयात करता है।

गिरावट का ट्रेंड | वर्ष 2000 से 2004 के बीच इसमें सालाना 0.4% की गिरावट आई। लेकिन 2005 से 2014 के बीच यह बढ़कर 3.4% हो गया। 2015 से 2025 तक कमोबेश यही ट्रेंड बना हुआ है। इस दौरान इसमें सालाना 3.5% की गिरावट आई है। रुपये की ऐसी चाल के दो कारण होते हैं-

- पहला है महंगाई दर। अगर भारत की महंगाई दर अमेरिका से अधिक होती है तो माना जाता है कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होगा।
- दूसरा कारण असेट मार्केट अप्रोच है यानी इसमें रुपये की वैल्यू इस बात पर निर्भर करती है कि देश में कितनी पूंजी आ रही है और कितनी बाहर जा रही है।

महंगाई का चक्कर | इतिहास बताता है कि अमेरिका में महंगाई दर भारत से कम रही है। इसकी वजह श्रमिकों की उत्पादकता में अंतर है। ILO के 2025 के अनुमान के मुताबिक, भारत में प्रति श्रमिक उत्पादकता 25,431 डॉलर है, जबकि अमेरिका में 153,446 डॉलर।

विदेशी निवेशकों की बिकवाली | ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। उन्हें लगता है कि अमेरिका में उन्हें यहां से अधिक रिटर्न मिलेगा। उन्होंने पिछले अक्टूबर में भारतीय बाजार से 1.13 करोड़ रुपये निकाले। नवंबर में उन्होंने और 41,872 करोड़ की बिकवाली की। इसलिए मुझे लगता है कि रुपये में गिरावट आगे भी बनी रहेगी। लेकिन अगर सालाना गिरावट की दर 4% से अधिक हो जाए, तो वह देश के लिए अच्छा नहीं होगा।

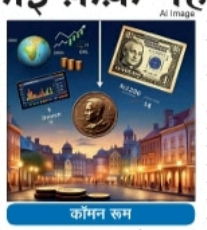

AI Image

कॉमन रूम

डॉलर में तेजी आएगी | चीन अभी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वहां 2021 में जो ग्रोथ रेट 8.1% थी, वह 2025 में घटकर 5% से भी नीचे जा सकती है। ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने से भारतीय निर्यात पर भी असर हो सकता है। टैरिफ की वजह से अमेरिका का व्यापार घाटा भी कम हो सकता है, जिससे डॉलर में और तेजी आएगी।

ग्लोबल ग्रोथ है अहम | दूसरी तरफ, ट्रंप के गाजा जंग में सुलह करवाने से और अगर उन्हें रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाने में कामयाबी मिलती है तो इससे भी कच्चे तेल के दाम में और कमजोरी आएगी। ऐसा होने पर ग्लोबल इनकम बढ़ेगी, जिसका भारत के निर्यात पर पॉजिटिव असर होगा। रुपये की कमजोरी का एक फायदा यह भी होगा कि इससे बिजनेस के ठिकाने के तौर पर भारत का आकर्षण बढ़ेगा क्योंकि इससे श्रम, जमीन और पूंजी विदेशी निवेशकों के लिए सस्ती पड़ेगी।

IT को मदद | 2022 में भारत 111 बिलियन डॉलर से अधिक रेमिटेंस हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बना था, जो 49 बिलियन डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के दोगुने से भी अधिक था। कमजोर रुपये से देश के सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में भी इजाफे की उम्मीद है।

(लेखक महिंद्रा यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में प्रफेसर हैं)

बजट का क्यों हो रहा बेसब्री से इंतज़ार

नरेन्द्र नाथ

संसद का बजट सत्र आज से शुरू होगा। इसमें नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली NDA सरकार तीसरे टर्म का दूसरा बजट पेश करेगी। पिछले कुछ वर्षों का यह सबसे अहम बजट माना जा रहा है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था किस ओर जाएगी, शनिवार को पेश होने वाले बजट में उसका मुकम्मल खाका देखने को मिलेगा। वहीं सियासत के लिए भी यह सत्र बहुत अहम होगा क्योंकि इस बार नए राजनीतिक समीकरणों को बनते-बिगड़ते भी देखा जा सकता है।

इधर-उधर का डर

बजट सत्र देश की सियासत की तस्वीर दिखा सकता है। पिछले साल जून में आम चुनाव के बाद जब लोकसभा में BJP का आंकड़ा बहुमत से नीचे आया, तो कहा गया कि मोदी सरकार के लिए अगले पांच साल कठिन हो सकते हैं। लेकिन फिर पहले हरियाणा और बाद में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद NDA ने मजबूत वापसी कर ली और विपक्ष फिर बैकफुट पर चला गया। यह सत्र ऐसे समय में हो रहा है, जब उद्धव ठाकरे की अगुआई वाली शिवसेना हो, या शरद पवार की अगुआई वाली NCP, इन दलों में उठापठक की खबरें आ रही हैं। सत्र में यह देखना दिलचस्प होगा कि इनके सांसद कितने एकजुट रह पाते हैं। साथ ही, दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम का भी व्यापक असर सत्र के दौरान दिखेगा।

उधर, नवीन पटनायक की अगुआई वाले BJD और जगन रेड्डी की अगुआई वाली YSR कांग्रेस भी पिछले साल चुनाव में मिली करारी पराजय के बाद अपने दल को एकजुट रखने में संघर्ष कर रहे हैं। यह सत्र उनके लिए भी अहम होगा कि उनके दल के सांसद कितने एकजुट रह पाते हैं।

हाल के दिनों में दोनों दलों के कुछ राज्यसभा सांसद पार्टी छोड़ चुके हैं। सूत्रों के अनुसार, कुछ और सांसद सत्र के दौरान पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं और कहीं न कहीं इनके सत्तारूढ़ दल से ही जुड़ने की खबर है। अगर ऐसा हुआ तो राज्यसभा का पूरा समीकरण बदल जाएगा और BJP वहां भी पूरी तरह मजबूत हो जाएगी। लेकिन सियासत के हिसाब से सबसे अहम यह होगा कि वक्फ बिल संसद में किस तरह पेश और पास होता है। NDA सरकार ने साफ संकेत दे दिया है कि किसी भी सूरत में इस सत्र में वह इस बिल को पास करवा कर रहेगी। उसका दावा है कि इसके लिए दोनों सदनों में उसके पास पर्याप्त नंबर हैं। पिछले साल जब यह बिल पेश हुआ था, तब सरकार की सहयोगी TDP ने भी इसके कुछ प्रावधानों पर चिंता जताई थी। वहीं दूसरे सहयोगी JDU के कुछ नेताओं में भी इस बिल को लेकर सवाल थे। लेकिन अब दोनों दल इस बिल पर सरकार के साथ दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति में विपक्ष के लिए इस बिल पर अपना स्टैंड सामने रखना बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। वह भी तब, जब महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद I.N.D.I.A. बिखरा-बिखरा सा दिखने लगा है और अधिकतर क्षेत्रीय दल हाल के दिनों में 'एकला चलो रे' की रणनीति पर बढ़ते दिख रहे हैं।

विशुद्ध राजनीति

कसौटी

नैरेटिव पर भी असर

भले NDA इस सत्र में आंकड़ों के हिसाब से अधिक मजबूत दिख रहा है, लेकिन सियासी तौर पर इस बार उसके सामने दूसरी तरह की चुनौतियां हैं। हाल के वर्षों में शायद ही किसी बजट पर आम लोगों से लेकर देश के उद्योग जगत तक की इस कदर उम्मीद भरी निगाहें टिकी हो। हाल के सालों में मिडल क्लास उपेक्षित महसूस कर रहा है। बजट से पहले ही इस वर्ग ने सरकार पर दबाव बना लिया है और माना जा रहा है कि BJP अपने सबसे मजबूत और कोर समर्थक वर्ग को इग्नोर करने का जोखिम नहीं लेगी। मिडल क्लास के लिए इस बजट में बड़ा पैकेज सामने आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो BJP और केंद्र सरकार इस वर्ग के बीच अपनी उपस्थिति और मजबूत करेगी। यह वर्ग नैरेटिव बनाने में भी अहम योगदान निभाता है। अपेक्षा के अनुरूप बजट नहीं हुआ तो मिडल क्लास की प्रतिक्रिया भी देखने लायक होगी। यही कारण है कि इस बार बजट का इतनी बेसब्री से इंतजार है। सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद उस पर पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण में भी मिडल क्लास की बेचैनी पर बात हो सकती है। साथ ही, तीसरे टर्म में मोदी सरकार की आगे की रणनीति और राजनीति की दिशा क्या होगी, इसकी भी झलक उनके भाषण में दिखेगी।

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ अमेरिका की चुनौती

29 जनवरी का लेख 'चीन के DeepSeek से क्यों डरा अमेरिका' पढ़ा। चीन के Deepseek R-1 चैटबॉट ने AI उद्योग में अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दी है, जिससे अमेरिकी चिप और सॉफ्टवेयर कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई। इसकी ओपन-सोर्स विशेषता और कम लागत पर निर्माण ने AI क्षेत्र में एक नया नजरिया पेश किया है। चीन की रणनीति AI के व्यावहारिक एप्लिकेशंस पर केंद्रित है, जबकि अमेरिका बुनियादी अनुसंधान और जेनरेटिव AI पर जोर देता है। हालांकि, अमेरिका का मुख्य संघर्ष अब सिर्फ चीन से नहीं, बल्कि अपनी कंपनियों की कमाई घटने से भी है। चीन खुलकर Deepseek पर पहल करता है और सस्ते मॉडल पेश करता है तो अमेरिकी कंपनियों के लिए फिर से रेवेन्यू मॉडल डिवेलप करने होंगे।

अंशु भारती, ईमेल से

■ फिर न हो ऐसा हादसा

प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के मौके पर भगदड़ मची और उसमें कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई घायल हो गए। यह घटना बहुत ही पीड़ादायक है। कई धार्मिक समारोहों में भी इस तरह की दुर्घटनाएं होती रही हैं। इतनी ज्यादा भीड़ में दुर्घटना होने की आशंका रहती ही है। लेकिन सबाल उठना लाजिमी है कि व्यवस्था में कहीं न कहीं कमी रह गई। अब सुरक्षा इंतजाम पुख्ता किया जा रहा है। स्टेशन पर ही यात्रियों को आगे बढ़ने से रोक दिया जा रहा है। प्रॉपर बैरिकेडिंग हो रही है। यह कहना भी जरूरी है कि इस घटना पर किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि ऐसी दुर्घटना फिर से न हो।

योगराज थूपड़, द्वारका मोड़

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

ट्रंप ने रोक दी पाकिस्तान की फंडिंग – एक खबर
– अब जेबखर्ची के लिए नया ड्रामा जल्द देखने को मिलेगा।

मोहन रावत

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

hindi.speakingtree.in

ध्यान के लिए ज़रूरी है इच्छाओं से मुक्त मन

जे. कृष्णमूर्ति

आज की सुबह उन सुंदर और सुहानी सुबहों में से थी जो अभूतपूर्व होती हैं। सूरज अभी निकल ही रहा था और आप उसे चीड़ और यूकेलिप्टस के पेड़ों के बीच देख सकते थे। वह दूर तक फैले हुए उस जल के ऊपर था, सुनहरे रंग की चमक पैदा करता हुआ ऐसा प्रकाश जो केवल पहाड़ों और समुद्र के बीच होता है। यह एक अत्यंत शांत, स्तब्ध और स्वच्छ सुबह थी, उस अद्भुत प्रकाश से भरी हुई जिसे आप अपनी आंखों से ही नहीं बल्कि अपने हृदय से भी देखते हैं। और जब आप इसे देखते हैं, तो आकाश पृथ्वी के बहुत निकट होता है, और आप उसके सौंदर्य में खो जाते हैं।

शायद आप जानते हों कि ध्यान केवल एकांत में करना चाहिए, रात्रि की निस्तब्धता में या उषाकाल की नीरवता में। जब आप एकांत में ध्यान करें, तो सचमुच एकांत हो। इस एकांत का आगमन तभी होता है जब मन विचार से मुक्त हो जाता है। जब कोई इच्छा आप पर हावी होती है और उसके पीछे भागते हुए आपका मन अतीत और भविष्य में भटकने लगता है, तो वहां एकांत नहीं होता। केवल वर्तमान की विराटता में ही इस एकाकीपन का आना संभव होता है।

मुझे नहीं मालूम कि आपने कभी ध्यान किया है या नहीं, आप कभी एकाकी हुए हैं या नहीं। एकाकी होना यानी वह अवस्था जिसमें हर वस्तु से, हर व्यक्ति से, हर विचार और वासना से बिल्कुल दूर, आप केवल अपने संग होते हैं। किसी काल्पनिक दृश्य या स्वप्न जगत की शरण में जाकर नहीं, बल्कि इस सबसे एकदम दूर, ताकि आपके भीतर कुछ भी ऐसा न हो जिसे पहचाना जा सके, जिसे आप विचार और भाव से छू सकें। इन सबसे इतनी दूर कि इस पूर्ण एकांत में मौन ही फूल बन जाता है, मौन ही ज्योति बन जाता है। केवल ऐसे ध्यान में प्रेम का अस्तित्व होता है।

इसे प्रकट करने की चिंता मत कीजिए। यह स्वयं अपने को प्रकट करेगा। इसका उपयोग न करें। इसे क्रिया का रूप देने की कोशिश न करें। यह स्वयं क्रिया करेगा। और जब यह क्रिया करता है तो उस क्रिया में कोई पछतावा, कोई अंतर्विरोध नहीं होता। इसलिए एकाकी होकर ध्यान करें। खो जाएं, डूब जाएं। इतना याद रखने की भी कोशिश न करें कि आप कहां थे। अगर आप इसे याद रखने की कोशिश करते हैं, तो यह याद उस चीज की होगी जो मर चुकी है। और अगर आप इसकी स्मृति को पकड़े रहते हैं, तो आप कभी एकाकी नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप अनंत एकांत में, प्रेम के सौंदर्य में, निर्दोषता और नूतनता में डूबकर ध्यान करें। तब जो आनंद मिलेगा, वह स्थायी होगा। अगर आप इसे याद रखने की कोशिश करते हैं, तो उस स्थान में जाकर ध्यान करें जहां पहले नहीं गए थे।

(पुलक 'ध्यान' से साभार)

इस पत्र ज्ञाई. सं. 1/32/2/2 राजधानी एक्सप्रेस सूचित। विनियम अनुसारी के किन संपूर्ण व अतिरिक्त पृष्ठसंख्या मुद्रित, प्रतिलिपि। राजधानीकर्मी नीचे, अतिरिक्त पत्र कर्मचारी विनियोग के लिए संबंध करता हुए। 2 साधुपुरम् नया नगर, नई दिल्ली-110003 में प्रकाशित तथा **राकेश प्रकाश प्रिंटिंग प्रेस, भाग्यश्री 2.2, औद्योगिक क्षेत्र मालिकपुर** और नवीन प्रेस 1-ए, सेक्टर 58, इंडस्ट्रीज़ एरिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर राजकीय, नवीन, सीमाना के मुद्रित। फोन : 2502202 फैक्स: 2502207, पैकिंग कार्यालय : टाइम्स पैकिंग, नई, मुंबई-400021। विशेष प्रेस मुद्रण : 1 ए. औ. सीमि. नवीन में मुद्रण मुद्रण संस्थान से संबंधित। नियमों व शु. संपादक : नवभारत, ए.
संपादक (रिपोर्ट व्यवस्था) : अमरीश पांडे। इस पत्र में प्रकाशित समाचार सामग्री के चयन एवं संपादन हेतु पी.टी.आई. भाषा के उत्तरदायी समाचारों।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 297

महत्त्वपूर्ण खनिजों के लिए गंभीर प्रयास

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को राष्ट्रीय अति महत्त्वपूर्ण खनिज मिशन पर मुहर लगा दी। इस अभियान या मिशन पर केंद्र सरकार 16,300 करोड़ रुपये व्यय करेगी और सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य स्रोतों से भी 18,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा। यह मिशन भारत में नीति निर्धारण को एक नई दिशा देता दिख रहा है। 21वीं शताब्दी में आर्थिक वृद्धि के लिए आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त एवं सुरक्षित बनाए रखना काफी अहम है और इसे बखूबी समझते हुए सरकार ने यह अभियान शुरू किया है। लीथियम और मॉलिब्डिनम जैसे महत्त्वपूर्ण खनिज मध्यवर्ती सामान तैयार करने में इस्तेमाल होते हैं। इन खनिजों का इस्तेमाल बैटरी से लेकर सेमीकंडक्टर आदि बनाने में होता है। हाल के वर्षों में यह बात साफ हो गई है कि ऊर्जा से लेकर वाहन आदि सभी महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में गतिविधियां इन मध्यवर्ती वस्तुओं की उपलब्धता पर निर्भर हो गई हैं इसलिए महत्त्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित, सस्ती और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना काफी अहम हो गया है। सेमीकंडक्टर उपलब्ध नहीं होने से कोविड महामारी के दौरान भारत के वाहन क्षेत्र में उत्पादन पर गंभीर असर हुआ था। अब सरकार ने इन खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उठा ली है जिसका स्वागत किया जाना चाहिए।

इसमें कोई शक नहीं कि इस प्रयास के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी जुड़ा है। दुनिया में इन महत्त्वपूर्ण खनिजों के खनन एवं प्रसंस्करण के क्षेत्र में चीन का खासा दबदबा है। अफ्रीका और इंडोनेशिया सहित जिन देशों में इन खनिजों का खनन और प्रसंस्करण होता है वहां चीन की कंपनियों (जिनमें कई चीन की सरकार से सीधा ताल्लुक रखती हैं) की तूती बोलती है। सरकारें एवं उनके नीति निर्धारक यह बात अच्छी तरह समझते हैं कि आपूर्ति व्यवस्था एवं व्यापार का इस्तेमाल अब दुनिया में एक हथियार के रूप में होने लगा है। इसे देखते हुए सभी देशों के यह जरूरी हो गया है कि वह महत्त्वपूर्ण खनिजों की सूची अपने स्तर पर तैयार करें और उनकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रणनीति अपनाएं। भारत में ऐसे खनिजों का भंडार है परंतु इनकी खोज पूरी गंभीरता से नहीं हुई है और इनका इस्तेमाल होने में अभी कुछ समय और लग सकता है। इसके अलावा, इन खनिजों के भंडार जहां मिले हैं उन्हें देखते हुए देसी निवेशक इस क्षेत्र में निवेश करने में हिचकिचाहट दिखा सकते हैं। इसका कारण यह है कि इनमें कई भंडार राजनीतिक रूप से संवेदनशील और जैव-विविधता वाले क्षेत्रों में हैं। तकनीक और राजनीतिक इच्छाशक्ति का इस्तेमाल कर इन चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है। परंतु, यह भी सच है कि इसमें वक्त लगेगा और भारत के घरेलू संसाधनों को विकसित करने के लिए नीतियां तैयार करने की दिशा में भी पूरा प्रयास नहीं हुआ है। हाल में इन खनिजों की खोज से जुड़े लाइसेंस की नीलामी में निजी क्षेत्र ने खास दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। यह महज संयोग नहीं था।

विदेश में ऐसे संसाधनों में निवेश का भी महत्त्व इस लिहाज से बढ़ गया है। सरकार ने खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (काबिल) के नाम से एक नए सार्वजनिक उपक्रम का गठन किया है जिसका उद्देश्य विदेश में इन खनिज संसाधनों में निवेश को बढ़ावा देना है। फिलहाल इस कंपनी ने कोबाल्ट और लीथियम पर ही ध्यान केंद्रित रखा है और अब अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी करने की संभावनाएं तलाश रही है। मगर इस दिशा में काफी कुछ किया जाना बाकी है, इसलिए माना जा रहा है कि नए मिशन पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की मुहर लगने के बाद न केवल 'काबिल' के प्रयासों को बल भी मिलेगा बल्कि इस क्षेत्र में भारत के निजी क्षेत्र की भी रुचि बढ़ेगी। वैसे भी अंत में सारा दारोमदार निजी क्षेत्र की भागीदारी पर ही निर्भर है। इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले दशकों में इन खनिजों में भी लाभ कमाने के भरपूर अवसर होंगे। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2050 तक कुछ महत्त्वपूर्ण खनिजों के दाम 20 से 50 गुना तक बढ़ सकते हैं। अतीत में जब नए खनिज (कोयला से पेट्रोलियम तक) औद्योगिक एवं ऊर्जा खंडों की आपूर्ति व्यवस्था के लिए अहम हो गए थे तब बड़ी कंपनियां इनकी आपूर्ति सुचारु रूप से संभालने एवं इनकी बिक्री करने के लिए आगे आई थीं। इस कारोबार में उतरने के बाद उन्हें काफी आर्थिक लाभ भी हुए। यह सिलसिला 21वीं शताब्दी में महत्त्वपूर्ण खनिजों के साथ फिर दोहराया जाएगा। अगर इस कारोबार में भारत से भी कुछ कंपनियां उतरें तो यह भारत की आर्थिक वृद्धि एवं ऊर्जा सुरक्षा के हित में होगा। नए मिशन का कितना प्रभाव होगा इसका मूल्यांकन इस आधार पर किया जाएगा कि भारतीय कंपनियां कितने उत्साह के साथ इन प्रयासों में शामिल होती हैं।

अजय मोहंती

कैसे रफ्तार पकड़े भारत की विकास गाथा

वर्ष 2024 में भारत के प्रति बहुत ज्यादा उत्साह था। उस खोए उत्साह को वापस लाना आने वाले बजट का जिम्मा है। बता रहे हैं मिहिर शर्मा

पिछले कुछ हफ्तों और महीनों में ऐसा लगा मानो भारत की विकास गाथा ठहरने लगी है। इसकी गति फिर से लौटाना ही इस हफ्ते आने वाले केंद्रीय बजट का पहला लक्ष्य होना चाहिए। पिछले साल इसी समय भरोसा दिख रहा था कि भारत कई आर्थिक संकेतकों पर उम्मीदों से और दूसरों से बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन अब शायद ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए भारत की वृद्धि दर दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले अब भी अधिक है, लेकिन कोविड महामारी के बाद से यह शायद सबसे सुस्त दर होगी।

हालांकि वृद्धि के आधिकारिक आंकड़े उतने भरोसेमंद नहीं रह गए हैं, जितने पहले हुआ करते थे, लेकिन बाकी संकेतक भी सुस्ती की बात कह रहे हैं। बिजली के उत्पादन को ही लीजिए। इसमें होने वाली वृद्धि को आम तौर पर वास्तविक गतिविधियों का सबसे भरोसेमंद संकेतक माना जाता है, लेकिन 2024 में इसकी वृद्धि दर भी महामारी के बाद से सबसे धीमी रही। इस अखबार में प्रकाशित विश्लेषण के मुताबिक साल की दूसरी छमाही में खास तौर पर ज्यादा सुस्ती रही। वर्ष 2024 के अंत में औद्योगिक गतिविधि भी धीमी हो गई।

इस बीच उपभोक्ता मांग के बारे जो चिंता कुछ क्षेत्रों की कंपनियां कई साल से जता रही थीं वह पिछले कारोबारी नतीजों के बाद तेज हो गई। अक्टूबर और नवंबर के दरम्यान त्योहारों का दौर आम तौर पर ज्यादा बिक्री का समय रहता है, लेकिन इस बार रोजमर्रा का सामान बनाने वाली (एफएमसीजी) कंपनियों को इसमें निराशा ही हाथ आई। इस समाचार पत्र ने नीलसनआईक्यू के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि इस बार पिछले त्योहारी महीनों के मुकाबले केवल 3 फीसदी ज्यादा सामान बिका। कीमत के लिहाज से तो वृद्धि एक-दो फीसदी के बीच ही रही।

चिंता की बात यह है कि एफएमसीजी कंपनियां इसके लिए एक हद तक शहरी इलाकों खास तौर पर महानगरों को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। अभी यह नहीं पता है कि शहरों में ही मांग क्यों नहीं आ रही है। कुछ का कहना है कि रियल एस्टेट की कीमतें बढ़ने के कारण ऐसा हुआ है और दूसरे जानकार इसे वेतन में कम बढ़ोतरी, अधिक कीमत और ऊंची खाद्य महंगाई को इसकी असली वजह बता रहे हैं। कारण जो भी हो धीमी उपभोक्ता मांग वास्तव में अर्थव्यवस्था की वृद्धि की राह में बाधा है। भारत की विकास गाथा हमेशा ही देश के भीतर उपभोक्ताओं की मजबूत वृद्धि पर निर्भर रही है और ऐसा नहीं होने पर भारतीय बाजार विदेशी निवेश के लिए तरसेंगे तथा देसी कंपनियों को मांग से ज्यादा क्षमता खड़ी होने की चिंता सताने लगेगी। हमारा नकद अंतरण और कल्याणकारी योजनाओं का ढांचा भी खास तौर पर ग्रामीण मांग तथा कृषि आय बढ़ाने के लिहाज से तैयार किया गया है इसलिए यह बड़े शहरों की दिक्कतें दूर नहीं कर सकता।

पिछले कुछ महीनों में धीमी वृद्धि के साथ दो और समस्याएं भारत को सताने लगी हैं। पहली, शेयर बाजार का प्रदर्शन है और दूसरी रुपये की चाल। हो सकता है कि इन्हें बढ़ा-चढ़ाकर बताया जा रहा हो मगर इनकी पड़ताल तो बनती है।

बाजारों में दो पहलू नजर आते हैं। देसी संस्थाएं और म्युचुअल फंड लगातार रकम लगा रहे हैं मगर विदेशी निवेशक 2024 की आखिरी तिमाही से अभी तक 19 अरब डॉलर से ज्यादा के शेयर बेच चुके हैं। बड़े बाजारों की बात करें तो इस साल 26 जनवरी तक स्थानीय मुद्रा के लिहाज से भारत का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। इस दौरान उभरते बाजारों के सूचकांक कुल मिलाकर 0.2 फीसदी ही गिरे हैं। अगर निफ्टी 50 गिरावट के साथ ही इस महीने का अंत करता है तो 2001 के बाद से पहला मौका होगा जब यह लगातार चार महीनों तक गिरा है। फिर भी इसका आगे का प्राइस टु अर्निंग रेश्यो हिंद-प्रशांत क्षेत्र के दूसरे सूचकांकों से ज्यादा होगा।

शेयरों के बर्तमान भाव से जो उम्मीदें लगी हैं उनको देखते हुए आय में एकाएक गिरावट आने की बहुत गुंजाइश नहीं है। लेकिन डॉनल्ड ट्रंप की 'अमेरिका फर्स्ट' नीति के बीच बेहतर होने के आसार भी नहीं दिख रहे। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस ने पिछली ट्रंप सरकार के दौर में आयात शुल्क लगने के बाद भारत के अगले 12 महीने के ऑपरेटिंग मार्जिन में 120 आधार अंक गिरावट का अनुमान लगाया था। उसके मुकाबले चीन के लिए 128 आधार अंक गिरावट का अनुमान था और यूरोप में अनुमान जस का तस था।

विदेशी निवेशक रुपये पर भी नजर रखेंगे। डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये में आ रही गिरावट ज्यादा बड़ी समस्या नहीं होगी क्योंकि डॉलर अच्छा खासा चढ़ा है। रुपये की कीमत बढ़ जाए तो देश से होने वाले निर्यात के लिए समस्या होती है और कम कीमत वाला रुपया कोई दिक्कत पैदा नहीं करता। लेकिन यह सवाल जरूर है कि रुपया निवेशकों को आकर्षित करने वाली कीमत कब हासिल करेगा।

इसी से जुड़ा सवाल भारत में मुद्रास्फीति की दिशा का भी है। रुपया गिरने से आयात महंगा हो जाता है, जिसके कारण देश के भीतर ऊर्जा की कीमत बढ़ जाती है। जिन विश्लेषकों ने 2025 की शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 50 आधार अंक दर कटौती होने की बात कही थी अब रुपये की चाल देखने के बाद वे कटौती कई महीने आगे टलने का अनुमान लगा रहे हैं।

ऐसी चुनौतियों से निपटने वाला आम बजट बनाना बहुत दुष्कर काम लग सकता है। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय व्यवस्था के भीतर मौजूद कई फायदों का इस्तेमाल कर सकता है। उनमें से कई फायदे पिछले सालों में सतर्कता के साथ किए गए उसके ही कामों के नतीजे हैं।

सबसे पहले, भारत का कर संग्रह बढ़िया है। प्रत्यक्ष कर संग्रह पिछले साल में तेजी से बढ़ा है और अब अप्रत्यक्ष कर संग्रह से आगे निकल गया है। सरकार कर के अलावा राजस्व बढ़ाने पर भी सतर्कता बरतती रही है और अब शायद इस रवैये को बदलने का समय आ गया है। दूसरी ओर, राजस्व व्यय के मामले में सरकार की मुट्ठी साल दर साल कसती गई है। यदि महामारी के असर को छोड़ दें तो व्यय नियंत्रण में रहा है। महामारी के दौरान हुआ खर्च वैसे भी दूसरे देशों के मुकाबले भारत के राजकोष पर कम नजर आया।

सबसे बड़ी बात है कि पिछले कुछ साल में स्पष्टता और राजकोषीय जिम्मेदारी के मामले में भारत ने अपनी साख बनाई है। अब वह इस साख पर चोट आते नहीं देख सकता। इसलिए, मौजूदा समस्याओं के बीच तैयार हो रहे बजट का गणित भी एकदम स्पष्ट होना चाहिए। नीतियों के मामले में कुछ ऐसे आसान तरीके भी हैं जिन्हें अपनाकर लोगों की उम्मीद तुरंत लौटाई जा सकती है। इस लेखक ने जुलाई, 2024 में पिछले बजट के समय भी लिखा था कि बजट में तीन नीतिगत दिशाएं स्वागतयोग्य हैं। पहली, प्रत्यक्ष कर प्रणाली को साफ करना। दूसरी, शुल्कों के जरिये देसी उद्योगों को संरक्षण देना बंद करना और तीसरी, नीति निर्माण को दिशा देने वाला नीतिगत ढांचा तैयार करने का वादा। इन तीनों दिशाओं में ठोस कदम उठाए गए तब भी भारत गाथा को गति मिल सकती है।

गंभीर एवं अहम मुद्दों पर केंद्रित हो बजट

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए केंद्रीय बजट और भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति दो अहम घटनाएं होती हैं, जिन पर सबकी नजरें टिकी होती हैं। राजकोषीय और मौद्रिक दिशा तय करने वाली दोनों घटनाएं और उनके नतीजे अगले आठ दिन में हमारे सामने होंगे। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आम बजट 1 फरवरी को आएगा और मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिन की बैठक 7 फरवरी को खत्म होगी।

इतना तो तय है कि सरकार वित्त वर्ष 2025 में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.9 प्रतिशत पर समेटने का अपना लक्ष्य हासिल कर लेगी। घाटा कम होकर 4.8 प्रतिशत रह जाए तो भी किसी को हैरत नहीं होगी। इससे सरकार वित्त वर्ष 2026 में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5 प्रतिशत से नीचे लाने का लक्ष्य निर्धारित कर सकेगी। यह वास्तव में बड़ी उपलब्धि होगी मगर दिक्कत यह है कि देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार इस समय काफी सुस्त है। जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान जीडीपी में केवल 5.4 प्रतिशत वृद्धि हुई, जो उससे पहले की सात तिमाहियों का सबसे कम आंकड़ा था। कोविड महामारी से प्रभावित वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी के 9.2 प्रतिशत तक पहुंच चुका राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष में घटकर 4.8 प्रतिशत तक पहुंच तो सकता है मगर इसके पीछे अधिक कर संग्रह के साथ व्यय में खासी कटौती तथा रिजर्व बैंक से मिलने वाले ऊंचे लाभांश का हाथ है।

कोविड महामारी के समय आए बजट को छोड़ दें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए यह अब तक का सबसे कठिन बजट होगा। राजकोषीय घाटा तो कम हो जाएगा मगर पूंजीगत व्यय घटाकर और तमाम तरह के कर बढ़ाकर ऐसा करते रहना आगे मुमकिन नहीं दिख रहा। ध्यान रहे कि पिछले साल अप्रैल से नवंबर तक पूंजीगत व्यय 5.13 लाख करोड़ रुपये रहा, जो 11.11 लाख करोड़ रुपये के बजट अनुमान का केवल 46 प्रतिशत था। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि वित्त वर्ष 2025 में केंद्र का पूंजीगत व्यय पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 12 प्रतिशत कम है। राज्यों का कुल पूंजीगत व्यय भी वित्त वर्ष 2024 की तुलना में इस बार लगभग 5 प्रतिशत कम रहा है। उनका कहना है कि व्यय पिछले वित्त वर्ष के बराबर रहता तो सितंबर तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर कम से कम आधा प्रतिशत बढ़ जाती।

बैंकिंग साख

तमाल बंद्योपाध्याय

अब आर्थिक वृद्धि को रफ्तार देने का समय आ गया है वरना हालत बिगड़ जाएगी। उपभोक्ता मांग कमजोर पड़ गई है, विदेशी मुद्रा भंडार कम (27 सितंबर 2024 के 704.9 अरब डॉलर से घटकर 17 जनवरी 2025 को 623.98 अरब डॉलर) हो रहा है और रुपये में भी गिरावट देखी जा रही है। बैंकों से ऋण आवंटन में कमी भी सुस्ती का इशारा कर रही है। चालू वित्त वर्ष में 10 जनवरी तक बैंकों ने 8.3 प्रतिशत ज्यादा ऋण बांटा है, जो साल भर पहले के आंकड़े से बमुश्किल आधा है। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में ऋण वृद्धि भी 11.5 प्रतिशत रही है, जो 2023-24 में 20.3 प्रतिशत थी। 2022-23 में 42 अरब डॉलर तक पहुंचा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पिछले वित्त वर्ष में घटकर 26.5 अरब डॉलर रह गया था और चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बढ़कर 16.17 अरब डॉलर रहा। मगर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारतीय बाजार से रकम निकालते जा रहे हैं। अंत में अमेरिका के नए राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की चुनौती है और चीन की अर्थव्यवस्था औद्योगिक उत्पादन तथा निर्यात के दम पर वापस चढ़ रही है। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में यह साल भर पहले के मुकाबले 5.4 प्रतिशत बढ़ गई, जो उम्मीद से बहुत ज्यादा आंकड़ा है। इन सब हालात में आर्थिक वृद्धि को रफ्तार देनी है और अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाना है तो बड़े सुधारों की व्यवस्था करनी होगी। मगर यह होगा कैसे?

कहा जा रहा है कि बजट में व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर घटाया जाएगा। कुछ साल पहले कॉरपोरेट कर की दर पुरानी कंपनियों के लिए 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत और नई कंपनियों के लिए 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दी गई थी। मगर क्या इसके बाद भारतीय कंपनियों ने भारी निवेश किया और रोजगार तैयार किए? बिल्कुल नहीं। ज्यादातर कंपनियों ने कर घटने से बची रकम का इस्तेमाल शायद अपना कर्ज चुकाने में किया है। सरकार बार-बार उनसे निवेश और क्षमता निर्माण के लिए कह रही है मगर कंपनियां किसी न किसी वजह से इसके लिए तैयार नहीं हैं। सरकार के सामने उनका भरोसा जीतने और उन्हें इसके लिए तैयार करने की चुनौती है।

नरेंद्र मोदी सरकार के दौर में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवालिया प्रक्रिया और रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण जैसे बड़े सुधार किए गए हैं। अब सुधारों के दूसरे दौर का समय आ गया है। जीएसटी को दुरुस्त करना बेहद जरूरी है। अधिकारियों को नमकीन पॉपकॉर्न और कैरेमल वाले पॉपकॉर्न पर अलग-अलग कर लगाने के लिए माथापच्ची में वक्त बरबाद करने के बजाय इस काम को फौरन अंजाम देना चाहिए। आर्थिक वृद्धि लड़खड़ाई तो कर राजस्व पर भी चोट आएगी। पहले भी देखा गया है कि नॉमिनल जीडीपी में 10 प्रतिशत से कम वृद्धि हो तो कर संग्रह पर भी बिगड़ जाता है। करों के बारे में नजरिया भी सही करना होगा। कर का मौजूदा ढांचा बचत को वित्तीय तंत्र में नहीं पहुंचने दे रहा बल्कि उसे शेयर बाजार में भेज रहा है। रियल एस्टेट, सोना और शेयरों से लंबे समय में होने वाले पूंजीगत लाभ पर तो फायदा मिल रहा है मगर बॉन्ड में निवेश करने पर यह फायदा नहीं मिलता। फिर बॉन्ड बाजार कंपनियों को पूंजी मुहैया कराने का कारगर विकल्प कैसे बनेगा?

सरकार को डिजिटलीकरण, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और लाभांश के बाद अब विनिवेश पर ध्यान देना होगा। सरकार कुछ सार्वजनिक उपक्रमों में हिस्सेदारी बेचकर लाभ कमाने का सुनहरा अवसर खो चुकी है। उदाहरण के लिए मई 2020 और फरवरी 2024 के बीच इंडियन ओवरसीज बैंक का शेयर 10 गुना (7.25 रुपये से बढ़कर 71 रुपये प्रति शेयर) चढ़ गया था। उसका शेयर 71 रुपये के भाव पर अपने बुक वैल्यू का पांच गुना हो गया था और शायद उस समय वह दुनिया का सबसे महंगा बैंक था। मगर क्या सरकार उसी समय हिस्सेदारी बेचकर मुनाफा कमा पाई? नहीं। दूसरे क्षेत्रों में भी सरकार ऐसे कई मौके लपकने से चूक गई।

वित्त मंत्री ने 2021-22 में आईडीबीआई बैंक के साथ दो सरकारी बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण का प्रस्ताव रखा था। मगर मामला कहीं अटक गया है। हाल में खबरें आईं कि आईडीबीआई बैंक के लिए बोली मंगाई जा सकती हैं मगर निजीकरण की प्रक्रिया वित्त वर्ष 2026 में पूरी होगी। इसे पंचवर्षीय योजना न कहें तो क्या कहें!

अगर सरकार वृद्धि दर बढ़ाना चाहती है तो उसे पूंजीगत खर्च बढ़ाना चाहिए ताकि लोगों की जेब में पैसे आएं। पॉपकॉर्न तो पॉपकॉर्न ही रहेगा। क्या फर्क पड़ता है कि नमकीन है या कैरेमल वाला? हमें उसके बजाय असली मुद्दों पर ध्यान देना होगा।

(लेखक जन स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड में वरिष्ठ सलाहकार हैं)

आपका पक्ष

विज्ञान के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ता भारत

भारत विज्ञान के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा। हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा से 100वें मिशन में जीएसएलवी 15 के जरिये एनवीएस सैटेलाइट को कामयाबी के साथ लॉन्च किया। इस सफलता ने दुनिया को बता दिया कि भारत विज्ञान के क्षेत्र में भी काफी विकास कर रहा है। भारत के वैज्ञानिक भी अमेरिका, चीन आदि देशों से कम नहीं हैं। 23 अगस्त, 2023 को चंद्रयान 3 को इसरो ने चंद्रमा पर उतारकर देश का मान बढ़ाया था। भारत की महिला वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई जिससे साबित हुआ कि देश की बेटियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। इससे पहले भारतीय मूल की कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में कदम रख भारत का भी मान बढ़ाया था। कल्पना चावला अंतरिक्ष जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। इसके बाद 2 सितंबर, 2023 का दिन भी हमारे देश के लिए ऐतिहासिक दिन बन गया। इस दिन इसरो ने पहले सूर्ययान आदित्य-एल1 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था और यह भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण राकेट पीएसएलवी-सी57 के साथ अंतरिक्ष गया था। उम्मीद है कि यह अभियान सफल होगा और इससे ओजोन परत को समझने में ज्यादा आसानी होगी। इसरो ने विश्व का दूसरा और देश का पहला ऐसा सैटेलाइट लॉन्च किया है जो अंतरिक्ष में रेडिएशन, आकाशगंगा, प्लस्मर और ब्लैक हॉल का अध्ययन कर इसके बारे जानकारी जुटाएगा। अगर सरकार विज्ञान की पढ़ाई को दुरुस्त करने के लिए गंभीरता दिखाए तो भारत विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया के सभी देशों को पीछे छोड़ देगा। सरकार को विज्ञान के क्षेत्र में कुछ कर दिखाने की चाहत रखने वालों की हर संभव मदद करनी चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

इसरो ने श्रीहरिकोटा से 100वें मिशन में जीएसएलवी 15 के जरिये एनवीएस सैटेलाइट को कामयाबी के साथ लॉन्च किया

धूम्रपान के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा

महज एक सिगरेट पीने वालों के जीवन के 20 मिनट कम हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से जुड़े वैज्ञानिकों ने एक शोध में यह साबित किया है कि धूम्रपान अच्छे स्वास्थ्य वालों के लिए एक गंभीर खतरा है। हालांकि यह एक ऐसा खतरा है कि इसे टाला भी जा सकता है लेकिन इसके बावजूद हर साल दुनिया में लाखों लोगों की जान धूम्रपान की वजह से जा रही है। वैश्विक स्तर पर देखें तो तंबाकू हर 4 सेकंड में एक जिंदगी को लील रहा है। इसका मतलब यही है कि हर साल होने वाली 87 लाख मौतों के लिए कहीं न कहीं तंबाकू जिम्मेदार है। इनमें से 13 लाख लोग वे हैं जो दूसरों के द्वारा किए धूम्रपान के कारण शिकार बन जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में 130 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। इनमें से 80 फीसदी निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रह रहे हैं। एक दूसरे अध्ययन में यह भी पता चला है कि धूम्रपान न करने वालों की तुलना में इसकी लत के शिकार लोगों की याददाश्त सोचने, समझने, बोलने, सीखने और निर्णय लेने जैसे दिमागी कौशल में 85 फीसदी से अधिक की गिरावट का सामना करना पड़ सकता है।

एमएम राजावत, शाजापुर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और कई राजनेताओं ने गुरुवार को महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि पर राजघाट में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

चिंतन

यह बजट सत्र उपयोगी रहे हंगामे में नष्ट न हो वक्त

आज 31 जनवरी से बजट सत्र का आगाज हो रहा है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ मोदी 3.0 सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण बजट सत्र शुरू होगा। पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव से पहले फरवरी में अंतरिम बजट पेश हुआ था और जुलाई में पूर्ण बजट। जून में सरकार गठन के तुरंत बाद बजट आया था, तो इसमें वो पैनापन नहीं था, जिसकी जरूरत थी। इस लिहाज से कल एक फरवरी को पेश होने वाला बजट सरकार की दशा व दिशा तय करेगा। अभी सरकार के पास चार वर्ष हैं, जिसमें उसके पास व्यापक आर्थिक सुधार को आगे बढ़ाने का अवसर है। बजट सत्र से ठीक एक दिन पहले हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने अपने एजेंडे व मंशा सरकार के सामने रखे हैं, जिसमें महाकुंभ में भगदड़, अतिविशिष्ट को अधिक तवज्जो, किसान आंदोलन व किसानों की समस्या, महंगाई, बेरोजगारी आदि विषयों पर चर्चा की मांग है। इस बैठक में सरकार ने विपक्ष से कहा है कि बजट सत्र के एजेंडे पर कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) निर्णय करेगी। साफ है कि सरकार व विपक्ष के रुख में सामंजस्य की बात नहीं है, इससे बजट सत्र में हंगामा के आसार बन रहे हैं। जैसा कि अब तक करीब दो दशक से संसद सत्र के दौरान हंगामे के चलते सदन का कीमती वक्त जाया होता रहा है, सत्र में विधेयक पास कराना मुश्किल होता गया है, हंगामेदार सत्र के कारण ही विधेयक पर ठीक ढंग से चर्चा तक नहीं हो पाती है। कायदे से सर्वदलीय बैठक सत्र से दो दिन पहले हो, उसमें सभी बिंदुओं पर चर्चा के बाद कार्य एजेंडा तय हो जाए, फिर उसी अनुरूप सदन में चर्चा हो। सरकार को भी सभी प्रस्तावित विधेयकों और कामकाज के बारे में विपक्ष के सामने सभी पहलुओं को रखना चाहिए। सरकार व विपक्ष अगर सामंजस्य के साथ चलेंगे तो कोई भी संसद सत्र सुचारू रूप से चल सकेगा। संसद सत्र को राजनीति का अखाड़ा बनने से रोकना सरकार का ही दायित्व है, जिसमें विपक्ष को विश्वास में लेना जरूरी है। अगर देश बदल रहा है, अमृतकाल चल रहा है, नए भारत की बात हो रही है तो राजनीति भी बदलनी चाहिए। संसद राजनीति की शाला नहीं होनी चाहिए। 21वीं सदी के दो दशक बीतने के बाद भी संसद विधायी कार्यों व सार्थक चर्चा से लबरेज होनी चाहिए। विकसित भारत के लक्ष्य में संसद की गतिशीलता, सार्थकता और राजनीतिक व संसदीय अनुशासन भी होने चाहिए। न तो विपक्ष की मांग को अनसुना किया जा सकता है और न ही सरकार कुछ भी थोप सकती है। संसद की कार्य उत्पादकता बढ़ाने की आवश्यकता है। भारतीय संसद की कार्यप्रणाली दुनिया के लिए नजीर बननी चाहिए। आमतौर पर सर्वदलीय बैठक में बनी सहमति संसद सत्र के पहले दिन से ही टूट जाती है, इसे रोकने की जरूरत है। लोकसभा चुनाव के बाद सांसदों को विधायी कार्य के बारे में प्रॉपर अनिवार्य प्रशिक्षण होना चाहिए, सांसदों के बात रखने का तरीका तय होना चाहिए। हालांकि यह सब नियम है, इसके बावजूद व्यवहार में संसद की गरिमा का पालन नहीं होता है। सांसद हंगामे को ही अपना दायित्व समझ लेते हैं। सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक राजनीतिक दलों को सरकार के विधायी एजेंडे के बारे में सूचित करने और विपक्षी दलों की मांगों के बारे में जानने का अवसर होता है। दो चरणों में चलने वाले यह बजट सत्र देश के लिए उपयोगी होना चाहिए, बजट व अन्य सभी विधेयकों पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, चर्चा हांगामे की भेंट नहीं चढ़नी चाहिए। हंगामा खड़ा करना विपक्ष का मकसद नहीं होना चाहिए।

बैंकिंग सुधार

सतीश सिंह

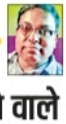

बैंकों को सशक्त बनाने वाले प्रावधान की बजट में उम्मीद

वर्ष 2025 के लिए केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाने वाला है, जिसमें आगामी वित्त वर्ष के लिए वैसे प्रावधान किए जाएंगे, जिनकी मदद से विकास को गति दी जा सके। साथ ही वंचित तबकों और किसानों की बेहतरी के लिए समुचित उपाय किया जा सके। देश के विकास को सुनिश्चित करने में विनिर्माण, निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रेल आदि क्षेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन बैंकों की भूमिका इन सभी क्षेत्रों से ज्यादा महत्वपूर्ण रही है और ये इन सभी क्षेत्रों के विकास की दशा और दिशा को तय कर रहे हैं। बजट को उद्देश्यपरक और कारगर बनाने के लिए सभी महत्वपूर्ण हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं, जिसमें बैंक भी शामिल हैं। आजादी के बाद से ही देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में बैंक अहम भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि सरकार बैंकों को सशक्त बनाने वाले प्रावधान बजट में करे। जब बैंक मजबूत होंगे, तभी ये देश को भी आर्थिक रूप से सबल बना सकेंगे। आज बैंकों के समक्ष सबसे बड़ी समस्या सस्ती पूंजी की कमी की है। मोटे तौर पर बैंक का काम ग्राहकों से जमा लेना और उसी जमा को जरूरतमंदों और कारोबारियों के बीच ऋण के रूप में वितरित करना है। बैंक जमा पर कम ब्याज देते हैं और ऋण पर ज्यादा ब्याज लेते हैं। ब्याज दरों में अंतर से ही बैंक मुनाफा कमाता है। मौजूदा समय में बचत, आवृत्ति और सावधि जमा पर अर्जित ब्याज पर सरकार टैक्स वसूल रही है। बैंकों ने भी अपनी कमाई बढ़ाने के लिए जमा को म्यूच्यूअल फंड और बीमा में निवेश किया है। इधर, कुछ सालों से अर्थव्यवस्था के मजबूत रहने से शेयर बाजार का सेंसेक्स लगातार ऊपर जा रहा है और लोगों को शेयर बाजार व म्यूच्यूअल फंड में निवेश पर बेहतर प्रतिफल मिल रहा है। ऐसी स्थिति में घरेलू निवेशक बैंक में निवेश करने से परहेज कर रहे हैं। जमा की किल्लत की वजह से बैंकों को ऋण देने के लिए बाजार से अधिक ब्याज पर पूंजी उठानी पड़ रही है और बाजार में तरलता का संकट पैदा होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। उधारी के उठाव में कमी आने से आर्थिक गतिविधियों में कमी दर्ज की गई है और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में उल्लेखनीय कमी आई है। लिहाजा,व्यक्तिगत बचत को प्रोत्साहित करने के लिए बचत, आवृत्ति एवं सावधि जमा पर अर्जित ब्याज को करमुक्त बनाने की जरूरत है। साथ ही,आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत सभी बैंक जमा पर कर की छूट भी देनी चाहिए। जमा को प्रोत्साहित करने के लिए गारंटीकृत रिटर्न के साथ सरकार द्वारा समर्थित बचत योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू करना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण अभी भी शेयर बाजार और म्यूच्यूअल फंड में निवेश करने से बचते हैं। इस क्रम में बचत को प्रोत्साहित करने के लिए महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और किसानों द्वारा जमा राशि पर कर मुक्त ब्याज देने की व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार को आकर्षक दीर्घ-अवधि सरकारी बचत बॉन्ड बैंकों के माध्यम से बेचना चाहिए, ताकि बैंक की जमा में वृद्धि हो और सार्वजनिक क्षेत्र की उधारी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिल सके। सरकार को ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने के लिए पुख्ता कानून बनाने की जरूरत है, क्योंकि साइबर अपराध की आवृत्ति बढ़ने से भी आमजन बैंकों में जमा रखने से परहेज कर रहे हैं। बैंक के विफल होने की स्थिति में जमा बीमा दावों की प्रक्रिया को और सरल बनाना चाहिए। इससे भी जमा को बढ़ावा मिल सकता है। बैंकों के गैर निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) में विगत वर्षों में उल्लेखनीय कमी आई है। फिर भी, सर्फेसी, बैंक अदालत आदि वसूली तंत्रों को और भी मजबूत बनाने की जरूरत है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद बैंक कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभों पर टीडीएस जनवरी 2025 से शुरू की जाने वाली है। कुछ बैंकों ने फ्रीलाइज इस भार को खुद वहन किया है तो कुछ ने नहीं। सरकार द्वारा मामले में हस्तक्षेप करने की जरूरत है। हाल के कुछ वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र के प्रदर्शन में बेहतरी आई है और एनपीए में भी उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। बैंकिंग सुविधाओं के डिजिटल हो जाने के बाद, ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटनाओं में बहुत तेजी आई है, जिससे निवेशकों का बैंकों पर से भरोसा कम हुआ है। बैंकों के वसूली तंत्र की कमजोरी के कारण भी एनपीए में अपेक्षित कमी नहीं आई है। इधर, बैंक कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभों पर टीडीएस की कटौती से उनके मनोबल में कमी दर्ज की गई है, जिससे बैंक के प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना बढ़ी है। अस्तु, इन समस्याओं का समाधान करने वाले प्रावधान बजट में करने की जरूरत है।

(लेखक एजीएआई में एडवीएस हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

जन अपेक्षाओं पर खरा उतरे शहरी सरकार

विचार

डॉ. संजय शुक्ला

छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों तथा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। दलीय आधार पर 10 नगर पालिक निगमों, 49 नगर पालिका परिषदों और 114 नगर पंचायतों में चुनाव हो रहे हैं। राज्य सरकार ने इन निकायों के महापौर एवं अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा कराने का फैसला किया है जो लोकतान्त्रिक व्यवस्था के लिए सार्थक पहल है। " वन नेशन,वन इलेक्शन" के गहमागहमी के बीच छत्तीसगढ़ पूरे देश में पहला राज्य है जहां शहरों से लेकर गांवों की सरकार चुनने के लिए चुनाव हो रहे हैं। दलीय आधार पर होने वाले नगरीय निकायों के चुनाव जहां "ईवीएम" से होंगे वहीं गैर दलीय आधार पर हो रहे पंचायत चुनाव "बैलेट पेपर" के जरिए होगा। भले ही पंचायत चुनाव गैर दलीय आधार पर हो रहे हैं लेकिन इन चुनावों में भी राजनीतिक दलों की पूरा दखल होता है। महत्वपूर्ण यह कि राज्य में हो रहे ये चुनाव " हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे" ध्येय वाक्य वाले साल भर पुराने विष्णु देव सरकार के लिए "लिटमस टेस्ट" है वहीं विपक्षी दल कांग्रेस के लिए " करो या मरो " की परीक्षा है। यह चुनाव उन लाखों शहरी और ग्रामीण मतदाताओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे इस चुनाव के जरिए अपने शहरों और गांवों का भाग्य निर्यंता चुनते हैं जिनसे उनके दैनंदिन कामों के लिए वास्ता पड़ता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण और शहरों व गांवों के विकास में आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ही यह चुनाव कराए जाते हैं। मतदाताओं की भी जवाबदेही है कि वे इस चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें तथा प्रतिनिधि चुनाव में धर्म, जाति और क्षेत्रवाद की जगह योग्यता को तरजीह दें।

गौरतलब है कि स्थानीय निकायों के जिम्मे केंद्र और राज्य सरकारों के योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ ही शहरों विकास, साफ - सफाई सहित अन्य सामुदायिक एवं जन कल्याणकारी कार्यों का संपादन करना है। इसके अलावा आमजनता से जुड़े रोजमर्रा के काम जैसे निवास प्रमाणपत्र, बच्चों के स्कूली दाखिले और छात्रवृत्ति के लिए प्रमाण पत्र, राशनकार्ड, बीपीएल कार्ड, मजदूर कार्ड, घरों में नल कनेक्शन सहित वार्डों में साफ-सफाई, पेयजल, बिजली व्यवस्था सहित अन्य अनेक सामुदायिक कार्य इन चुनावों के जरिए चुने गए पार्षदों जिम्मे ही होता है। बीते दशकों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा शहरी विकास से संबंधित अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन सीधे नगरीय निकायों के माध्यम से किया जा रहा है बावजूद ये संस्थाएं जन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रही है। इसके पीछे मुख्य वजह निर्वाचित प्रतिनिधियों और वहां पदस्थ नौकरशाहों के बीच आपसी टकराव, राजनीतिक हस्तक्षेप और गतिरोध, फिजूलखर्ची ,भ्रष्टाचार व भाई - भतीजावाद है। अमूमन हर चुनाव में सभी राजनीतिक दल और उम्मीदवार मतदाताओं के सामने शहर को साफ - सुथरा और सुंदर, प्रदूषण, धूल और मच्छर मुक्त, चौबीस घंटे पेयजल, मजबूत सड़क, अतिक्रमण और अवारा मवेशियों से छुटकारा दिलाने जैसे वादे करते हैं लेकिन चुनाव के बाद स्थिति ज्यों कि त्यों ही रहती है।

छत्तीसगढ़ के लिहाज से देखें तो राज्य के राजधानी से लेकर सभी प्रमुख शहर वायु और जल प्रदूषण, गंदगी, धूल, मच्छर, खस्ताहाल सड़कों, बरसात में जलभराव, बजबजाती नालियों, चौक - चौराहों पर अवारा मवेशियों के जमावड़े, अव्यवस्थित यातायात, लचर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम,अवैध कब्जों, बदहाल सफाई, ड्रेनेज और पेयजल व्यवस्था, बंद स्ट्रीट लाइट, अवैध झुग्गियों और गुमटियों जैसे समस्याओं से जूझ रहे हैं। राज्य के अधिकांश शहरों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की पुख्ता व्यवस्था अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पायी है फलस्वरूप कचरों का पहाड़ जनस्वास्थ्य के साथ पर्यावरण के लिए भी नुकसानदेह साबित हो रहा है। शहरों के प्राकृतिक जल स्रोत नदी - तालाब और उद्यान सौंदर्यीकरण के नाम पर व्यवसायिक गतिविधियों के भेंट चढ़ रहे हैं फलस्वरूप जलस्रोतों और उद्यानों का इकोसिस्टम भी प्रभावित हो रहा है। अनियोजित विकास और जनसंख्या के बढ़ते दबाव की वजह से जहां शहरों की हरियाली खत्म हो रही है वहीं कांक्रीट के बढ़ते जंगल की वजह से शहरों का तापमान लगातार बढ़ रहा है तथा भूजल का स्तर तेजी से घट रहा है। राज्य के विभिन्न शहरों के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित कोल आधारित उद्योगों के थूंए तथा औद्योगिक अपशिष्टों तथा झुग्गी बस्तियों में लकड़ी और कोयले की सिगड़ियां जलाने और गंदगी एवं निर्माण कार्यों से उड़ने धूल का दुष्प्रभाव पर्यावरण और लोगों के सेहत पर भी परिलक्षित हो रहा है।

शहर सदैव उच्च शिक्षा के लिए जाने जाते रहे हैं लेकिन शिक्षण संस्थानों के जमीनों पर तन रहे कामर्शियल काम्प्लेक्स तथा अन्य व्यवसायिक गतिविधियों के कारण स्कूलों और कॉलेजों के शैक्षणिक वातावरण पर बुरा असर पड़ रहा है वहीं इन संस्थानों में खेलकूद का मैदान भी नहीं बचा है। किसी भी शहर की पहचान उसकी सांस्कृतिक रचनाधर्मिता से भी होती है लेकिन छत्तीसगढ़ के शहर इस पहचान से अछूते हैं। राज्य के शहरों में कला, पेंटिंग, रंगमंच, साहित्य, संस्कृति से जुड़े लोगों के लिए कोई ऐसा सर्व सुविधायुक्त आधुनिक थियेटर या कलाविथिका नहीं है जहां इन विधाओं का माकूल प्रदर्शन संभव हो सके। गौरतलब है कि साल 2015 में राजधानी रायपुर दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में पांचवें पायदान पर शामिल हो चुका है वहीं अभी भी देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित 15 शहरों में रायपुर, रायगढ़, कोरबा और भिलाई - दुर्ग शामिल है। कोरबा, रायगढ़, रायपुर और भिलाई - दुर्ग जैसे औद्योगिक शहरों के सफेद राखड़, काली धूल और दमघोंटू हवा ने यहां के वाशिंदों का जीना दुश्वार कर दिया है।

देश के 100 शहरों की शक्ल- सूरत और सीरत संवारने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने साल 2015 में देश में " स्मार्ट सिटी मिशन" का आगाज किया था। इस मिशन के तहत शहरी जनजीवन के गुणवत्ता में सुधार हेतु शहरों के अधोभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण, सुरक्षा और संचार प्रौद्योगिकी का विकास, गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य और पेयजल व्यवस्था की सुनिश्चितता और जनभागीदारी से सरकारी कामकाज में सुधार जैसे उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। छत्तीसगढ़ के तीन शहरों रायपुर, नवा रायपुर और बिलासपुर को स्मार्ट सिटी मिशन के लिए चुना गया था लेकिन ये शहर अभी भी स्मार्ट सिटी के लक्ष्य और मानकों से कोसों दूर है। रायपुर और बिलासपुर की पहचान गड्ढे और धूल युक्त शहर की बन चुकी है वहीं नवा रायपुर के सड़कें और चौराहे अवारा मवेशियों के "मौठान" बने हुए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यायधानी बिलासपुर में भूमिगत नाली निर्माण तथा रायपुर में अंडर ग्राउंड केबल डालने के नाम पर होने वाले सड़क खुदाई की वजह से इन शहरों को " खोदापुर" नाम देकर प्रशासन को ट्रोल भी किया जाता रहा है। बहरहाल सरकारी तंत्र की लालफीताशाही के चलते मोदी सरकार की शहरों को स्मार्ट बनाने की महत्वाकांक्षी योजना कछुआ चाल से चल रही है। इस योजना में भ्रष्टाचार, फिजूलखर्ची और गुणवत्ताहीन निर्माण कार्यों की खबरें जनता के अरमानों पर लगातार पानी फेर रही है। शहरों की स्थिति देखने के बाद रहवासी यही उलाहना दे रहे हैं कि गोया स्मार्ट सिटी की बात छोड़िए इन्हें रहने लायक ही बना दीजिए।

गौरतलब है कि किसी भी प्रदेश के मजबूत अर्थव्यवस्था का प्रतिबिंब उसका चमचमाता शहर हो होता है, शहर जहां तरक्की, रचनात्मकता और नवीनता का केंद्र होता है वहीं यह अर्थव्यवस्था में प्रगति और रोजगार का जनक भी होता है।छत्तीसगढ़ जैसे विकासशील राज्य में शहरों की दुर्दशा जहां प्रदेश के आर्थिक विकास में बाधक हैं वहीं इसका प्रभाव जन-स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। दूसरी ओर शहरों की दयनीय स्थिति का पूरा ठीकरा नगरीय निकाय प्रशासन पर ही फोड़ना न्यायसंगत नहीं होगा बल्कि इसके लिए आम नागरिक भी जवाबदेह हैं जो अपने नागरिक कर्तव्यों के प्रति सदैव उदासीन नजर आते हैं। शहरों के लचर ड्रेनेज सिस्टम और पर्यावरण प्रदूषण के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार सिंगल यूज प्लास्टिक जिसमें पॉलीथीन कैरी बैग, डिस्पोजेबल गिलास, कटोरी, स्ट्रा आदि सामाग्रियां हैं। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित किया गया है बावजूद आम नागरिक इसका उपयोग धड़ल्ले से कर रहे है फलस्वरूप इसका निर्माण, विक्रय और वितरण पर प्रभावी अंकुश नहीं लग पा रहा है। नागरिकों को वाहनों के प्रदूषण जांच, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अधिकाधिक उपयोग, सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग बंद करने, निर्माण कार्यों के दौरान ग्रीन नेट का उपयोग करने, अनियमित निर्माण, दुकानों के सामने अवैध पार्किंग व अवैध कब्जों की प्रवृत्ति के अलावा मवेशियों को अवारा छोड़ने, सार्वजनिक स्थलों में कचरा फेंकने जैसे गतिविधियों पर आत्म अनुशासन प्रदर्शित करने की जरूरत है ताकि हम अपने शहर पर गर्व कर सकें। अलबत्ता हालिया चुनाव के सार्थकता के मद्देनजर प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों से भी अपेक्षा है कि वे अपने वादों और चुनाव घोषणा पत्रों के क्रियान्वयन के प्रति पूरी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करें ताकि शहरी सरकार जन अपेक्षाओं पर खरा उतर सके।

(ये लेखक के अपने विचार हैं।)

हर दिन सुखद और आनंददायक

संकलित

दर्शन

आनंद प्रत्येक व्यक्ति का सच्चा लक्ष्य है। मनुष्य आनंदकी लालसा करता है और इसे अनेक रीतियों से खोजने का प्रयास करता है। वह अच्छा भोजन करने में, मैत्रीपूर्ण सामाजिक समूहों में, स्नेही परिवार में, एक भारी-भरकम वेतन में, शानदार पर्यटन में, तथा सबसे बढ़िया घरों एवं कारों में आनंद प्राप्त करता है। फिर भी, अपनी आशा के अनुरूप प्राप्त कर लेने के उपरांत भी, उसकी प्रसन्नता स्थायी नहीं रहती है। जीवन के उतार-चढ़ाव उसे बार-बार झकझोरते रहते हैं। चाहे वह खाना हो, सोना हो, खेलना हो, प्रार्थना करना हो अथवा कार्य करना। अपनी सभी गतिविधियों को संतुलित करने से आपके जीवन में जो संतुलन आएगा, वह आपके जीवन के प्रत्येक दिन की पूर्णता से जीने में सहायता करेगा। अपने जुनून को अपना पूर्णकालिक व्यवसाय बनाएं। आप प्रत्येक दिन संतुष्टि का अनुभव करेंगे तथा सदैव अपनी उत्कृष्टता की पराकाष्ठा प्राप्त करेंगे। आप अपनी आयु के आधार पर अपना परोपकार का चार्ट बना सकते हैं। परोपकार का आपकी वित्तीय व्यवस्था में एक अंश अवश्य होना चाहिए, क्योंकि केवल इसका समावेश ही आपको अद्वितीय संतोष की अनुभूति प्रदान कर सकता है। सदैव स्मरण रखें कि बाह्य स्थितियां एवं परिस्थितियां सदैव अनुकूल नहीं रह सकती हैं। ध्यान के माध्यम से आत्म-अवलोकन करें तथा अपनी आंतरिक गहन शांति एवं नीरवता का सागर खोजें। विश्वास करें कि सब कुछ दिव्य योजना के अनुसार नियंत्रण में है। *- सद्गुरु श्रीमधुसूदन साई*

देने वाला तो कोई और ही

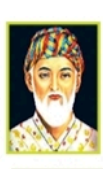

संकलित

प्रेरणा

रहीम खान खाना का नियम था, कि वे प्रतिदिन गरीब याचकों को दान देते थे और देते समय वह कभी अपनी नजर दान लेने वाले पर नहीं डालते थे। वह नजर नीचे करके रूपए-पैसों के ढेर से मुट्ठी भरकर गरीबों को देते थे। अपने नियम अनुसार एक दिन जब वह गरीबों को दान दे रहे थे तो उनसे किसी ने पूछा, 'जैसे-जैसे आपका हाथ दान देने के लिए उठ रहा है, आपके नैन नीचे क्यों झुकते जा रहे हैं? तुम ऐसे दान क्यों देते हो? ऐसा तुमने कहां से सीखा? ऐसी देनी देन जू किन सीखे हो सैन। ज्यों-ज्यों कर ऊंचे करो, त्यों-त्यों नीचे नैन। इस पर रहीम ने दोहे के रूप में इसका उत्तर दिया, 'देनहार कोउ और है, भेजत सो दिन रैन। लोग भरम हम पै धरैं, याते नीचे नैन' देने वाला तो कोई और ही है, जो दिन-रात दे रहा है, लेकिन लोग समझते हैं कि मैं दे रहा हूं, इसलिये मेरी आंखें अनायास ही शर्म से झुक जाती हैं। मनुष्य कहां किसी को कुछ दे सकता है, देने वाला तो दूसरा ही है, जो दिन-रात भेजता रहता है, इन हाथों से दिलवाने के लिए। लोगों को व्यर्थ ही भ्रम हो गया है कि रहीम दान देता है। मेरे नेत्र इसलिए नीचे को झुके रहते हैं कि मांगने वाले को यह भान न हो कि उसे कौन दे रहा है, और दान लेकर उसे दीनता का एहसास न हो। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पहले प्रश्न वाला दोहा गोस्वामी तुलसीदास का है, वहीं कुछ लोग इसे कवि गंग का मानते हैं। लेकिन प्रश्न चाहे किसी ने भी किया हो, महत्वपूर्ण बात तो रहीम के उत्तर में निहित है, दान देते समय या किसी की मदद करते समय हमारे मन में अभिमान नहीं बल्कि नम्रता का भाव होना चाहिए।

अंतर्मन

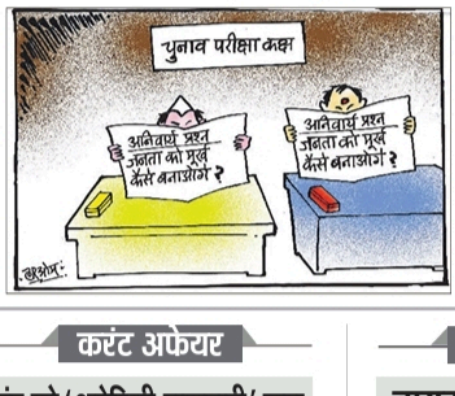

आज की पाती

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' में चुनौतियां

देश में एक राष्ट्र, एक चुनाव की प्रक्रिया के लिए समय-समय पर आवाज उठाई जाती है। इसके लिए केंद्र सरकार ने एक कमेटी का गठन भी किया है। इसका नेतृत्व पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे है। कमेटी ने आम लोगों से विभिन्न प्लेटफार्म पर एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए राय देने के लिए कहा है ताकि इस प्रक्रिया के लिए आमजन के मन की बात को भी समझा जाए। एक साथ चुनाव ऐसे लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा जो हर चुनाव में केंद्र और राज्य सरकार की अच्छी-बुरी नीतियों का विश्लेषण कर अपने कीमती वोट का प्रयोग करते हैं। क्या इससे भ्रष्ट और आमजन को अनदेखा करने वाली की नीयत बदलेगी?

-विजय कुमार, रायपुर

टेंड

'बापू' को शत-शत नमन!

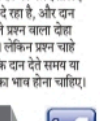

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें शत-शत नमन! श्रद्धेय 'बापू' की शिक्षाएं और उनका त्यागमय जीवन विश्व शांति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आइए, उनके दिखाए सत्य, अहिंसा व सादगी के मार्ग पर चलकर हम सभी 'नए भारत विकसित भारत' के निर्माण हेतु संकल्पित हों।

-योगी आदित्यनाथ, सीएम उप्र

सद्प्रयासों पर मिट्टी

ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो लोग महाकुंभ में पानी श्रद्धालुओं के लिए भोजन-पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, उनके सद्प्रयासों के ऊपर राजनीतिक विद्वेषता मिट्टी डाल दी जा रही है।

-अखिलेश यादव, सपा सांसद

मानव बुद्धि महत्वपूर्ण

सुदेश अग्रवाली ने बहुत अच्छा कहा कि उपाध्यक्षता, सचिवता और कोषाध्यक्ष ने एआई एक महत्वपूर्ण तत्व हो सकता है। लेकिन अंततः यह मानव बुद्धि ही है जो प्रगति, विकास और व्यवहार का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण होगी।

-किरण मजूमदार-शॉ, उद्यमी

स्वास्थ्य ही सब कुछ

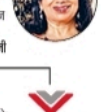

सुपर प्रधानमंत्री ने इतने इतना उपयुक्त तरीके से रखा है कि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। कुछ भी क्वॉलाइट वाले पर वालों तो सही। नियमित व्यायाम आपके जीवन को बदल देगा। इस पर विश्वास करें और आगे बढ़ें।

-अक्षय कुमार, अभिनेता

करंट अफेयर

ट्रंप को 'अमेरिकी राष्ट्रवादी' कहा भारत-अमेरिका संबंध होंगे मजबूत

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत-अमेरिका के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों का उल्लेख करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक 'अमेरिकी राष्ट्रवादी' बताया। दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में एक संवाद सत्र में जयशंकर ने वैश्विक कूटनीति की उभरती प्रकृति और इसके प्रति भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। ट्रंप भारत के मित्र हैं या शत्रु, इस बारे में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए जयशंकर ने कहा, मैंने हाल ही में उनके (ट्रंप के) शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया था और हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया गया। मेरा मानना है कि वह एक अमेरिकी राष्ट्रवादी हैं।' उन्होंने स्वीकार किया कि ट्रंप की नीतियां वैश्विक मामलों में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती हैं, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की विदेश नीति राष्ट्रीय हित से निर्देशित होती रहेगी। जयशंकर ने कहा, हां, वह (ट्रंप) बहुत सी चीजें बदलेंगे, हो सकता है कि कुछ चीजें उम्मीद के अनुरूप नहीं हो, लेकिन हमें देश के हित में विदेश नीतियों के संदर्भ में खुला रहना होगा। उन्होंने कहा, 'कुछ मुद्दे हो सकते हैं जिन पर हम एकमत न हों, लेकिन कई क्षेत्र ऐसे होंगे जहां चीजें हमारे दायरे में होंगी। जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ट्रंप के बीच मजबूत व्यक्तिगत संबंधों पर भी जोर देते हुए कहा, अमेरिका के साथ हमारे संबंध मजबूत हैं।

ऑफ बीट

वायरल गर्ल मोनालिसा को मिली बॉलीवुड फिल्म

प्रयागराज महाकुंभ में माला बेचने वाली वायरल लड़की मोनालिसा बॉलीवुड में एंट्री लेने वाली है। वे डायरेक्टर सनोज मिश्रा के साथ 'द डायरी ऑफ मणिपुर' में आने वाली है। इस बात की जानकारी खुद डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने एक वीडियो शेयर करते हुए दी है। सनोज मिश्रा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह मोनालिसा के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे है। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है कि नमस्कार दोस्तों मैं फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा। मेरे साथ आज प्रयागराज की सनसनी बनी हुई मोनालिसा हैं और आप लोगों से जैसा की मैंने कहा था कि मेरी अगली फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' में मैं इनको कास्ट कर रहा हूं, तो मैं इनसे मिलने के लिए प्रयागराज भी गया था और अब इनके गांव आया हुआ हूं। इसके आगे डायरेक्टर ने कहा कि मैं आज इनकी फैमिली के साथ, इनके पिताजी के साथ पूरे परिवार के साथ बैठकर हमारी बातचीत हुई। सारे मुद्दों पर बातचीत हुई और सच कहूं तो बहुत ही इनोसेंट लोग है। ये मेरी सोच से भी परे लोग हैं इतने इनोसेंट हैं। अब से मैंने जो वेडा उठाया था, मुझे लग रहा है कि अब से मेरी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि मैंने वो जिम्मेदारी ली थी। अब इसे बहुत अच्छे से प्रेजेंट भी करूंगा।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

हिन्दुस्तान 1936

विराट लोकप्रियता

भारतीय क्रिकेटरों की लोकप्रियता का जो नजारा गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी के अरुण जेटली स्टेडियम में देखने को मिला, वह विरल और विचारणीय है। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को खेलते हुए देखने के लिए हजारों दर्शक उमड़ पड़े। मैच अंतरराष्ट्रीय स्तर का नहीं था। दिल्ली और रेलवे के बीच रणजी ट्रॉफी का सामान्य मुकाबला था। ऐसे मैच को देखने बमुश्किल दस हजार लोग जुट पाते हैं, पर चूंकि इस मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली खेलने वाले थे, इसलिए दर्शकों का हुजूम उमड़ पड़ा। अनुमान था कि दस हजार लोग देखने आएंगे, तो उसी हिसाब से स्टेडियम को खोला गया था, पर भीड़ बढ़ती गई, स्टेडियम के स्टैंड बारी-बारी से खुलते गए। आयोजकों ने जरूरी चतुराई का परिचय दिया। शुरू में दर्शकों को जब लगा कि वे विराट कोहली को नहीं देख पाएंगे, तब उन्होंने अपनी मांग के साथ शोर मचाया और कामयाब हुए। ऐसे फैसलों के लिए आयोजकों को आगे भी तैयार रहना चाहिए।

दरअसल, विराट कोहली ने प्रथम श्रेणी के ऐसे क्रिकेट मैच में खेलना लगभग बंद कर दिया था। वह केवल अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों या आईपीएल में खेलने उतरते थे। चूंकि अंतरराष्ट्रीय मैचों में स्टेडियम के अंदर पहुंचना आसान या फिफायती नहीं होता है, अतः बड़ी संख्या में दर्शकों के मन में अपने प्रिय खिलाड़ी को देखने की ललक रह जाती है। पहले के दौर में बड़े खिलाड़ी भी प्रथम श्रेणी क्रिकेट में खेलने उतरते थे और दर्शकों को दीदार का मौका मिल जाता था। नए दौर में खिलाड़ियों ने फटाफट क्रिकेट पर ही अपना ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रखा है। ऐसे में, उन्हें आंखों के सामने देखने की इच्छा रखने वाले आम दर्शकों की चाहत को समझा जा सकता है। अरुण जेटली स्टेडियम में उमड़ी दर्शकों की भीड़ को देख या जानकर विराट कोहली भी इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि पिछले लगभग 12 साल तक उन्होंने अपनी लोकप्रियता के किस पक्ष को उपेक्षित छोड़ दिया था। दर्शक ही किसी भी खेल या खिलाड़ी को फर्श से अर्श पर पहुंचाता है। अगर देखने वाले ही न हों, तो खेल ही ठप्प हो जाए। विराट कोहली को देखने उमड़ी भीड़ वास्तव में पुराने और नए, दोनों तरह के खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने दिग्गज खिलाड़ियों को रणजी खेलने के लिए पाबंद करते हुए एक अच्छा फैसला लिया है। जाहिर है, दिग्गज खिलाड़ियों के प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलने से निचले स्तर पर क्रिकेट की गुणवत्ता और व्यवसाय में भी सुधार आएगा।

विराट कोहली ने प्रथम श्रेणी के ऐसे क्रिकेट मैच में खेलना लगभग बंद ही कर दिया था, पर अब उन्हें दर्शकों के प्रेम से नई प्रेरणा व ऊर्जा मिलेगी।

क्रिकेट ने इस देश को एक से बढ़कर एक अद्भुत नजारे दिखाए हैं। दिल्ली में जब दर्शक स्टेडियम के बाहर शोर मचा रहे थे, तब प्रधानमंत्री का काफिला गुजर रहा था। पुलिस ने भी आयोजकों को कहा कि दर्शकों को स्टेडियम के अंदर लिया जाए। स्टेडियम में दर्शकों के आते ही माहौल बन गया और 'कोहली, कोहली' की गगनभेदी गूंज दूर-दूर तक पहुंचने लगी। ऐसे नजारे रणजी या दिलीप ट्रॉफी में दुर्लभ हैं। इससे प्रथम श्रेणी क्रिकेट का महत्व भी बढ़ जाएगा। टेस्ट मैच में विशेष रूप से हमारी टीम का प्रदर्शन निराशाजनक हो गया है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के हाथों बुरी हार दर्शकों को बेचैन कर रही है। भारतीय क्रिकेटप्रेमी यही चाहते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाजों को नई ऊर्जा और प्रेरणा मिले, ताकि उनके बल्ले पहले की तरह खूब बोलने लगें।

हिन्दुस्तान SindhuStan | 75 साल पहले 31 जनवरी, 1950

स्वदेशी की प्रेरणा

स्वदेशी के ग्रहण और विदेशी के बहिष्कार की पुकार हमारे यहां नई नहीं, बल्कि इस सदी के प्रारंभ की है, जब लंकाशायर के तथा दूसरे विदेशी कपड़े और मारीशस की विदेशी चीनी आदि के खिलाफ जोरों की हलचल शुरू हुई थी। हमारी राष्ट्रीय हलचल के इतिहास में वह काल 'स्वदेशी और बहिष्कार का युग' कहलाता है, जिसे महात्मा गांधी के 'सत्याग्रह और असहयोग' के समय सम्पूर्णता मिली। विदेशी कपड़ों की होली तथा अन्य विदेशी वस्तुओं के परित्याग के उस समय को देखे हुए अनेक व्यक्ति आज भी हमारे देश में विद्यमान हैं और यह कहना अत्युक्ति नहीं होगी कि भारत में कपड़े, चीनी आदि के उद्योगों को जो इतनी समृद्धि मिली उसका बहुत कुछ कारण विदेशी बहिष्कार तथा स्वदेशी-ग्रहण की हमारी हलचल ही है। स्वराज्य-प्राप्ति की अपनी लक्ष्य-सिद्धि के बाद, ऐसा लगता है, हमारी वह हलचल ही ढीली नहीं हुई, बल्कि उसके साथ ही स्वदेशी की हमारी भावना भी ढीली पड़ गई। राजनैतिक दृष्टि से शायद यह अनुचित भी नहीं है, क्योंकि विदेशी सत्ता हटने के बाद विदेश के प्रति हमारी कड़वाहट या विरोधी भावना भी खत्म हो जाती है; परन्तु राष्ट्रहित का सारा दारोमदार राजनीति पर ही नहीं होता, बल्कि अर्थनीति भी उसमें अपना बहुत योग रखती है। इस दृष्टि से देखें तो परतंत्रता-मुक्ति के बाद भी स्वदेशी की भावना का बने रहना आवश्यक है। रविवार २९ जनवरी को राजधानी में आयोजित भारतीय उद्योग प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए सरदार वल्लभभाई पटेल ने इसलिए स्वदेशी पर जोर दिया, यह सर्वथा उचित एवं सामयिक है।

सरदार पटेल ने बताया कि आजादी तो हमें मिल गई, लेकिन आम लोगों की हालत में कोई फर्क नहीं पड़ा है। उनके लिए भोजन, वस्त्र तथा निवास-स्थान की समस्या उल्टे बढ़ गई है, क्योंकि देश-विभाजन के फलस्वरूप उपजाऊ प्रदेश विदेश बन गये हैं तथा पड़ोसी देश का व्यवहार ऐसा है कि चीजों का आदान-प्रदान निर्बाध और सुलभ नहीं रहा। साथ ही दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों की गड़बड़ी और मुसीबत का भी आपने जिक्र किया और बताया कि अपने देश भारत को इस तरह की मुसीबत से बचाना है। इस तरह आजादी के बावजूद वह मुसीबत का वक्त है और सच्ची आजादी मनाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने देश को आर्थिक रूप में स्वावलम्बी बनायें।

प्रतिभाओं की राह न रोके अमेरिका

यहां स्कैन करें

फ्रेंक एफ इस्लाम | अमेरिकी उद्यमी व समाजसेवी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, उधर, अनेक खतरे हैं। अमेरिका में प्रतिभाओं की कमी हो सकती है और आर्थिक विकास व नवाचार कमजोर पड़ सकता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया की चिंता बहुत बढ़ा दी है। वह अवैध अप्रवासियों के साथ आतंकियों जैसा व्यवहार करेंगे, उन्हें खतरनाक जेलों में डाल देंगे। अमेरिका में कई जगह सीमा पर सेना तैनात की गई है, ताकि घुसपैठ रुक जाए। घुसपैठियों के साथ बुरे व्यवहार की तैयारी है। इतना ही नहीं, ज्यादा बड़ी चिंता यह है कि वैध रूप से प्रतिभाशाली युवाओं के अमेरिका आने के रास्तों को काफी हद तक बंद करने की तैयारी है।

एच-1बी वीजा पिछले चार दशक में अमेरिका के तकनीकी उद्योग के विकास को आगे बढ़ाने में बहुत मददगार रहा है। इन वर्षों में लाखों इंजीनियर व विशेषज्ञ अमेरिका आए हैं, उन्होंने यहां उद्योग के विकास में बहुत योगदान दिया है और खुद भी लाभान्वित हुए हैं। अमेरिका को सफलता के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ाने में अनेक ऐसे लोगों का हाथ है, जिन्हें एच-1बी वीजा का लाभ मिला है। आज दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क को भी यह लाभ मिला था। क्रमशः माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट (गूगल की होल्डिंग कंपनी) के सीईओ सत्य नडेला और सुंदर पिचाई भी यह सुविधा पाने वालों में शामिल हैं। जाहिर है, इन तीनों हस्तियों अलावा भी लाखों प्रतिभाएं हैं, जिन्होंने अमेरिका की संपन्नता में अपना भरपूर योगदान दिया है।

नवंबर के राष्ट्रपति चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद से एच-1बी के भविष्य पर एक गहन बहस छिड़ गई है। यह बहस दिसंबर के अंत में मस्क और विवेक रामास्वामी द्वारा सोशल मीडिया पोस्टिंग से ही शुरू हो गई थी, जिन्हें ट्रंप ने सरकारी दक्षता सलाहकार आयोग विभाग के सह-प्रमुख के रूप में नामित किया था। हालांकि, यह निर्णय अटक गई। अनेक पेशेवर यही चाहते हैं कि अमेरिका अपने यहां प्रतिभाओं का स्वागत करता रहे, ताकि उसके विकास की रफ्तार बनी रहे।

ट्रंप के एमएजीए (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) के अभियान का भी कड़ा विरोध हो रहा है। हालांकि, ट्रंप इसी वादे के साथ दूसरी बार भी चुनाव जीते। ट्रंप समर्थक समूह ने सख्त आप्रवासन नियंत्रण की दृढ़ता से वकालत की है। यह तर्क दिया है कि यह उद्यम वीजा कार्यक्रम अमेरिकियों को नौकरी से वंचित करता है, साथ ही, उनके वेतन को भी घटाता है।

20 जनवरी को ट्रंप के सत्ता संभालने के साथ ही बदलाव का दौर शुरू हो गया है। यहां यह एक परंपरा रही है कि अमेरिकी जमीन पर पैदा होने वाले किसी भी बच्चे को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता मिल जाती है, पर ट्रंप के नेतृत्व में बदलाव हुआ है। आप्रवासन जैसे विषयों पर संघर्ष करने वाले वकीलों ने चेतावनी दी है कि यह कार्यकारी आदेश मोटे तौर पर अमेरिका में पैदा हुए उन बच्चों पर लागू हो सकता है, जिनके माता-पिता अमेरिकी नागरिक या ग्रीन कार्ड-धारी नहीं हैं। यह आदेश 19 फरवरी को प्रभावी होने वाला है। अगर अदालत इस आदेश पर रोक न लगाए, तो क्या होगा? एच-1बी और एल-1 वीजा धारकों के बीच व्यापक चिंता फैल गई है।

लोगों को अभी भी उम्मीद है कि ट्रंप अपना रुख लचीला कर लेंगे और ट्रंप ने ऐसे कुछ संकेत दिए भी हैं, पर उनकी कथनी-करनी में फर्क है। वैसे, गौर करने की बात है कि राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने एच-1बी आवेदनों की जांच की थी और कई आवेदनों को खारिज किया था।

अमेरिका में एक और बदलाव हुआ है, 20 जनवरी को अमेरिकी दक्षता सलाहकार आयोग विभाग का काम संभालने से पहले ही विवेक रामास्वामी की छुट्टी कर दी गई है। यह बताने की कोशिश हो रही है कि रामास्वामी ओहियो के गवर्नर पद के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इसीलिए वह राष्ट्रीय जिम्मेदारी से पीछे हट गए हैं। हालांकि, सच यही है कि रामास्वामी उद्यम वीजा या एच-1बी के समर्थक रहे हैं और इसी वजह से उनके नाम की घोषणा ट्रंप समर्थकों को बहुत चुभती रही है।

रामास्वामी को जिम्मेदारी न मिलने के पीछे जो भी कारण हो, एच-1बी पर चल रही बहस भारतीय अमेरिकी समुदाय और भारतीय तकनीकी क्षेत्र के लिए विशेष महत्व रखती है। वर्तमान में 70 प्रतिशत से अधिक एच-1बी वीजा भारतीय नागरिकों को दिए जाते हैं, जिससे वे इस सुविधा के सबसे बड़े लाभार्थी बन जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2023 की बात करें, तो 3,86,318 स्वीकृत एच-1बी याचिकाओं में 2,79,386 यानी लगभग 72.3 प्रतिशत भारतीय नागरिकों को जारी किए गए थे। बीते वित्त वर्ष में 4,41,502 वीजा स्वीकृत किए गए थे और वीजा पाने वालों में 3,20,791 यानी 72.6 प्रतिशत भारतीय नागरिक थे।

कई भारतीय अमेरिकियों के लिए एच-1बी वीजा एक आर्थिक जीवन रेखा, समृद्धि का मार्ग और पराए देश में ताकत बढ़ाने का साधन रहा है। गौर कीजिए, इस देश में पिछले 25 वर्षों में भारतीय अमेरिकी आबादी तीन गुना से ज्यादा हो गई है। 16 लाख से बढ़कर 50 लाख पार कर गई है। इससे अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों का सियासी प्रतिनिधित्व भी बढ़ा है। केंद्रीय स्तर पर चुने गए प्रतिनिधियों की संख्या शून्य से बढ़कर छह तक पहुंच गई है। इसके अलावा, अनेक भारतीय मूल के अमेरिकियों के पास वहां राज्यों में अहम राजनीतिक या प्रशासनिक जिम्मेदारी है। वैसे, भारतीय प्रतिभाओं से केवल अमेरिका ही फायदे में नहीं है, इससे खुद भारत को भी फायदा हो रहा है। इससे भारतीय आईटी क्षेत्र के विकास को भी बल मिला है। ऐसे में, जब वीजा सुविधा पर गाज गिरेगी, तब भारतीय अमेरिकी समुदाय ही नहीं, भारतीय आईटी उद्योग भी बहुत प्रभावित होगा।

राष्ट्रपति ट्रंप के आसपास ऐसी अनेक ताकतवर हस्तियां हैं, जो एच-1बी का विरोध करती रही हैं। इनका मानना है कि यह वीजा नीति अमेरिकी श्रमिकों को कमजोर करती है। टकर कार्लसन जैसी मीडिया हस्तियां इन तर्कों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करती हैं।

बेशक, कमला हैरिस राष्ट्रपति बनतीं, तो ग्रीन कार्ड बैकलॉग को कम करने और अमेरिका में अप्रवासियों के स्थायी निवास के रास्ते का विस्तार करने पर चर्चा हो रही होती। इसके बजाय, ट्रंप के नेतृत्व में एच-1बी सुविधा पर खतरे की तलवार लगातार मंडरा रही है।

एच-1बी पर चल रही बहस सिर्फ आप्रवासन का मामला नहीं है, इससे अमेरिका की प्राथमिकताएं भी बदल जाएंगी। यह जनमत संग्रह की तरह होगा कि अमेरिका को किस दिशा में आगे बढ़ना है? अभी ट्रंप जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, उधर अनेक खतरे हैं। अमेरिका में प्रतिभाओं की कमी हो सकती है और आर्थिक विकास व नवाचार कमजोर पड़ सकता है। बदलावों की दिशा में बढ़ते कदम अमेरिका और भारत ही नहीं, वैश्विक प्रौद्योगिकी को भी प्रभावित करेंगे। वीजा की यह विवादित बहस जितनी जल्दी सुलझ जाए, उतना अच्छा है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

एआई के बल पर बढ़त बनाने और बांटने का बोलबाला

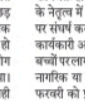

यहां स्कैन करें

राहुल जैकब | आर्थिक शोधकर्ता व वरिष्ठ पत्रकार

आज की दुनिया में जिस एक चीज की अपेक्षा की जा सकती है, वह है अनपेक्षितता, यानी कोई अपेक्षा ही नहीं की जा सकती। 21 जनवरी को अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओपेनएआई के सैम ऑल्टमैन, ओरेकल के लैरी एलिसन और सॉफ्टबैंक के मसायोशी सेन के साथ मिलकर 500 अरब डॉलर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट (एआई परियोजना) की घोषणा की। करीब एक सप्ताह पहले अमेरिकी शेयर बाजार में टेक कंपनियों को तकरीबन एक ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था, क्योंकि निवेशक चीनी स्टार्टअप डीपसीक की चुनौतियों से घबरा से गए थे। डीपसीक ने 10 जनवरी को अपना पहला मुफ्त चैटबॉट एप जारी किया और तभी से एप्पल के एप स्टोर पर यह सबसे लोकप्रिय मुफ्त एप बन गया है।

कई विशेषज्ञ यही मान रहे हैं कि एआई एक उपयोगी उत्पाद बन जाएगा। शायद हम हरेक जगह कंपनियों व व्यक्तियों द्वारा सस्ते एआई मॉडल का स्वर्णिम युग देखने वाले हैं, लेकिन चिप बनाने वाली एनवीडिया और एआई की दौड़ में आगे रहने वाली अन्य कंपनियों के शेयरों के लिए हालिया दिन विनाशकारी रहे हैं। 27 जनवरी को एनवीडिया की एक दिन की गिरावट शेयर बाजार के इतिहास में सबसे बड़ी गिरावट के रूप में दर्ज हो चुकी है। यहां कई सबक हैं, जिनको समझना चाहिए। मन चाहें, तो केस स्टडी के तौर पर डीपसीक का इस्तेमाल बतौर उदाहरण यह सवाल करने के लिए कर सकते हैं, जो मैंने फैशनेबल अर्थनिक नीति के बारे में भी कही थी। सिर्फ इसलिए कि दूसरे देश ऐसा कर रहे हैं, यह मतलब नहीं है कि भारत में भी ज्यादातर बड़ी कंपनियों के लिए सब्सिडी राज अच्छी नीति है।

डीपसीक ने बताया कि हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं, जिसको अच्छे और बुरे में बांटकर अमेरिका व चीन द्वारा नव-निर्माण किया जा रहा है।

अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धियों के खिलाफ टैरिफ बढ़ाने से घरेलू अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। भारत में श्रमिक-बहुलता वाले निर्यातकों से बात करने के बाद मैंने लघु एवं मध्यम आकार के निर्यातकों से यही शिकायत सुनी कि बाहर से आने वाले कच्चे या अर्द्ध-निर्मित मालों पर नई दिल्ली द्वारा अधिक टैरिफ लगाने से उनकी प्रतिस्पर्द्धा कम हो गई। दशकों पहले, यही कहा जाता था कि अमेरिका द्वारा इस्पात आयात पर लगाई गई टैरिफ से डेट्रॉयट की गैस वाली कारें समाप्त हो गईं और टोयोटा व अन्य गाड़ियों के लिए राहें आसान हो गईं।

कयास यह है कि अमेरिकी सरकार ने चीनी कंपनियों को हाईएंड चीप से दूर रखने का प्रयास किया, जिससे डीपसीक इस कदर लार्ज-लैंग्वेज मॉडल बना सका। हालांकि, कुछ लोगों को संदेह है कि डीपसीक की ऐसी चीप तक पहुंच थी, लेकिन उसने यह बात छिपा रखी थी। ऐसे में, डीपसीक की सफलता पिछले कई वर्षों में इलेक्ट्रिक कारों, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और अब एआई जैसे क्षेत्रों में चीन द्वारा किए गए उल्लेखनीय विकास को बयान करती है। चीन के श्रम-प्रधान निर्यात को भी, जिसे वह पसंद नहीं करता, अपनी फैक्टरियों में, माल प्रबंधन में और अति कुशल बंदरगाहों पर रोबोट के इस्तेमाल से लाभ होता है। यहां यह जानना जरूरी है कि ताइवान और हांगकांग की कंपनियां करीब आधी सदी से आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन कर रही हैं और अपने प्रौद्योगिकियों पर चीन की बढ़त बनाने का काम करती हैं, जिसे 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' और 'मेक इन इंडिया' के झंडाबरदार नजरंदाज कर देते हैं। इसी कारण साल 2023 में आई *ब्रेकिंग द मॉल्ड* किताब के लेखकों द्वारा केंद्र व गुजरात सरकार द्वारा गुजरात में समीकंडक्टर प्लांट बनाने के लिए एक अमेरिकी कंपनी को भारी सब्सिडी देने की योजना की आलोचना उचित है।

साफ है, इस सप्ताह की घटनाएं यही बता रही हैं कि हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं, जिसको अच्छे और बुरे में बांटकर अमेरिका और चीन द्वारा तेजी से नव-निर्माण किया जा रहा है। बेशक, चीन की अर्थव्यवस्था में कमजोर मांग और हद से अधिक निवेश की समस्या है, लेकिन जैसा कि *शाइनोकिज्य* के लेखक बिल बिशप कहते हैं, डीपसीक द्वारा हर किसी को अपना काम उपलब्ध कराना एक शानदार कदम है। ट्रंप प्रशासन भले ही निर्यात को प्रतिबंधित कर दे, लेकिन यह एआई को लेकर अमेरिका व उसके मित्र-राष्ट्रों और शेष दुनिया (विशेषकर ग्लोबल साउथ) में बांटने का ही काम करेगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

सपने देखना जारी रखिए

साल 1986 की बात है। मैं पहली और आखिरी बार स्पेन के 'वे टु सैंटियागो' तीर्थस्थल गया था। हमने एक छोटी पहाड़ी पर अपना सफर खत्म ही किया था कि क्षितिज पर एक गांव दिखाई पड़ा। ठीक उसी समय मेरे गाइड पेड्रस ने मुझसे कहा था, 'हमें सपने देखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। सपने आत्मा को पोषण प्रदान करते हैं, ठीक वैसे ही, जैसे भोजन शरीर का करता है। जीवन में कई बार हम अपने सपनों को बिखरते हुए देखते हैं और हमारी इच्छाएं मरने लगती हैं, लेकिन हमें सपने देखना जारी रखना होगा। यदि हम ऐसा नहीं करते, तो हमारी आत्मा मर जाती है।'

अच्छी लड़ाई वह होती है, जो हम अपने लिए लड़ते हैं, क्योंकि हमारा दिल हमसे इसकी इजाजत लेता है। अच्छी लड़ाई वह है, जो हमने अपने सपनों के नाम पर लड़ी है। जब हम युवा होते हैं, तब सपने अपनी पूरी ताकत के साथ हमारे अंदर प्रस्फुटित होते हैं। तब हम बहुत साहसी होते हैं, पर उन सपनों के लिए कैसे लड़ना है, यह नहीं जानते। कठिन प्रयासों से हम सीखते हैं कि कैसे लड़ना है, लेकिन तब तक हमारे पास युद्ध में जाने की हिम्मत नहीं बचती। इसलिए हम अपने भीतर लड़ाई करते हैं और अपना सबसे बड़ा दुश्मन बन जाते हैं। हम कहने लगते हैं, हमारे सपने बचकाने थे। अपने सपनों को मारते जाते हैं, क्योंकि हम अच्छी लड़ाई लड़ने से डरते हैं।

हमारे सपनों की मृत्यु का एक बड़ा लक्षण निश्चितता की चाह है। हम जीवन को एक रोमांचक अभियान के रूप में नहीं देखते। हम अपने आप को बुद्धिमान, निष्पक्ष समझना शुरू कर देते हैं और अपनी जिंदगी से कम से कम सवाल करने को उचित मानने लगते हैं। हम अपने से परे देखने लगते हैं; हम तलवारों, बरछियों के टूटने की खनक सुनना शुरू कर देते हैं, हम धूल और पसीने सूंघने लगते हैं और योद्धाओं की आंखों में शिकस्त देखने लगते हैं, हम कभी उनकी असली खुशी नहीं देख पाते। उनके लिए हार और जीत महत्वपूर्ण नहीं होती; महत्वपूर्ण बात यह होती है कि वे कितनी अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं।

हमारे सपनों के अंत का एक लक्षण शांति की चाह है। ऐसी स्थिति में हम अपने जीवन से कुछ भी भव्य मांगना बंद कर देते हैं। उस अवस्था में हम खुद को परिपक्व मानने लगते हैं; लेकिन वास्तव में हम अपने सपनों के लिए लड़ने से इनकार कर रहे होते हैं। दरअसल, अपनी कायरता से हम पराजय को अपने करीब बुलाते हैं और एक दिन सपने न होने के कारण हमारा सांसें लेना मुश्किल हो जाता है और तब हम वास्तव में मौत की तलाश करते हैं। यह मृत्यु ही हमें निश्चितताओं से, हमारे काम से और भयानक शांति से मुक्त करता है।

जीवन में कई बार हम अपने सपनों को बिखरते हुए देखते हैं और हमारी इच्छाएं मरने लगती हैं, लेकिन हमें सपने देखना जारी रखना होगा। यदि हम ऐसा नहीं करते, तो हमारी आत्मा मर जाती है।

पाउलो कोएल्हो

राहुल गांधी | नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा

गांधीजी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, भारत की आत्मा हैं और हर भारतीय में आज भी जीवित हैं। सत्य, अहिंसा और निडरता की शक्ति बड़े से बड़े साम्राज्य की जड़ें हिला सकती है। पूरा विश्व उनके इन आदर्शों से प्रेरणा लेता है।

हादसे के बाद उंगली प्रशासन की ओर

सामाजिक जीवन में उत्सव जरूरी है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि महाकुम्भ में संगम तट पर आस्था की अभिव्यक्ति के फलस्वरूप करोड़ों लोग जमा हो रहे हैं। मगर ऐसे आयोजनों में जिस तरह हादसे होने लगे हैं, वे अपने आप में यह सवाल खड़े करते हैं कि क्या अब इस तरह की भीड़ का जुटना जानलेवा बन गया है? महाकुम्भ में जनसैलाब का उमड़ जाना तय था, फिर भी मंगलवार-बुधवार की रात वहां भगदड़ मच गई। यह संकेत है कि आयोजन स्थल पर लोगों की संख्या को सीमित रखने या वहां पहुंचाने को लेकर लापरवाही बरती गई, जिसकी कीमत कई लोगों ने चुकाई। इस घटना से एक बार फिर यही साफ होता है कि धार्मिक आयोजनों में पूर्व में हुए हादसों से सबक नहीं लिया जाता है। यह देखा जाना चाहिए कि आयोजन में यदि तय संख्या से अधिक लोग पहुंच रहे हैं, तो उनको पूर्व में ही रोक लिया जाए या फिर भीड़ का उचित प्रबंधन हो। मगर प्रयागराज में ऐसा नहीं हो सका। यदि अब भी सबक नहीं लिया, तो यह अनुचित ही होगा। जहां भी ज्यादा संख्या में लोगों के जमा होने की संभावना हो, वहां प्रशासन सभी स्तरों पर सुरक्षा व बचाव के इंतजाम सुनिश्चित कर ले। ऐसे हादसों में उंगली प्रशासन पर ही उठती है, क्योंकि आयोजन का सफल प्रबंधन उसी की जिम्मेदारी होती है।

सूर्यदीप कुशवाहा, टिप्पणीकार

वीआईपी संस्कृति पड़ी भारी

प्रयाग महाकुम्भ में भगदड़ एक दुखद घटना है। शासन, प्रशासन ने चाहे दैवी हो या समाचारपत्र, महाकुम्भ का बढ़-चढ़कर प्रचार-प्रसार किया था। नतीजतन, काफी बड़ी संख्या में भीड़ वहां एकत्र होने लगी है। जब यह बात सबको पहले से मालूम थी कि भारी भीड़ हादसों को जन्म दे सकती है, तो पहले से ही भीड़ को नियंत्रित या उनके प्रबंधन के उपाय कर लेने चाहिए थे। मगर ऐसा नहीं किया गया। फिर, आमतौर पर यह भी देखने को मिलता है कि श्रद्धालुगण ऐसे अवसरों पर संयम कतई नहीं रखते। अधीर होना भीड़ का चरित्र है। इसीलिए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए था। मगर खबरों में जैसा बताया जा रहा है, वीआईपी संस्कृति को बढ़ावा दिया गया, जिसकी कीमत आम श्रद्धालुओं ने चुकाई। क्षमता से अधिक भीड़ जुटने का अंदेशा होने के बावजूद उचित व्यवस्था नहीं की गई, जिस कारण भगदड़ मच गई। सवाल यह भी है कि जब सफलता में वाहवाही लूटने का कोई मौका नहीं गंवाया जाता, तो जानलेवा घटनाओं की जिम्मेदारी लेने का साहस भी दिखाना चाहिए। देखते हैं कि आगे ऐसा कुछ होता है या नहीं?

हेमा हरि उपाध्याय, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम
महाकुम्भ में हादसा

इंतजामों को नाकाफी साबित करती भीड़

प्रयागराज महाकुम्भ में मौनी अमावस्या के मौके पर करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाकर सनातन-संस्कृति और सभ्यता का नया इतिहास रच दिया। आयोजन में भगदड़ के हालात जरूर बने, लेकिन उसे संभाल लिया गया। करोड़ों की भीड़ में किसी प्रकार की अफरातह से भी सावधान रहने की जरूरत होती है। महाकुम्भ में आस्था की डुबकी सुकून और पुण्य लाभ प्राप्त करने की होती है। सभी श्रद्धालुओं को भी स्नान-ध्यान का मौका देना, हम सभी का परम कर्तव्य होना चाहिए। वास्तव में, नागरिकों को अपनी जान-माल की रक्षा के लिए खुद जागृत रहना होता है। सहयोग व सामंजस्य बनाकर रखना होता है। जब श्रद्धालुओं की संख्या करोड़ों में हो, तो व्यवस्थाओं में चूक होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए, आस्था की डुबकी में कोई खलल न हो, ऐसी कारगर रणनीति तैयार करनी होगी। महाकुम्भ देश का पौराणिक-ऐतिहासिक महत्व रखने वाला आयोजन है। इसे जीवंत रखना जरूरी है। वर्तमान प्रशासन और जांबाज जवानों को सलाम, जो इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और जनता-जनार्दन की अपनी कर्तव्य-निष्ठा से अवगत करा रहे हैं। अब जनता भी इस महाकुम्भ को यादगार बनाए व व्यवस्था बनाने में अपना सहयोग दे। इसकी सफलता इसी में निहित है।

योगेश जोशी, टिप्पणीकार

सावधानी बरतें श्रद्धालु

महाकुम्भ हमारी सांस्कृतिक-आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। इसमें करोड़ों श्रद्धालु हिस्सा ले रहे हैं और संगम में डुबकी लगाकर पुण्य के भागी बन रहे हैं। यह आयोजन बताता है कि कैसे साझा उद्देश्य के लिए करोड़ों लोग जमा होते हैं और प्रशासन अपनी मुस्तैदी से उनकी सुरक्षा में तत्पर रहता है। देखा जाए, तो केंद्र और राज्य सरकारें प्रशंसा के काबिल हैं, जिन्होंने प्रयागराज में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए इतनी उचित व्यवस्था की है। यह सही है कि भगदड़ में कई लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा, लेकिन उम्मीद है कि सरकार इस हादसे की उचित व निष्पक्ष जांच करेगी और जिन वजहों से यह हादसा हुआ है, उनको गंभीरता से दूर करने के उपाय करेगी। हालांकि, हाथ श्रद्धालुओं को आगे कोई परेशानी न हो। वास्तव में, सरकार, प्रशासन और पुलिस आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चाहे जितनी मर्जी काम कर लें, जब तक आम लोग इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करते, हादसों का खतरा बना रहता है। महाकुम्भ जैसे आयोजनों में भीड़ का होना स्वाभाविक है, इसलिए लोगों को संयम से काम लेना चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, टिप्पणीकार

सम्पादकीय

महाकुंभ में भगदड़ का सबक करोड़ों के इंतजाम धरे रह गए, हर बार दोहराई गई वही लापरवाही

महाकुंभ में मची भगदड़ ने पुराने जख्मों को कुरेद दिया है। आजादी के बाद से लेकर अब तक के कुंभ मेलों में कई बार भगदड़ मची है। सैकड़ों लोगों की मौत भी हुई, लेकिन उन सभी हादसों से कभी सबक नहीं लिया गया। हर बार कोई न कोई लापरवाही या व्यवस्था में खामी ही सामने आई। ज्यादातर मामलों में प्रशासन भीड़ को काबू करने में नाकाम रहा। पिछले कुंभ में भी यही हुआ था, जब बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुंचे श्रद्धालुओं को रेलवे और जिला प्रशासन संभाल नहीं पाया। स्टेशन पर बने 'फुटब्रिज' पर भगदड़ मची और बयालीस लोगों की मौत हो गई थी। इस बार भी ऐसा ही हुआ। महाकुंभ की सुरक्षा संभाल रहे जिम्मेदार लोगों को पता था कि मौनी अमावस्या पर बड़ी संख्या में लोग स्नान के लिए आएंगे, तो इसकी व्यवस्था उसी के अनुरूप क्यों नहीं की गई। स्पष्ट है कि भीड़ प्रबंधन के ठोस उपाय नहीं किए गए। कोई ज्यादा दिन नहीं हुए, जब कुंभ मेला क्षेत्र में आग लगने की घटना हुई थी। तब से वहां सुरक्षा बंदोबस्त बढ़ा दिए गए थे। ऐसे में लाखों-करोड़ों लोगों के जुटान को देखते हुए कई स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था करने की आवश्यकता थी। यह दुखद है कि हर कुंभ मेले के आयोजन के बाद और बेहतर तैयारियां तथा सुरक्षा प्रबंध पुख्ता करने के दावे किए जाते हैं। मगर हादसे नहीं थमते। इस बार महाकुंभ से पहले ही अनुमान लगाया जा रहा था कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम स्थल पर पहुंचेंगे। कुंभ मेला स्थल तैयार करते समय अनुभवी अधिकारियों को क्या अनुमान नहीं था कि इस बार बेहिसाब भीड़ पहुंचेगी? जितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, उस हिसाब से तो कुंभ परिसर और नदी के तट अपर्याप्त हैं। इस समय उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा अमला आयोजन को सफल बनाने में जुटा है। फिर भी कहां कमी रह गई, यह सवाल स्वाभाविक है। संगम पर लगातार भीड़ बढ़ने और उस पर नियंत्रण के लिए पहले से आकलन क्यों नहीं किया गया? यह सुरक्षाकर्मियों की भी लापरवाही है, क्योंकि वे समय पर संकट को भांप नहीं पाए। मंगलवार और बुधवार की दरम्यानी रात भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की मौत होने बात कही जा रही है। 60 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। इस बीच विपक्षी दलों को भी आयोजन में बदइंतजामी का आरोप लगाने का स्वाभाविक अवसर मिल गया है, लेकिन इसी के साथ सबक उठना लाजिमी है कि तैयारियों में कमी कहां रह गई। इस आयोजन के लिए कई हजार करोड़ की राशि खर्च की गई। अत्यधिक प्रचार का असर यह हुआ कि देश के कोने-कोने में रह रहे श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान करने का मानस बना लिया।

नतीजा यह हुआ कि लाखों-करोड़ों लोग अलग-अलग परिवहन साधनों से संगम की ओर चल पड़े। तेरह जनवरी से शुरू हुए इस आयोजन के शुरुआती दौर में ही लाखों श्रद्धालुओं का जुटान होने लगा था। ऐसे में इतने लोगों के लिए पूरे शहर और मेला क्षेत्र में ठहरने के वैकल्पिक प्रबंध करने की आवश्यकता थी। इससे श्रद्धालु एक निश्चित संख्या में क्रम से संगम की ओर जाते और वहां से निकलते जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सभी इंतजाम धरे के धरे रह गए। करोड़ों की भीड़ को संभालने के लिए सात स्तरीय सुरक्षा भी काम नहीं आई। फिलहाल यह हादसा एक बार फिर कड़ा सबक दे गया है।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई विधि तरीकों को युक्त करेंगे तथा आज आप अवश्य पाएंगे कि आपके जीवन के कोई सौभाग्य होंगे, जब आपके विचारे कुशल होंगे और दुनियें सफल, आपकी किस बातों से लाभान्वित होगा पहिचान कर ले किसी बनाये प्रयत्न में और नहीं सुनो को सुनाकर तथा स्वाधानता अर्थ को समझ लेंगे, धार्मिक परमार्थिक संकेतों में लो, जब तक लाभकारक नहीं सफल और कामदेव में लक्ष्य प्रदान करेगा

मेष
राजभय रहेगा। विवाद को बढ़ाना न दें। लेन-देन में जल्दबाजी हानि देगी। शारीरिक कष्ट संभव है। अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे। व्यवसाय में मुश्किल होगी। दूसरों से अपेक्षा न करें। चिंता तथा तनाव रहेंगे। अनहोनी की आशंका रहेगी।

वृष
राज्य से प्रसन्नता रहेगी। कोई बड़ा काम हो सकता है। नई योजना बनेगी। नया उपक्रम प्रारंभ हो सकता है। सामाजिक कार्य करने का अवसर मिलेगा। प्रतिष्ठा बढ़ेगी। स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा। कोई नई समस्या आ सकती है।

मिथुन
किसी आनंदोत्सव में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा। कारोबार में बुद्धिबल से उन्नति होगी। नौकरी में मातहतों का सहयोग प्राप्त होगा। दुश्वनों से सावधानी आवश्यक है।

कर्क
लेन-देन में जल्दबाजी न करें। पुराना रोग उभर सकता है। दुःखद समाचार की प्राप्ति संभव है। किसी के उकसाने में न आएं। बात बिगड़ सकती है। आवश्यक निर्णय सोच-समझकर करें। नौकरी में कार्यभार रहेगा। लाभ के अवसर हाथ आएंगे।

सिंह
प्रेम-प्रसंग में आशातीत सफलता प्राप्त होगी। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। सट्टे व लॉटरी से दूर रहें। कारोबार का विस्तार होगा। नौकरी में प्रयोशन मिल सकता है। सुख के साधन जुटेंगे। शत्रु परास्त होंगे।

कन्या
पुराना रोग उभर सकता है। अनहोनी की आशंका रहेगी। मातहतों से कड़ासुनी हो सकती है। पार्टनरों से मतभेद संभव है। वाहन व मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें। दूसरों से अपेक्षा न करें। बनते काम बिगड़ सकते हैं। आय में निश्चितता रहेगी। कारोबार का विस्तार होगा।

तुला
आंखों को चोट व रोग से बचाएं। धन प्राप्ति सुगम होगी। सुख के साधन जुटेंगे। कारोबार लाभदायक रहेगा। नौकरी में उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे। मातहतों का सहयोग प्राप्त होगा। थकान व कमजोरी महसूस हो सकती है।

वृश्चिक
शत्रु भय रहेगा। जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। शारीरिक कष्ट संभव है। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। भूमि व भवन संबंधी खरीद-फरोख्त की योजना बनेगी। आर्थिक उन्नति होगी। व्यवसाय ठीक चलेगा। निवेश शुभ रहेगा।

धनु
पुराना रोग परेशानी का कारण बन सकता है। अज्ञात भय सताएगा। वाणी में हल्के शब्दों के प्रयोग से बचें। वैवाहिक प्रस्ताव मिल सकता है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। कुसंगति से बचें। चिंता रहेगी। धन प्राप्ति में अवरोध दूर होंगे।

मकर
आय में वृद्धि होगी। कारोबार लाभप्रद रहेगा। दुष्टजन हानि पहुंचा सकते हैं। दूर से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। घर में अतिथियों का आगमन होगा। व्यय बढ़ेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे।

कुंभ
घर-बाहर पूछ-परख रहेगी। आय में वृद्धि होगी। कारोबार का विस्तार होगा। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। प्रयास सफल रहेंगे। पार्टनरों का सहयोग प्राप्त होगा। निवेश लाभदायक रहेगा। घर में सुख-शांति रहेगी।

मीन
व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। नेत्र पीड़ा हो सकती है। मानसिक बेचैनी रहेगी। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। अधिकार प्राप्ति के योग हैं। पार्टनरों का सहयोग मिलेगा। नौकरी में उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे। भागदौड़ रहेगी। पारिवारिक चिंता बनी रहेगी।

आज का इतिहास | बढ़ता राजस्थान

31 जनवरी की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- मुगल बादशाह अकबर के संरक्षक बैरम खाँ की 1561 में गुजरात के पाटण में हत्या कर दी गई।
- ब्रिटेन की रानी एलिज़ाबेथ प्रथम के आदेश पर 1599 में भारत में ब्रिटेन की पहली ईस्ट इंडिया कम्पनी की स्थापना हुई।
- ब्रिटेन में तख्त के खिलाफ साजिश करने वाले गाइफ़ाक्स को 1606 में मौत के घाट उतार दिया।
- चीन में 1850 को ताए पींगहा (जनता का संकल्प) नाम से सबसे बड़ा जनान्दोलन आरंभ हुआ।
- अमेरिका में 'दासता उन्मूलन' संबंधी 13वां संशोधन विधेयक 1865 में स्वीकृत हुआ।
- अफगानिस्तान के अमीर के मर्व को रूसी फौजों ने 1884 में छीन लिया।
- अमेरिका में पहली बार 1893 में 'कोका कोला' ट्रेडमार्क का पेटेंट किया गया।
- 'प्रथम विश्व युद्ध' के दौरान जर्मनी ने 1915 में रूस के खिलाफ़ ज़हरीली गैस का इस्तेमाल किया।
- 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के फ़ील्ड मार्शल फ्रेडरिक पौलस ने सोवियत संघ की सेना के समक्ष हथियार डाले।
- तत्कालीन सोवियत संघ के मॉडल के आधार पर 31 जनवरी, 1946 को यूगोस्लाविया के 6 देशों (बोस्निया-हर्जेगोविना, सर्बिया, मैसेडोनिया, मोंटेनेग्रो, स्लोवेनिया, क्रोएशिया) का विघटन।
- 1953 में हुए आईरिश सागर में नौका दुर्घटना में चालक दल के सदस्यों के साथ कम से कम 200 यात्रियों की मौत हो गई।
- अबादान से तेहरान तक पाइपलाइन बिछाने का काम 1957 में पूरा हुआ।
- अमेरिका ने 1958 में पहले भू-उपग्रह का प्रक्षेपण किया।
- अमेरिकी देशों के संगठन ने 1962 में क्यूबा को न शामिल करने का फैसला किया।
- मोर को 1963 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया।
- सोवियत संघ ने 31 जनवरी, साल 1966 को लूना कार्यक्रम के तहत मानवरहित लूना 9 स्पेशक्राफ्ट की लांचिंग की।
- प्रशान्त महासागर में स्थित द्वीपीय देश नौरू को 1968 में आस्ट्रेलिया से स्वाधीनता मिली।
- अमेरिका ने 1968 में नेवादा में परमाणु परीक्षण किया।
- पूर्व और पश्चिमी बर्लिन के बीच 19 साल के अंतराल के बाद 1971 में फिर से टेलीफोन सेवा बहाल हुई।
- बीरेन्द्र वीर विक्रम शाह 1972 में नेपाल के 12वें राजा बने।
- पेन अमेरिका एयरवेज़ का विमान 1974 में अमेरिकी सीमाओं में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें लगभग 25 लोग मारे गये।
- चीन ने 1979 में सोवियत संघ को विश्वयुद्ध भड़काने वाला मुख्य देश होने का आरोप लगाया।
- कोलकाता में 1983 को पहला शुष्क बंदरगाह शुरू हुआ।
- श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में 1996 में हुए आत्मघाती हमले में 86 की मौत, 1400 घायल।
- सन 2000 में हवाला केस के सभी आरोपी बरी।

विशेष आलेख

क्या बजट आम आदमी की उम्मीदों पर खरा उतरेगा?

ललित गर्ग

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लगातार अपना आठवां बजट पेश करेंगी। यह केंद्रीय बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार का अपने तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण वित्तीय बजट होगा। इस बार के बजट से हर सेक्टर की बड़ी उम्मीदें टिकी हुई हैं, इस बजट की घोषणाओं से भविष्य में राष्ट्र किन दिशाओं में आगे बढ़ेगा, उसकी संपन्न एवं दिशा अवश्य स्पष्ट होगी। टैक्सपेयर्स भी इस बार वित्तमंत्री से इनकम टैक्स में राहत देने की उम्मीद कर रहे हैं। मिडिल-क्लास और वेतनभोगियों को भी राहत की उम्मीद है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की एक मौलिक सोच एवं दृष्टि से यह बजट दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था को एक चमकते सितारे के रूप में स्थापित करने एवं सुदृढ़ आर्थिक विकास के लिये आने की राह दिखाने वाला होगा।

संभावना है कि इस बजट में समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचे में निवेश, क्षमता विस्तार, हरित विकास, महिलाओं एवं युवाओं की भागीदारी, मोदी की गारंटियों पर बल दिया जायेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल और सामाजिक विकास की दृष्टि से देश को आत्मनिर्भर बनाने की रफ्तार को भी गति दी जायेगी। यह बजट देश को न केवल विकसित देशों में बल्कि इसकी अर्थव्यवस्था को विश्व स्तर पर तीसरे स्थान दिलाने के संकल्प को बल देने में सहायक बनेगा। आम आदमी बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और घटती खपत के बीच कुछ राहत की उम्मीद लगा रहा है। बजट, शिक्षा, रक्षा, उद्योग, महिलाओं और गरीब वर्गों के लिए सुधारों और प्रोत्साहनों का खाका तैयार करेगा। वित्त मंत्री से उम्मीद की जा रही है कि वे आयकर स्तैब में बदलाव करेंगी, जिससे वेतनभोगियों एवं करदाताओं को राहत मिलेगी। इस समय वेतनभोगी एवं करदाता की 15 लाख रुपये से अधिक की आमदनी पर 30 प्रतिशत टैक्स लगता है। सरकार 10 लाख रुपये तक की आय को पूरी तरह टैक्स-फ्री करने और 15 से 20 लाख रुपये की आमदनी पर 25 प्रतिशत का नया टैक्स स्तैब लाने पर विचार कर रही है। इससे मध्यम वर्ग के लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, जो अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करेगा। केंद्र सरकार बजट सत्र 2025 में नया आयकर कानून पेश करने की योजना बना रही है, जो करदाताओं को लाभान्वित करेगा और कर प्रणाली को सरल बनाएगा। इसके अलावा, सरकार इस बार के बजट में शेयर से होने वाली कमाई पर टैक्स लगाने का प्रावधान कर सकती है। इसमें शेयरों से मिलने वाले लाभांश, ब्याज से होने वाली कमाई और पूंजीगत लाभ पर भी टैक्स लगाया जा सकता है। यह बजट न केवल देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेगा, बल्कि सामाजिक और तकनीकी विकास की दिशा में भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण की भी संभावनाएं हैं। इस बजट से विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण घोषणाओं की उम्मीद है, जो अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने और आम जनता को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से की जा सकती हैं। आम आदमी के लिए सबसे पीड़ादायक टैक्स का बोझ है। हालांकि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) जैसे टैक्स का फैसला समय-समय पर जीएसटी काउंसिल में लिया जाता है, लेकिन सरकार से उम्मीद की जाती है कि वो इन शुल्कों को और तर्कसंगत बनाकर आम लोगों को कुछ राहत दे। अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ने के कारण निवेशकों में घबराहट है और इसने रोज़गार के अवसरों को भी कम किया है जबकि महंगाई के हिसाब से मजदूरी और वेतन में बढ़ोतरी नहीं होने से खासकर सीमित आमदनी वाले परिवारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पिछली तिमाहियों में कंपनियों के निराशाजनक प्रदर्शन ने भी इन हालात को मुश्किल बनाया है। जिससे नौकरी चाहने वाले युवाओं को पर्याप्त संख्या में रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। इन सारे कारकों के कारण मध्य वर्ग ने अपने खर्चों में कटौती की है जिससे पिछले कुछ महीनों में उपभोग में गिरावट आई है। इन परेशानियों एवं चिन्ताओं को कम करने में इस बार का बजट राहतभरा होने की उम्मीदें हैं। बजट में विभिन्न उद्योगों, विशेषकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा से रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। सड़कों, रेल, बंदरगाहों और हवाई अड्डों के विकास के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की योजना बनाई जा सकती है, जिससे लॉजिस्टिक्स में सुधार होगा और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, जिससे मानव संसाधन का विकास हो सके। महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की जा सकती है, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं लाई जा सकती हैं। उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों के लिए अतिरिक्त अनुदान दिया जा सकता है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, और चिकित्सा के क्षेत्र में इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजनाएं लाई जा सकती हैं। ■मेक इन इंडिया■ पहल के तहत स्वदेशी हथियार निर्माण को प्रोत्साहित किया जाएगा। साइबर खतरों से निपटने के लिए रक्षा बजट का एक हिस्सा डिजिटल सुरक्षा पर केंद्रित हो सकता है। बुलेट ट्रेन परियोजनाओं और रेल नेटवर्क के आधुनिकीकरण को गति दी जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए सब्सिडी और बैटरी निर्माण में निवेश बढ़ाने की योजनाएं पेश की जा सकती हैं। ■गरीब कल्याण अन्न योजना■ का विस्तार कर मुफ्त राशन वितरण को जारी रखा जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घर उपलब्ध कराने के लिए बजट बढ़ाया जाएगा। यह बजट इसलिए विशेष रूप से उल्लेखनीय होगा क्योंकि मोदी सरकार ने देश के आर्थिक भविष्य को सुधारने पर ध्यान दिया, न कि लोकलुभावन योजनाओं के जरिये प्रशंसा पाने अथवा कोई राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की है। राजनीतिक हितों से ज्यादा देशहित को सामने रखने की यह पहल अनूठी है, प्रेरक है।

भगदड़ मचने के कारण और एहतियाती कदम !

सुनिल कुमार महला

हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला के दौरान मौनी अमावस्या के दिन मची भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई। वहीं, इस दर्दनाक हादसे में 90 लोग घायल हो गए। दरअसल,संगम तट से पहले बने द्वार के पास रात करीब 1 बजे भगदड़ की स्थिति बनी। वास्तव में, कई श्रद्धालुओं की मौत और घायल होने से यकायक मेला स्थल पर अफरातफरी मच गई।

हालांकि,पुलिस, प्रशासन, आपदा प्रबंधन की टीम ने तत्परता दिखाते हुए राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन जो हुआ है वह बहुत ही दुखद है। पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि हाल ही में 28 अक्टूबर को दक्षिण कोरिया के सियोल के इटावन में हैलोवीन कार्यक्रम के दौरान 150 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और 2 अक्टूबर को इंडोनेशिया के मलंग में एक फुटबॉल मैच के बाद 130 से अधिक लोगों की मौत का कारण बनी भगदड़ से पता चलता है कि भगदड़ कितनी खतरनाक होती है। वास्तव में किसी भगदड़ में मौत का सबसे आम कारण कंप्रेसिव एस्फिक्सिया को माना जाता है, जो एक खतरनाक स्थिति है, यह तब होती है जब शरीर पर बाहरी दबाव के कारण सांस लेना बंद हो जाता है? पाठकों को जानकारी के लिए बताता चलूं कि महाकुंभ में स्नान के लिए 45 घाट बनाए गए हैं, लेकिन लोग मुख्य संगम पर ही स्नान करने की जिद करने लगे, जिससे भीड़ एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ने लगी और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लगे हुए बैरिकेटिंग टूटने लगे। बताया जा रहा है कुछ महिलाओं का दम घुटने लगा और वह नीचे गिरने लगी, जिससे भगदड़ और बढ़ गई और चीख पुकार मचने लगी। घटनास्थल का वह मंजर बड़ा ही भयावह था। वास्तव में,भगदड़ भीड़ प्रबंधन की असफलता या अभाव की स्थिति में पैदा हुई मानव निर्मित आपदा है। अक्सर भगदड़ किसी अफवाह के कारण पैदा होती है और भगदड़ में लोग दिशाहीन होकर इधर-उधर भागने लगते हैं, जिसके परिणामस्वरूप दम घुटने व कुचलने से चोटिल होने एवं मृत्यु की घटनाएँ होती हैं। अक्सर भगदड़ मचने के पीछे जो कारण निहित होते हैं उनमें क्रमशः मनोरंजन कार्यक्रम, एस्केलेटर और मूविंग वॉकवे, खाद्य वितरण, जुलूस, प्राकृतिक आपदाएँ, धार्मिक आयोजन, धार्मिक/अन्य आयोजनों के दौरान आग लगने की घटनाएँ, दंगे, खेल आयोजन, मौसम संबंधी घटनाएँ आदि शामिल होते हैं। बैरिकेड्स, अवरोध, अस्थायी पुल, अस्थायी संरचनाएँ और पुल की रेलिंग का गिरना, दुर्गम क्षेत्र (पहाड़ियों की चोटी पर स्थित धार्मिक स्थल जहाँ पहुँचना मुश्किल है), फिसलन युक्त या कीचड़ युक्त मार्ग, संकरी गलियाँ एवं संकरी सीढ़ियाँ, खराब सुरक्षा रेलिंग, कम रोशनी वाली सीढ़ियाँ, बिना खिड़की वाली संरचना, संकीर्ण एवं बहुत कम प्रवेश या निकास स्थान, आपातकालीन निकास का अभाव भी बहुत बार भगदड़ के कारण बन सकते हैं। अप्रभावी भीड़ प्रबंधन तो भगदड़ मचने का कारण है ही। बहुत बार यह देखा जाता है कि किसी एक प्रमुख निकास मार्ग पर ही लोगों की निर्भरता होती है ,जो भगदड़ का कारण बन जाती है। आज अक्सर यह भी देखने को मिलता है कि किसी कार्यक्रम विशेष के लिए क्षमता से अधिक लोगों को अनुमति दे दी जाती है। बहुत से स्थानों पर उचित सार्वजनिक संबोधन प्रणाली का भी अभाव होता है, जिससे सूचना देने में दिक्कत आती है। भीड़ अनेक बार गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार अपनाती है और सुरक्षा नियमों का ठीक से पालन नहीं करती है। आग या बिजली का प्रसार भी अनेक बार भगदड़ मचने का कारण बन सकता है।

शख्सियत | बढ़ता राजस्थान

अमित जैन
(युवा उद्योगपति व रोटेरियन)

नमस्कार साथियों हमारी आज की शख्सियत कलिम के स्टार हैं युवा उद्योगपति व रोटेरियन अमित जैन। 9 मार्च सन 1990 को अलवर में जन्में अमित युवा उद्योगपति व समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं।

अलवर से रोजुएशन और सीए इंटर करने के बाद खुद का बिजनेस अंगद ब्रांड से सरसों का तेल पैकिंग के बाद पिछले 7 साल से अद्धानी विल्मर के लिए ऑयल पैक बनाने के लिए काम कर रहे हैं। 2020 में रोटरी जॉइन किया और समाजिक सेवा के क्षेत्र में शामिल हुए। 2023-2024 में ये रोटरी क्लब ऑफ अलवर फोर्ट के सचिव और 2024-2025 में कोषाध्यक्ष हैं। रोटरी क्लब में रहकर काफ़ी काम किये इन्होनें। कई संस्थाओं को जरुरत का सामान दिया गया। स्कूल और अनाथाश्रम में पोशाक वितरण कार्यक्रम कर बच्चों को सम्मान दिया। भीषण गर्मी में क्लब की ओर से पानी के टैंकरों की मदद से लोगों को पानी पिलाने का पुनित कार्य किया गया। उन्होंने बताया कि इस साल गर्मी में 2 महीने का पानी के टैंकर सप्लाई की जाएगी। रोटरी क्लब के एसटीएच के साथ मिलकर 2 साल में 3000 पेड़ लगाए गए। पिछले 2 साल से विजन संस्था बिजली के घर के साथ भी अमित जुडे हुए हैं। बहुत ही होनहार युवा हैं हर समय लोगों की मदद के लिए तत्पर और तैयार रहते हैं। दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम इनक उज्जवल भविष्य की कामना करती है।

रूपक शर्मा

2025_030 | बढ़ता राजस्थान

Sudoku

	5	7	2	6	3	4		
6	4	8			5			
			7	8				
	1		5		9		7	6
5	7	6		3	2			4
8		4			1		5	3
7	6	1	3					9
4			1		7	6	3	2
	3		4			7		1

Ans_2025_029

8	2	7	5	1	4	9	3	6
5	6	9	3	8	2	1	4	7
4	3	1	7	6	9	8	5	2
1	7	8	4	3	6	2	9	5
9	4	2	8	5	7	6	1	3
6	5	3	9	2	1	7	8	4
3	8	6	1	7	5	4	2	9
2	9	5	6	4	8	3	7	1
7	1	4	2	9	3	5	6	8

कैसे खेलें

वर्ग को 1 से 9 तक अंकों से ऐसे भरे कि आड़ी व खड़ी पंक्ति के साथ ही 3 गुणा 3 के बॉक्स में 1 से 9 तक अंक आएं। कोई अंक दुबारा नहीं आए।

स्वामित्वधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कान्तेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,इंडस्ट्रियल रोड खण्डवा,निवाई टोंक (राज.) से मुद्रित एवं 185/ 116 "प्रतिष्ठा" सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-तनुजा पठारे*। प्रधान संपादक-सह वित्तीय विजयवर्गीय मो.नं. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन नं.0141-2796794,795 टोंक कार्यालय-बाईपास निवाई, टोंक मो.नं.9414823448 अलवर कार्यालय-नेहाल सिंह का नोहरा,अलवर मो.नं. 7733000123,कोटा कार्यालय-छावनी मेन रोड,कोटा मो.नं.7023350734 । ई मेल-badhatarajasthan@yahoo.com *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार

राष्ट्रीय सहारा
पटना • शुक्रवार • 31 जनवरी • 2025
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

आलसी सुखी नहीं हो सकता, निद्रालु ज्ञानी नहीं हो सकता, ममत्व रखनेवाला वैराग्यवान नहीं हो सकता और हिंसक दयालु नहीं हो सकता
-भगवान महावीर

हिन्दुत्व के मोर्चे पर कांग्रेस

राजनीति

नवल किशोर कुमार

सियासत चाहे वह भारत की हो या फिर किसी और देश की, वह देश में रहने वालों के सापेक्ष ही होती है। भारत में विविध धर्मों और पंथों के लोग रहते हैं और यह बात किसी से भी छिपी नहीं है कि यहां की सियासत में धर्म का उपयोग होता रहा है। धर्म आधारित सियासत के कारण ही 1947 में देश का विभाजन हुआ और भारत तथा पाकिस्तान विश्व के नक्शे पर दो राष्ट्र के रूप में उभरे। लेकिन भारतीय संविधान का आधार धर्मनिरपेक्षता है, जिसकी नजर में सभी धर्म व पंथ एक समान हैं।

वस्तुतः यह बात सही भी है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इस देश में धर्म के आधार पर राजनीति ब्रिटिशकाल से जारी है। पहले समाज सुधार आंदोलनों के तहत 1875 में आर्य समाज की स्थापना और बाद में 1906 में मुस्लिम लीग का गठन। यह सियासत तब और जोर पकड़ने लगी जब 1925 में महाराष्ट्र के नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। आजादी के बाद भी धर्म की घुसपैठ लोकतांत्रिक सियासत में बनी रही। हालांकि प्रारंभिक दौर में इसके प्रभाव कम दिखते थे, लेकिन 1980 के दशक के बाद से इसका प्रभाव रोज-ब-रोज बढ़ता जा रहा है। मौजूदा सच्चाई यह है कि आज हिन्दुत्व का एजेंडा सियासत के केंद्र में है। निश्चित तौर पर इसके लिए भाजपा जिम्मेदार है, लेकिन कांग्रेस की भूमिका भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं रही है। आज की पीढ़ी भले ही शाहबानो केस के बारे में नहीं जानती हो, लेकिन सत्य तो यही है कि राजीव गांधी के कार्यकाल के समय से ही कांग्रेस नरम हिन्दुत्व की पक्षधर रही है। हालांकि उसने खुलकर हिन्दुत्व का पक्ष नहीं लिया है। लिहाजा उसकी विरोधी उसके ऊपर तुष्टिकरण का आरोप लगाती रही है।

बीते 27 जनवरी, 2024 को मध्य प्रदेश के महू-जो कि डॉ. भीमराव अंबेडकर का जन्मस्थान है-वहां एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा नेताओं के द्वारा प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के मौके पर स्नान करने पर कटाक्ष किया कि स्नान करने से क्या गरीबी दूर हो सकती है? उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा के नेतागण केवल फोटो खिंचवाने के लिए ऐसा करते हैं। हालांकि खरगे ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि उनके बयान से यदि किसी को किसी प्रकार का ठेस पहुंची हो तो वह इसके लिए माफी मांगते हैं, लेकिन सियासत में बयानों का महत्त्व वही होता है जो धनुष से निकले तीर का होता है।

भाजपा के नेताओं ने खरगे के बयान की आलोचना की और उनके बयान को सनातन धर्म के अपमान से जोड़ा। इस मामले में कांग्रेस को भी एक तरह से बैकफुट पर जाना पड़ा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को मल्लिकार्जुन खरगे के बचाव में आना पड़ा और उन्हें यह कहना पड़ा कि यह सनातन धर्म का अपमान कैसे हो सकता है? सनातन धर्म कहता है कि राजा को हमेशा अपने जन के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए।

धर्म के बहाने वे बेरोजगारी को बढ़ावा नहीं दे सकते और कानून-व्यवस्था को बर्बाद नहीं कर सकते। उन्हें 'धर्म' पर किताबें पढ़ने और फिर दूसरों को सनातन धर्म का उपदेश देने की जरूरत है। सवाल यह है कि जब देश में धर्म आधारित सियासत का दौर जोरों पर है, तब खरगे के बयान का निहितार्थ क्या है? यह सवाल इसलिए भी कि इंडिया गठबंधन, जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही है, के एक घटक दल समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी महाकुंभ में स्नान करते व खरगे के शब्दों में फोटो खिंचवाते नजर आए। दरअसल, हिन्दुत्व के मामले में भाजपा कांग्रेस की तुलना में अधिक सफल है और यह मानने से किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस यदि भाजपा को हिन्दुत्व के मोर्चे पर घेरेगी तो उसे असफलता ही हाथ लगेगी। पूर्व में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी द्वारा अपना जनेऊ दिखाया जाना एक सुस्पष्ट उदाहरण है। इसलिए भी कांग्रेस सामान्य तौर हिन्दुत्व के सवाल पर भाजपा से टकराना नहीं चाहती है। इसके बदले कांग्रेस ने देश में सामाजिक न्याय के मसले को उठाना शुरू किया है

दरअसल, हिन्दुत्व के मामले में भाजपा कांग्रेस की तुलना में अधिक सफल है और यह मानने से किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस यदि भाजपा को हिन्दुत्व के मोर्चे पर घेरेगी तो उसे असफलता ही हाथ लगेगी। पूर्व में राहुल द्वारा अपना जनेऊ दिखाया जाना एक सुस्पष्ट उदाहरण है। इसलिए भी कांग्रेस सामान्य तौर हिन्दुत्व के सवाल पर भाजपा से टकराना नहीं चाहती है। इसके बदले कांग्रेस ने देश में सामाजिक न्याय के मसले को उठाना शुरू किया है

लहरहाल, कांग्रेस को अपनी लाइन और लेंथ स्पष्ट रखनी होगी कि वह सामाजिक न्याय के मसले पर अपनी सियासत को आगे बढ़ाएगी या फिर हिन्दुत्व के सवाल पर। एक साथ दोनों मोर्चों पर भाजपा के साथ लड़ने में उसे केवल हार का सामना करना पड़ेगा। ताजा प्रकरण से यह बात स्पष्ट भी हो जाती है, लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि कांग्रेस हिन्दुत्व के भाजपा के नैरेटिव का तोड़ कैसे खोज सकेगी, यदि वह स्वयं हिन्दुत्व के सवाल पर भाजपा को चुनौती देगी? वजह यह कि अब भाजपा देश में सबसे मजबूत पार्टी है और कांग्रेस को कई राज्यों में अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। वैसे भी 1980 के दशक में कांग्रेस की तरफ से राजीव गांधी ने जो किया, उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा है कि आज इस देश के अल्पसंख्यक भी पूरी तरह से उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। दूसरी ओर भाजपा ने हिन्दुत्व के एजेंडे के सहारे ही ओबीसी और दलितों में अपनी पैठ को व्यापक कर लिया है।

(लेख में विचार निजी हैं)

अहर्निशा

डॉ. ज्ञानानंददास स्वामी

प्राचीन समय में लाहौर के राजमार्ग पर एक संत चल रहे थे। उसी समय सामने से कुछ लोग एक मृत व्यक्ति को अंतिम क्रिया के लिए ले जा रहे थे। लोग अर्थी को कंधा देते हुए जोर से 'राम नाम सत्य' बोलते हुए निकल रहे थे। संत ने पूछा, 'इस आदमी को कहां ले जा रहे हो?' 'दाह संस्कार के लिए', लोगों ने उत्तर दिया। संत ने पूछा, 'तुम सब राम का नाम ले रहे हो, भजन कर रहे हो, लेकिन जो ऊपर सो रहा है वह तो कुछ बोल नहीं रहा?' एक व्यक्ति ने कहा, 'अरे! देखते नहीं वह हमेशा के लिए सो चुका है। वह आदमी भजन थोड़े ही कर सकता है?' संत कहते हैं, 'तो जो भजन नहीं करता, वह हमेशा के लिए सोया कहलाता है?' संत का यह वचन बड़ा ही मार्मिक था। सब में जीवन ही शक्ति है, सारे आध्यात्मिक साधन जीवित व्यक्ति ही कर सकता है। किंतु यह बात समझते-समझते काफी देर हो जाती है। इस क्षेत्र में अभी हम जाग्रत नहीं हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो हम अभी सो रहे हैं। गीता में इसे निशा यानी रात्रि कहा है। यदि हम अपनी दैनिक क्रिया पर नजर डालेंगे तो लगेगा कि हम प्रायः दिन-रात खाने-पीने में, सुख-आराम में, भोग-विलास और पदार्थ संचय में तथा धन कमाने में ही लगे रहते हैं। किंतु भगवान ने मनुष्य में वह विवेकशक्ति दी है। वह जाग्रत हो सकता है, जिससे वह अपना कल्याण कर सके और ईश्वर को प्राप्त कर सके, परंतु मनुष्य उस विवेकशक्ति का दुरुपयोग करके वस्तुओं और विषयों का संग्रह और उपभोग करता रहता है। धन का हिसाब रखना, जमीन की एक-एक इंच का हिसाब रखना, केवल अपने स्वार्थ और सामर्थ्य के बारे में सोचना, मान-सम्मान आदि पाने की अदम्य लालसा रखना, इसमें बहुत लोग सतर्क रहते हैं। इसलिए गीता में कहा गया है कि वे लोग अध्यात्म के मार्ग में सोते हैं और सांसारिक मार्ग में जागते हैं। दूसरी ओर, महंत स्वामी महाराज कहते हैं-जो सज्जन मनुष्य सद्पाचार के मार्ग पर चल रहे हैं, जिनका लक्ष्य केवल आत्म कल्याण ही है, जिन्होंने इंद्रियों और मन को वश में कर लिया है और वह वस्तुओं के ग्रहण या संग्रह में आसक्त नहीं हैं। इसके विपरीत वे सभी सांसारिक वस्तुएं जिन्हें प्राप्त करने और संग्रह करने में मनुष्य स्वयं को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, उन सभी को अभी निशा ने आवृत्त कर लिया है। अब हमें सोचना है क्या अभी जागने का समय नहीं आया?

दूर की सोचें राहुल

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों के प्रति अब समान रूप से हमलावर हो गए हैं। दिल्ली में एक चुनाव सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने साफ-सुथरी राजनीति की बात की थी, लेकिन उनकी सरकार में सबसे बड़ा शराब घोटाला (आबकारी घोटाला) हो गया और वह 'शीश महल' में रहने लगे। इसी तरह उन्होंने भाजपा, मोदी और आरएसएस पर एक बार फिर देश में नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया। सच तो यह कि राहुल गांधी को अपनी नीतियों को लेकर स्पष्ट होना चाहिए और यह समझ बनानी चाहिए कि उन्हें कब किसका और किस मुद्दे पर विरोध करना है। केजरीवाल पर

उनका हमला लगभग वैसा ही है, जैसा भाजपा के होते हैं। तो क्या यह माना जाना चाहिए कि जो भाजपा का शत्रु है वह राहुल गांधी का भी शत्रु है। यह हास्यास्पद स्थिति है कि केजरीवाल के मामले में राहुल गांधी भाजपा की लाइन ले रहे हैं। जब केजरीवाल जेल में थे तो वह उनकी रिहाई की मांग कर रहे थे और जब दिल्ली के चुनाव में उनकी पार्टी के साथ गठबंधन या समझौता नहीं हुआ तो उन पर तीखा हमला कर रहे हैं। अब राहुल गांधी को यह तय करना चाहिए कि ऐसा करके वह किसको फायदा पहुंचा रहे हैं और किसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि अब उनकी मोहब्बत की दुकान वाला जुमला अर्थहीन हो चुका है। जब उनकी मोहब्बत की दुकान उनके गठबंधन 'इंडिया' यानी विपक्षी दलों के गठबंधन के साझेदारी को ही मोहब्बत नहीं दे पा रही है तो बाकी किसे देगी। शायद उनकी मोहब्बत सिर्फ उनके लिए है जो आंख मूंदकर उनके साथ आ जाए और जो उनका अपना ही क्यों ना हो, अगर उनके विरोध में आता है तो वहां उनकी मोहब्बत की दुकान बंद हो जाती है। दरअसल, जरूरत इस बात की है कि कांग्रेस अपने छोटे-छोटे दली स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एजेंडा तैयार करे और उसी के अनुसार अपने राजनीतिक दोस्त और दुश्मन को तय करे। अन्यथा इस समय राहुल गांधी जो कर रहे हैं उससे उनके दोस्त भी दुश्मन होते चले जाएंगे और इसकी भारी कीमत उनकी पार्टी कांग्रेस को चुकानी पड़ेगी?

तकनीक विरोधी तर्क

देश के किसी भी राज्य की पुलिस व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा किसी आरोपी को नोटिस नहीं भेज सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए पुलिस को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 41ए (भारतीय सुरक्षा संहिता की धारा35) को लेकर आदेश दिया। अदालत ने राज्य सरकारों को स्थाई आदेश जारी करने का आदेश दिया। उन्हें सीआरपीसी या बीएनएसएस के तहत सेवा के निर्धारित तरीकों के माध्यम से ही नोटिस जारी करने को कहा। हरियाणा के डीजीपी के आदेश में कहा गया था कि सीआरपीसी की धारा 41ए व बीएनएसएस की धारा35 के तहत नोटिस भौतिक रूप से या व्हाट्सएप, एसएमएस, ई-मेल व किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तामील कराये जा सकते हैं। सबसे बड़ी अदालत अपने एक फैसले में व्हाट्सएप के जरिए दिए नोटिस को पहले ही गलत बता चुकी है। वास्तव में व्यक्तिगत रूप से नोटिस देने में कई दफा पुलिस असफल रहती है। आरोपी

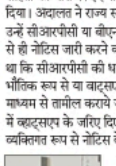

तक उसकी पहुंच न हो या वह पकड़ न आ रहा हो तो नोटिस देने में उसे कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। कई दफा पुलिस नोटिस रिहाइस में चिपकाकर इतिश्री करने की रस्म निभाती नजर आती है। आधुनिक तकनीकि और संचार माध्यमों के उपयोग को दर-किनार करना अब अव्यावहारिक नहीं ठहराया जा सकता। आज जब अपराधियों की धर-पकड़ में उनकी लोकेशन का खुलासा करने में फोन और नेट-वर्क सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से नोटिस न देने का निर्णय पुलिस के अधिकारों को सीमित करने सरीखा है। आधुनिक तकनीकि व प्रौद्योगिकी को रोजमर्रे के जीवन में आसानियां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रयोग किए जाने में कोई हर्ज नहीं। यह आवश्यक है कि नोटिस प्राप्ति की सूचना स्पष्ट तौर पर प्राप्त होने का प्रमाण पुलिस के हाथ हो ताकि उसे साक्ष्य प्राप्त करने में दिक्कत न हो। पुराने व पारंपरिक तरीकों को बदलना निसंदेह जोखिमपूर्ण हो सकता है। मगर इस भय से सुविधाओं को नित-प्रति जीवन से दूर नहीं रखा जा सकता। हालांकि पुलिस भी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने को कम बदनाम नहीं है। वह रसमादायगी के तौर पर मैसेज, व्हाट्सएप या ई-मेल कर हाथ पर हाथ रखे बैठी रह सकती है। अदालती नोटिसों से न घबराने वाले दोषियों की धर-पकड़ अंततः पुलिस का ही जिम्मा है।

कटाक्ष/ सहीराम

बोल तेरी तकदीर में क्या है

खलवली है खलवली। है खलवली। ट्रंप के आने से इधर मृत्युलोक में तो खलवली है ही। उधर स्वर्गलोक में भी खलवली है। ट्रंप के आने से घन्ना सेठों के हाथों में तो जैसे ट्रंप का इक्का ही आ गया है, लेकिन गरीब-गुरबा में खलवली है। भारतीयों में तो खुद मृत्युलोक के स्वर्ग अमरीका में ही खलवली मची है। संभावित माताएं अपने सात-आठ माह के गर्भ लेकर अस्पताल भागी जा रही हैं।

नौ महीने पूरे कर अगर बच्चा वह इस दुनिया में आया तो अमेरिका का नागरिक कैसे बनेगा। ट्रंप साहब ने पच्चीस फरवरी तक की छूट दी है। तब तक अगर बच्चा जन लिया तो वह अमेरिका का नागरिक मान लिया जाएगा, नहीं तो नहीं। तो संभावित माताएं डॉक्टरों से कह रही हैं-पच्चीस फरवरी से पहले-पहले मुझे बच्चा जनना है डॉक्टर! आप कुछ भी करो-ऑपरेशन करो, सीजेरियन करो, सुई लगाकर लेबर पेन करो। पर हमें उससे पहले-पहले बच्चा चाहिए। कोई बात नहीं अगर वह सात महीने का होगा। कोई बात नहीं अगर वह आठ महीने का होगा। पूर्ण विकसित नहीं होगा न। कोई बात नहीं। नौ महीने का पूर्ण विकसित होकर पैदा हुआ और अमेरिका का नागरिक नहीं बन पाया तो फिर उसके विकसित होने का फायदा ही क्या। आप तो बस मेरा बच्चा पैदा करवाओ। मृत्युलोक के स्वर्ग में मची इस भागमभाग, आपाधापी और अफरा-तफरी से ऊपर स्वर्गलोक में भी खलवली है। बच्चे की तकदीर लिखनेवाला विधाता परेशान है। सब समय पर ही होगा न भई। विधान भी कोई चीज है कि नहीं? नहीं-नहीं, यह गड़बड़झाला ठीक नहीं है। इधर भारत के नजूमियों, पौथी-पत्रा देखनेवाले भविष्यवक्ताओं, समय और ग्रह नक्षत्रों की गणना करनेवाले ज्योतिषियों में भी खलवली है। वे तो अपनी सारी गणनाएं, जन्म के वक्त और स्थान से ही तो करते हैं, लेकिन अगर जन्म स्वाभाविक नहीं होगा, ममगर्जी के समय पर बच्चे पैदा होंगे तो उनके ग्रह नक्षत्रों की गणना कैसे होगी। उनके जन्म का समय और स्थान विधाता तो तय नहीं कर रहे, माता-पिता कर रहे हैं। वैसे तो सरकारें तकदीर बदलने के लिए ही बदली जाती हैं, लेकिन अमेरिका में इस बार ऐसी सरकार बदली है कि खुद दुनिया की तकदीर बांचना मुश्किल लग रहा है।

भारत में सेकेंड हैंड कार मार्केट का आकार

- भारत में सेकेंड हैंड कार मार्केट की सेल्स 2030 तक दोगुनी होकर 1.08 करोड़ यूनिट्स हो सकती है। 2023 में यह 46 लाख यूनिट्स थी, जो सालाना आधार पर 13 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर (सीएजीआर) को दर्शाती है
- कार्स24 की रिपोर्ट में बताया गया कि लीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद सेकेंड हैंड कार खरीदारों के लिए आर्थिक सुलभ और बजट अनुकूल विकल्प बनी हुई हैं, जो गुणवत्ता से समझौता किए बिना अच्छी वैल्यू प्रदान करती हैं
- रिपोर्ट के अनुसार, सेकेंड हैंड कार बाजार में फाइनेंस के जरिए खरीदी जाने वाली कारों की संख्या में भी इजाफा हुआ है

स्रोत : मीडिया इन्यूट्रस

महाकुंभ में अनियंत्रित भीड़-भगदड़ के चलते कई लोगों की मौत, अनेक घायल.अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण। मृतकों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना! देखिये, शासन 'महाकुंभ-महाप्रबंधन' पर क्या कहता है! अपन का तो कबीर, रैदास, नानक और नारायण गुरु जैसे संतों में यकीन है: 'मन चंगा तो कठौती में गंगा'!

उर्मिलेश, पत्रकार
@UrmileshJ

रीडर्स मेल

ट्रंप के उद्गार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हालिया वार्ता ने भारत-अमेरिका संबंधों को नई मजबूती प्रदान की है। ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा कि अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी जो भी कदम उठाएंगे, वही सही होगा। यह भारत की निर्णायक नीति और सशक्त नेतृत्व का प्रमाण है, जो वैश्विक मंच पर अपनी दृढ़ता और आत्मनिर्भरता को स्थापित कर रहा है। इसके अलावा, दोनों देशों ने रक्षा सहयोग को और विस्तार देने पर सहमति जताई है। अमेरिका से आधुनिक सुरक्षा उपकरणों की खरीद और हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना भारत की वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह न केवल भारत की सैन्य क्षमता को मजबूत करेगा, बल्कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा। भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक सहयोग भी नई ऊंचाइयों को छू रहा है। यह वार्ता इसका संकेत है कि भारत एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभर रहा है और आने वाले समय में विश्व व्यवस्था में अपनी प्रभावी भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

प्रो. आरके जैन 'अरिजीत', ई मेल से

बुमराह हैं बेजोड़

यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जसप्रीत बुमराह भारत की राष्ट्रीय धरोहर हैं। पिछले दो दशक में जब से यह पुरस्कार शुरू हुए हैं तब से पांच भारतीय खिलाड़ियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और बुमराह के अलावा वह हैं द्रविड़, तेंदुलकर, अश्विन और कोहली, लेकिन बुमराह पहले भारतीय तेज गेंदबाज हैं जिन्हें विश्व का सबसे श्रेष्ठ खिलाड़ी माना गया हो। आज विश्व क्रिकेट में बुमराह अपना लोहा मनवा चुके हैं और उनकी धारधार गेंदबाजी का खौफ विश्व की सभी टीमों के बल्लेबाजों के मन में रहता है। उनके ऊपर ओनिड्र टीवी का नारा बिल्कुल सटीक बैठता है 'मालिक का गौरव, पड़ोसी की ईर्ष्या, क्योंकि वह भारतीय टीम का गौरव हैं, लेकिन विपक्षी टीमें सभी ईर्ष्या करती हैं कि कैसे इस तरह के दिग्गज गेंदबाज उनके पास नहीं हैं। चूंकि बुमराह तीनों फॉर्मेट खेलते हैं और अभी वह चोटिल भी हैं तो यह बेहतर होगा कि उनका चयन सूझबूझ से हो और उन्हें हर श्रृंखला खेलने पर मजबूर न किया जाए।

बाल गोविंद, नोएडा

दिख रहे सकारात्मक रुझान

महामारी के कारण पढ़ाई में व्यवधान के बाद, ASER 2023 से देखा गया हालिया रुझान बताता है कि भारतीय स्कूली बच्चों के बुनियादी कौशल में सकारात्मक रुझान देखने को मिल रहा है। हालांकि यह इस बात पर महत्त्वपूर्ण सवाल उठाता है कि रिकवरी को कैसे टिकाऊ बनाया जाना चाहिए; क्या पाठ्यक्रम पूरा करने और बुनियादी शिक्षा के बीच के अंतर को दूर करने के लिए पर्याप्त उपाय हैं? वास्तव में, हम गति को कैसे बनाए रख सकते हैं और शिक्षण पद्धतियों को विविध कक्षा की जरूरतों के अनुसार कैसे समायोजित कर सकते हैं? नीति निर्माताओं को अब ऐसी चुनौतियों का सामना करने की जरूरत है क्योंकि वे युवाओं के लिए अधिक आशाजनक शैक्षिक भविष्य के लिए प्रयास कर रहे हैं।

अंशु भारती, बेगूसराय

letter.editorsahara@gmail.com

गांधी पुण्यतिथि

डॉ. घनश्याम बादल

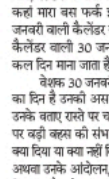

एक नहीं, हजारों बार मरे हैं गांधी

शारीरिक रूप से 30 जनवरी 1948 को गांधी की गोली से देह से आत्मा में तब्दील हो गए थे मगर सच कहें तो हम ने गांधी को उसके बाद भी एक बार नहीं बार-बार मारा है, हजार बार मारा है। देश के विभाजन के समय मारा एक लंबे कालखंड तक चले मजहबी दंगों में मारा, 1984 में मारा गोधरा में मारा, और न जाने कहां-कहां मारा बस फर्क इतना है कि इन सब दिनों में 30 जनवरी वाली कैलेंडर की तारीख नहीं थी और आज वही कैलेंडर वाली 30 जनवरी है, जिसे गांधी की हत्या का कल दिन माना जाता है।

वेशक 30 जनवरी गांधी की शहादत को नमन करने का दिन है उनकी असमय मृत्यु पर रोने का दिन है परंतु उनके बताए रास्ते पर चलने के संकल्प दिन है या नहीं इस पर बड़ी बहस की संभावना आज भी है। गांधी ने देश को क्या दिया या क्या नहीं दिया? या गांधी देश के लिए क्या थे, अथवा उनके आंदोलन, कार्य, सिद्धांत, जीवन शैली, उनके लिए गए फैसले, भारत विभाजन पर उनकी जिद, मुस्लिमों को इस देश में रहने देने की जिद, उस पर भी पाकिस्तान को 200 करोड़ रुपये और एक बड़ा भू-भाग देने पर कई बड़े नेताओं से अलग सोच व राय ही नहीं अपितु अपनी ही मनमर्जी करना मत मतांतर का विषय हो सकता है। उनके अनुयायियों व विरोधियों में कमोबेश इन मुद्दों पर गांधी के जीते जी ही तलवारें नहीं खिंचती रही वरन उनके जाने के बाद भी खिंचती रही हैं और हो सकता है तब तक खिंची रहे जब तक गांधी का नाम इस देश व दुनिया में रहेगा। अपने लंबे राजनैतिक जीवन में गांधी ने कितना सही या कितना गलत किया इस पर बहस या चिंतन करना गलत भले ही न हो पर उनकी पुण्य तिथि पर शायद यह उचित न हो। आज उनके जाने के बाद यदि गोडसे जैसे हत्यारे के नाम पर कुछ लोग जो राजनीति करते रहे हैं वह बेहद चिंता का सबब है। कोई भी कानून किसी हत्यारे को निरपराध नहीं मानेगा। आप किसी से सहमत या असमत हो सकते हैं इसका हक आप को लोकतंत्र देता है, पर हत्यारों को सम्मानित करना उसका मंदिर बनवाना, मजहब की आड़ लेकर उन्हें शहीद जैसे शब्द देना क्या है? अगर गांधी गोडसे की गोली से बच जाते बहुत संभव था कि वे उसे बचा लेते या बचाने के लिए अनशन अथवा सत्याग्रह पर बैठ जाते मगर ऐसा हुआ नहीं

और देश उनके आखिर शब्द 'हे राम' को अपना कर बैठ गया। गांधी के हत्यारे के साथ कानून को जो करना था उसने किया, अब वह किसी संघ से जुड़ा था या नहीं यह महत्त्वपूर्ण नहीं रह गया है। महत्त्वपूर्ण यह है कि क्या सरकारें बदलने के साथ राष्ट्रपिता के प्रति भाव भी बदलते रहेंगे? गांधी को विरला मंदिर में नियमित होने वाली प्रार्थना सभा में आजाद होने के महज पांच महीने 14 दिन बाद ही देश ने लाश में तब्दील होते देखा, नफरत की पौध को हरे होते देखा, आम आदमी को सचमुच ही किसी नेता की मृत्यु पर बिलख-बिलख कर रोते देखा। समय के साथ गोडसे अपनी नियति को प्राप्त हो गया, जिंदा होकर गांधी नहीं लौटे। खेद, कि वक्त ने उनके सपनों व गांधीवाद को भी मरते देखा पर आज यदि गोडसे लौटता दिख रहा है तो यह गांधी की शहादत को नमन करने पर प्रश्न तो खड़े करेगा ही। भले ही कुछ लोगों के लिए 30 जनवरी गांधी के मरने पर रोने का दिन न हो पर उनके आदर्शों की लगातार हो रही हत्या पर रोने का दिन तो है ही। गांधी को तब मारा गया जब साहा जमाना, उन्हें गौर से सुन रहा था, आईंस्टीन जैसे चिंतक उन्हें एक चमत्कार बता रहे थे, देश को उनके नेतृत्व की जरूरत थी, पर गोलियों की धांय...धांय...धांय... की तीन आवाजों के साथ 'हे राम...' कह कर वे शांत हो गए। चारों तरफ कोहराम, मच गया, उन घरों में भी कई दिन चूल्हा नहीं जला जिन्होंने गांधी जी को कभी देखा सुना तक न था, यह थी गांधी के मरने के गम की आम जन की अभिव्यक्ति। 'आजादी का भगवान' देश के लिए प्रार्थना करने के लिए आया था, सबके लिए 'सबको सन्मति दे भगवान...' का तराना गाने' आया था। जिसे देश ने 'बापू' कहा था, दुनिया ने 'महात्मा' बताया था, हमारी छोटी सोच के चलते बीसवीं सदी का चमत्कार कहे जाने वाला, वह महानायक हमने अपने हाथों ही मार डाला था आज के दिन।

यही है 30 जनवरी पर रोने का सबब। गांधी आम आदमी के लिए पूज्य थे और आज भी हैं। गांधी की महात्मा होने की छवि हमेशा जस की तस आगे भी बनी रहेगी। भले ही कुछ खास लोग गोडसे से कहलवाते रहे 'मैंने गांधी का वध किया है।' आज भी दुनिया गांधी से ऊर्जा लेकर, किसी समस्या का अहिंसापूर्वक, विरोधी को अपनी बातों व विचारों से प्रभावित करके, आपस में बातचीत करके हल ढूंढती दिख रही है यही है गांधी के गांधी होने का अद्भुत रहस्य। वे बेखौफ जिये, निस्पृह रहे, जो करना था करते रहे। इसी आत्मबल ने गांधी को महात्मा बनाया। हमें आजादी दिलवाई। पर हमने गोडसे गढ़े, नफरत पाली मजहब, राजनीति, वोट व आदमी का घालमेल कर उन्हें शूट कर दिया इसी शर्मनाक शूटआउट पर रोने का दिन है आज।

बोल तेरी तकदीर में क्या है

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया काज़मी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन द्वारा हिन्दुस्तान नोटिया कैम्पर्स लिमिटेड प्रेस, गौरव-दरियापुर, पुलिस स्टेशन-शहतूश, दानापुर, पटना से मुद्रित तथा चतुर्थ तल, सहारा इंडिया विहार, बोरिंग रोड क्रासिंग, पटना से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - संजय त्रिपाठी *।
पटना कार्यालय- 3911448/417/454/422, फैक्स : 2535935,2520760 विज्ञापन-3911455/434, प्रसार- 3911451/428
वर्ष - 19, अंक 6554
आर.एन.आई. नं. बीआईएचएआईएन/2006/18082 Postal Reg. No. : R-10/NP-50/06-07
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु उत्तरदायी

दैनिक जागरण
सार्थक चर्चा ज्ञान के आदान-प्रदान का माध्यम है

हंगामा न हो

संसद के बजट सत्र को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में हुई चर्चा को संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू ने बहुत रचनात्मक बताया, लेकिन यह कहना कठिन है कि इस सत्र के दौरान संसद की कार्यवाही रचनात्मक ही रहेगी। यह कहना इसलिए कठिन है, क्योंकि अब संसद में किसी न किसी बहाने हंगामा ही अधिक होता है। विपक्ष अपनी ओर से महत्वपूर्ण माने जाने वाले जन विषयों को उठाने पर जोर देता है, उन पर सार्थक विचार-विमर्श में कम ही रुचि दिखाता है। पता नहीं क्यों और कैसे यह मान लिया गया है कि किसी मसले पर हंगामा करने मात्र से उस पर चर्चा का उद्देश्य पूरा हो जाता है? किसी मुद्दे पर हंगामा करने से वह सतह पर अवश्य आ जाता है, लेकिन देश की जनता को यह पता नहीं चल पाता कि राजनीतिक दल उसे किस तरह सुलझाना चाहते हैं? सार्थक चर्चा के अभाव में देश को कोई दिशा नहीं मिल पाती। उसे बस ऐसी खबरें मिलती हैं कि संसद में हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई, सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने यह स्पष्ट किया कि वह महाकुंभ में हुई भगदड़ पर चर्चा को प्राथमिकता देगा। इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन क्या इससे यह संकेत नहीं मिलता कि उसने अपने स्तर पर राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों की तलाश नहीं की?

यह ठीक है कि विपक्षी नेताओं ने यह भी कहा कि वे महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे भी उठाएंगे, लेकिन ये तो वे विषय हैं, जिन्हें लेकर सदैव सरकार को घेरने की कोशिश की जाती है। विडंबना यह है कि इन मुद्दों पर भी घिसे-पिटे विचार प्रकट किए जाते हैं। यह तय माना जाना चाहिए कि बजट चाहे जैसा हो, विपक्ष उसे सिरे से खारिज करते हुए यही कहेगा कि वह किसी काम का नहीं और उसमें किसानों, नौजवानों, महिलाओं आदि के लिए कुछ भी नहीं। इस तरह की प्रतिक्रियाएं विपक्ष की विचारशून्यता का ही परिचायक होती हैं। अच्छा हो कि इस पर गंभीरता से विचार किया जाए कि महंगाई, बेरोजगारी आदि के साथ संसद का सही तरह न चलना भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यदि संसद सही तरह नहीं चलेगी और जन मुद्दे उठाने के नाम पर हंगामा अधिक होगा तो फिर जनाकांक्षाओं के इस सर्वोच्च मंच की महत्ता और गरिमा ही कम होगी। संसद में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा कैसे हो, इसके लिए विपक्ष के साथ-साथ सत्तापक्ष को भी तत्परता दिखानी होगी। इसलिए दिखानी होगी, ताकि बजट के साथ-साथ संसद के इस सत्र में वक्फ एवं एक साथ चुनाव समेत जो अन्य महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाने हैं, उन पर सचमुच गंभीर चर्चा हो सके। विपक्ष को यह शिकायत करने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए कि उसे अपनी बात नहीं कहने दी जा रही है।

नई ऊर्जा

झारखंड सरकार ने भारतीय महिला हाकी टीम की कप्तान और ओलिंपियन सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को राजधानी रांची के हरमू में जमीन आवंटित किया है। साथ ही इस पर भवन बनाने के लिए 35-35 लाख रुपये के अनुदान भी दिए हैं। खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में यह सराहनीय पहल है। खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को और बेहतर बना सकें और राज्य का गौरव बढ़ा सकें, उन्हें समय-समय पर सम्मानित करना सरकार का सही कदम है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से 'मंडल लाओ-नौकरी पाओ' योजना भी चलाई जा रही है, जिसके तहत अच्छे प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को नौकरी दी जा रही है। ऐसे सम्मान खासकर खिलाड़ियों को नई पीढ़ी को ऊर्जा देने का काम करेंगे। उन्हें खेल की दिशा में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेंगे। हालांकि सम्मान के साथ-साथ राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के अंतरराष्ट्रीय मानकों की तरह खेल सुविधाएं भी विकसित की जानी चाहिए। इसके अलावा राज्य के सभी जिला और प्रखंड स्तर पर खेल स्टेडियम की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराई जानी चाहिए। आज कई राज्य अपने खिलाड़ियों के लिए नई खेल नीति लाकर उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। राज्य सरकार को इस दिशा में गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए। कई मामलों में राज्य के खिलाड़ियों को अपेक्षित आधारभूत संरचनाएं नहीं मिल पाने के कारण वे प्रतिस्पर्द्धा में पिछड़ जाते हैं। शासन-प्रशासन को इस मामले में गंभीर होना होगा।

खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में यह सरकार का सराहनीय कदम है

वैचारिक संघर्ष की दशा-दिशा

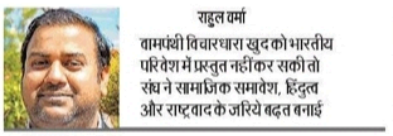

राहुल वर्मा

वामपंथी विचारधारा खुद को भारतीय परिवेश में प्रस्तुत नहीं कर सकी तो संघ ने सामाजिक समावेश, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के जरिये बढ़त बनाई

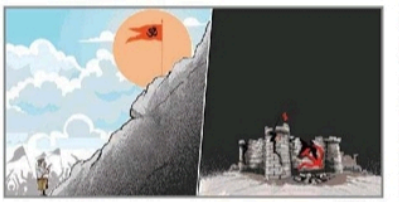

अशोक राजपूत

यह साल भारत के लिए गहरे निहितार्थ लिए हुए है। बीते दिनों ही भारत ने अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाया है। इसे साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के सौ वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी भाकपा भी इसी साल अपना सौवां स्थापना दिवस मनाएगी। यह भी एक बड़ा संयोग है कि भारतीय सामाजिक-राजनीतिक विमर्श में वैचारिक स्तर पर दो विपरीत ध्रुवों पर खड़े संघ और कम्युनिस्ट दल इसी साल अपने सौवें पड़ाव से गुजरेंगे। ऐसे में उनकी अभी तक की यात्रा और भावी दशा-दिशा के प्रति उत्सुकता बहुत स्वाभाविक है। बर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की चर्चा करें तो संघ से संबद्ध मानी जाने वाली भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा इस समय शीर्ष पर है तो कम्युनिस्ट आंदोलन निरंतर विखंडन के बाद पूरी तरह हाशिए पर पहुंच चुका है। भारतीय राजनीतिक विमर्श में भाजपा दक्षिणपंथ, कम्युनिस्ट वामपंथ तो कांग्रेस मोटे तौर पर वामपंथी झुकाव के बावजूद मध्यमार्गी पार्टी ही मानी गई है। भाजपा के मौजूदा वर्चस्व को देखते हुए यही प्रतीत होता है कि उसकी वैचारिक धारा समय के साथ भारतीय राजनीति पर अपनी पैठ मजबूत करती गई, जबकि खांटी वामपंथी कम्युनिस्ट और वाम झुकाव वाली कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते दिख रहे हैं।

विचारधाराओं के संघर्ष की पृष्ठभूमि के एक पड़ाव की जड़ें स्वतंत्रता पूर्व के दौर से जुड़ी हैं तो उसका अगला विस्तार आजादी के बाद होता है। भाकपा दिसंबर 1925 के दौरान अस्तित्व में आई। वामपंथी खेमे में आरंभ से ही टकराव के कई मोर्चे खुले दिखे। इसमें सत्ता प्राप्ति के लिए रार चुनने से लेकर संविधान सभा में सहभागिता के मुद्दे पर कायम मतभेद प्रमुख बिंदु रहे। चीन और रूस के समर्थन के मुद्दे ने भी आंतरिक धड़ों के बीच ऐसा पेच फंसाया जो अंदरूनी विभाजन का आधार बना। परिणामस्वरूप, भाकपा से ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-मार्क्सवादी यानी माकपा निकली। अलग-अलग रह चुनने के बावजूद वैचारिक गोंद ने दोनों धड़ों को जोड़े रखा और उनके गठजोड़ ने केरल, बंगाल और त्रिपुरा में अपना राजनीतिक वर्चस्व बनाए रखा। माओवादी हिंसक धारा भी कुछ हिस्सों में अपनी जड़ें जमाने में सफल रही। हालांकि अब स्थिति यह है कि बंगाल और त्रिपुरा से इन दलों का लगभग सफाया हो चुका है। केवल केरल में ही उनकी राजनीतिक जमीन बची है। वहीं, हिंसक माओवादियों की स्थानीय जनता पर पकड़ कमजोर हुई है तो सुरक्षा एजेंसियों के अभियानों ने भी उन्हें खासा नुकसान पहुंचाया है। समय के साथ खुद को बदल पाने में नाकाम रहना भारत में वामपंथ का दायरा सिकुड़ने की बड़ी वजह रही।

आजादी से पहले के दौर की बात करें तो उसी दौरान मुस्लिमों को लामबंद करने के लिए बनी मुस्लिम लीग का लक्ष्य तो भारत विभाजन के सच को पूरा हो गया था। लीग के इक्का-दुक्का अवशेष जरूर कुछ इलाकों तक सक्रिय रह गए हैं। पंजाब में पंथिक राजनीति के रूप में शुरू हुए अकाली दल में विभाजन होते गए और प्रमुख अकाली पार्टी-शिरोमणि अकाली दल अपने पुरोधा प्रकाश सिंह बादल के निधन के बाद पंजाब में खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। अकाली दल के अन्य धड़ों की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं। दलितों की गोलबंदी के लिए डा. भीमराव आंबेडकर का रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया यानी आरपीआइ के रूप में किया गया राजनीतिक प्रयोग भी सफल नहीं रहा। वहीं, तमिलनाडु में 1920 के दौरान पेरियार के नेतृत्व में गति पकड़ने वाले आंदोलन ने द्रविड़ कषगम यानी डीके के रूप में राजनीतिक चोला पहना। डीके से ही डीएमके, एआइएडीएमके और एमडीएमके जैसी अन्य द्रविड़ राजनीतिक धाराएं निकलीं जो आज भी परस्पर संघर्षरत हैं। तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का वर्चस्व होने के बावजूद इन धड़ों में वैचारिक टकराव जारी है।

जहां ये विचारधाराएं समय के साथ संकुचित और विखंडित होती गईं तो दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छत्र तले दक्षिणपंथी विचारधारा निरंतर फलती-फूलती गई। स्वतंत्रता से पहले जहां हिंदू महासभा और अभिनव भारत जैसे हिंदुत्व के लिए समर्पित संगठन भी सक्रिय थे तो कालांतर में इस प्रकार के संगठन भी संघ की वैचारिकी में समाहित होते गए। इतना ही नहीं, आरंभ में कांग्रेस के भीतर असंतुष्ट दक्षिणपंथी नेता भले ही संघ से जुड़े संगठनों का सीधा हिस्सा न बने हों, लेकिन उन्होंने संघ परिवार से गलबहियां करने में कोई संकोच नहीं किया। जनसंघ के रूप में संघ का राजनीतिक प्रयोग अपेक्षित रूप से सफल नहीं रहा, लेकिन देश में पहली गैर-कांग्रेसी सरकार के गठन में जरूर उसकी अहम भूमिका रही। यहां तक कि जयप्रकाश नारायण जैसे गांधीवादी नेता को भी संघ से कोई परहेज नहीं रहा। मोरारजी देसाई और जगजीवन राम जैसे दिग्गज कांग्रेसी भी संघ के समर्थन से बनी सरकार का हिस्सा बने। जनता पार्टी के असफल प्रयोग के बाद संघ ने भाजपा के रूप में एक नई शुरुआत को समर्थन दिया और दो लोकसभा सीटों से एक समय 303 लोकसभा सीटों तक पहुंची भाजपा ने अपनी सफलता से चमत्कृत किया है। संघ के अन्य संगठन भी अपने विस्तार में सफल रहे हैं।

संकुचन-विस्तार के विरोधाभास से विपरीत विचारधाराओं की गुणवत्ता को तो स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं किया जा सकता, मगर यह अवश्य समझा जा सकता है कि इनके विकास और पिछड़ने के क्या कारण हो सकते हैं। इसमें सबसे प्रमुख कारण तो यही छिपता है कि वामपंथी विचारधारा जहां अंतरराष्ट्रीयवाद से प्रभावित होकर उसके सही भारतीय स्वरूप को सामने नहीं रख पाई तो संघ ने सामाजिक समावेश, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के जरिये आगे बढ़ने में सफलता पाई। पिछली सदी के अंतिम दशक में मंडल, मंदिर और मार्केट के रूप में देश जिस बदलाव का साक्षी बना, उन परिस्थितियों को संघ ने दूसरों के मुकाबले शायद कहीं बेहतर तरीके से भुनाया।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं स्टेट्स फार पालिसी रिसर्च में फेलो हैं)
response@jagran.com

भारत के भविष्य को आकार देने की पहल

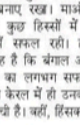

जी. किशन रेड्डी

भारत की ऊर्जा जरूरतों से लेकर खाद्य सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन एक दूरदर्शी कदम है

समय के साथ कदम मिलाने का प्रयास। प्रतीकात्मक

ढाई हजार साल से भी पहले राजस्थान के जावर में जिंक के खनन से लेकर कोहिनूर की खोज तक भारत ने लंबे समय से खदानों और खनिजों के सामरिक महत्व को समझा है। हमारे पूर्वज इस बात को भलीभांति समझते थे कि खदानें राजकोष का एक प्रमुख स्रोत हैं। खदानें देश के आर्थिक विकास, उद्योगों को बढ़ावा देने, रोजगार निर्माण, देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और वैज्ञानिक एवं तकनीकी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसे देखते हुए महत्वपूर्ण खनिजों के लिए सुधारों की एक शृंखला प्रारंभ की गई है। इसी कड़ी में 2015 में, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम में व्यापक संशोधन किए गए जिसने खनन क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी और एक पारदर्शी नीलामी व्यवस्था की शुरुआत हुई। इसके कारण 442 ब्लाकों की नीलामी पारदर्शिता से की गई और राज्यों को नीलामी प्रीमियम और रायल्टी के रूप में लगभग 2.7 लाख करोड़ रुपये का लाभ हुआ। राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की स्थापना के बाद 6,000 करोड़ रुपये का उपयोग अन्वेषण गतिविधियों में हुआ है। इसके अलावा, खनिज संपन्न जिलों में जिला खनिज निधि को एक लाख करोड़ रुपये मिले, जिनका उपयोग स्थानीय विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जनकल्याणकारी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है।

आज महत्वपूर्ण खनिज नए युग की तकनीक से प्रेरित समाज की जीवनरेखा बन गए हैं। जब देश स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत तकनीकों की ओर बढ़ रहा है, तो महत्वपूर्ण खनिजों को न्यू आयल के रूप में देखा जा रहा है। लीथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे खनिज इलेक्ट्रिक वाहनों, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों और सेमीकंडक्टर के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसी तरह, फास्फेट, पोटाश और ग्लौकोनाइट कृषि उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण हैं, जबकि टाइटेनियम और बेरिलियम एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में आवश्यक हैं। इसलिए भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता है। भविष्य की इन मांगों के प्रति व्यापक दूरदृष्टि रखते हुए 16,300 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन (राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन) की शुरुआत का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। घरेलू उत्पादन में तेजी लाने, विदेश से महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने और प्रौद्योगिकी विकास आदि पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस मिशन को आरंभ करने की घोषणा वित्त वर्ष 2024-2025 के आम बजट में की गई थी। इससे अब महत्वपूर्ण खनिजों की दीर्घकालिक सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने और भारत की महत्वपूर्ण खनिज मूल्य शृंखलाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

यह मिशन भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल करेगा, जो भावी पीढ़ी की मांगों को पूरा करने के लिए अपनी अर्थव्यवस्थाओं को रणनीतिक रूप से नया आकार दे रहे हैं। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन की दिशा में तेज गति प्रदान करेगा और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक रणनीतिक आधार तैयार करेगा। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुमानों के अनुसार, इन खनिजों की वैश्विक मांग 2030 तक तीन गुनी और 2040 तक चार गुनी हो जाएगी। वर्तमान में हमारे अधिकांश महत्वपूर्ण खनिज पूरी तरह से आयातित हैं। सरकार ने इस मिशन के जरिये इस दिशा में आत्मनिर्भरता के साथ-साथ वैश्विक बाजार में निर्यात करने का लक्ष्य रखा है। इस मिशन का लक्ष्य घरेलू स्तर पर 1,200 खनिज-समृद्ध स्थलों की खोज करना है। साथ ही बौद्धिक संपदा उत्पन्न करना भी है, जिसका लक्ष्य महत्वपूर्ण खनिज मूल्य शृंखला में 1,000 पेटेंट प्राप्त करना है। यह मिशन 100 घरेलू अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का भी समर्थन करेगा और खनन एवं प्रसंस्करण से लेकर पुनर्चक्रण तक महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले 10,000 कुशल पेशेवरों का निर्माण करेगा। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत खनिज प्रसंस्करण पार्कों, उत्कृष्टता केंद्रों और लक्षित कौशल विकास कार्यक्रमों की स्थापना यह सुनिश्चित करेगी कि भारत महत्वपूर्ण खनिज नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र बने।

वर्ष 2030 तक भारत का लक्ष्य अपनी बिजली क्षमता का 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करना और कार्बन उत्सर्जन को एक अरब टन कम करना है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लीथियम-आयन बैट्री जैसी तकनीकों के घरेलू विनिर्माण की आवश्यकता है, जिसके लिए लीथियम, निकल और कोबाल्ट की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होगी। मिशन इस अंतर को पाटने और यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है कि भारत वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा क्रांति का नेतृत्व करे न कि उसका अनुसरण रहे। कुल मिलाकर भारत का यह राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन केवल आज की चुनौतियों का जवाब नहीं है, बल्कि यह भारत के भविष्य को आकार देने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है। साथ ही यह भारत को स्वच्छ ऊर्जा के लिए वैश्विक परिवर्तन का नेतृत्व करने, हमारी विनिर्माण महत्वाकांक्षाओं को सुरक्षित और सशक्त बनाने के लिए है। यह मिशन हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देने, आर्थिक विकास सुनिश्चित करने और हमारी ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक समग्र प्रयास है।

(लेखक केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

अतिचिंता

चिंतन मस्तिष्क की स्वाभाविक क्रिया है। गर्भ में भ्रूण के निर्माण और प्राण आने के क्षण से ही मनुष्य की चेतना जागृत हो जाती है। यही चेतना उसके मस्तिष्क को सक्रिय रखती है। इसमें सतत विचारों और भावों का प्रवाह बना रहता है। जीवन है तो चिंतन अपरिहार्य है।

औसत मस्तिष्क में प्रतिदिन लगभग चौसठ हजार विचारों का आना-जाना बताया गया है। इन विचारों-भावों की प्रकृति और तीव्रता कैसी होगी, यह उन जीवन मूल्यों और धारणाओं पर निर्भर है जिन्हें हम संजोते, सहेजते रहे हैं। मस्तिष्क का स्वभाव है कि जिस विचार या भाव की इसमें प्रतिष्ठा कर देंगे, वही फल-फूल कर अपना वर्चस्व स्थापित कर देगा। अस्वस्थ विचार मन में घर कर जाएं तो उचित विचार की स्थापना दुष्कर होगी। अतः आवश्यक है कि जिस विचार को मस्तिष्क में स्थान दिया जा रहा है वह तर्कसम्मत, श्रेष्ठ और सुफल हो। मनुष्य सौभाग्यशाली है कि प्रभु ने उसे मन-मंदिर में कोई भी विचार या अभिलाषा आरोपित करने की अद्भुद सामर्थ्य प्रदान की है। श्रेष्ठ, स्वस्थ विचारों का चयन ही सुफल देता है।

कठिनाइयों से विचलित होकर अतिचिंता में डूबे रहना कुछ व्यक्तियों की मनोवृत्ति बन जाती है, जो कालांतर में उन्हीं के लिए घातक बन जाती है। वे नहीं समझते कि अधिसंख्य समस्याएं अल्पकालिक होती हैं, उतनी गंभीर नहीं होतीं जितना हम उन्हें मान लेते हैं। सामान्य कठिनाइयों को जीवन-मरण का प्रश्न न बनने दें। अत्यधिक चिंता समाधान दिलाना तो दूर, समस्या को और जटिल बना देती है, मनोबल गिराती है, ऊर्जा का ह्रास करती है। संयत, शांत रहना सीख जाएंगे तो अतिचिंता से ग्रस्त नहीं होंगे। अनावश्यक विचारों को मन से निष्कासित कर डालें, भविष्य की सुध लें। बुद्ध का संदेश है, उतनी क्षति हमें कुछ और नहीं पहुंचा सकती, जितना हमारे अपने ही अनियंत्रित विचार।

हरीश बड़थ्वाल

हिंसा सहें नहीं, प्रतिकार करें

सुनीता मिश्रा

हमारे देश में अधिकांश महिलाएं किसी न किसी रूप में विवाह के पश्चात हिंसा सहती हैं, जो कई बार हत्या में भी बदल जाती है

बीते दिनों दिल्ली हाई कोर्ट ने दहेज हत्या के एक मामले में पति को जमानत देने से इन्कार करते हुए कहा कि महिलाओं को अपने वैवाहिक घरों में कष्ट नहीं सहना चाहिए, क्योंकि इससे अपराधियों को प्रोत्साहन मिलता है। अदालत ने कहा कि 'आइपीसी की धारा 304 बी लगभग 40 वर्षों से अस्तित्व में है, फिर भी न्यायालय ऐसे मामलों से दुखी है, जिनमें महिलाओं को परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है और उनकी हत्या की जाती है। केवल इसलिए, क्योंकि उनका विवाह ऐसे परिवार में हुआ है, जो वैवाहिक संबंध के कारण अधिकार के रूप में धन और दहेज की मांग करता रहता है।'

दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के अंतर्गत दहेज लेना और देना दोनों को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसमें दहेज लेने-देने या उसमें सहयोग करने पर पांच वर्ष की कैद और 15 हजार रुपये के जुर्माने का प्रविधान है। दहेज के लिए प्रताड़ित करने पर पति और उसके रिश्तेदारों को तीन साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। यदि किसी महिला की विवाह के सात साल के भीतर असमान्य परिस्थितियों में मौत हो जाती है और यह साबित कर दिया जाता है कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, तो आइपीसी की धारा 304-बी के तहत उसके पति और आरोपित रिश्तेदारों की कम से कम सात साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। यह सत्य है कि हमारे देश में अधिकांश महिलाएं किसी न किसी रूप में विवाह के पश्चात कष्ट सहती हैं, जो कई बार हत्या में भी बदल जाती है। इन घटनाओं के बढ़ने का एक प्रमुख कारण महिलाओं को कानून की जानकारी का न होना है। जानकारी के अभाव में वे अपने साथ हो रहे दुर्व्यवहार को सहती रहती हैं। महिलाओं को इस बात को समझना होगा कि हिंसा करने वाले के साथ उसे रहने वाला भी कहीं न कहीं उतना ही अपराधी माना जाता है।

दुनियाभर में भारतीय संस्कृति की विशेष पहचान दिलाने में भारत की महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। हर परिवार में महिलाओं की भूमिका सबसे अहम होती है। सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के बावजूद कई बार उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। अगर वे नहीं होंगी, तो घर एक घर की तरह नहीं लगेगा। उनके होने से परिवार और बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं, जिनका कोई मोल नहीं है। ऐसे में हाई कोर्ट का निर्णय स्वागत योग्य है। इससे महिलाओं में जागरूकता बढ़ेगी। वे समाज के दबाव में वैवाहिक घरों में कष्ट सहने को मजबूर नहीं होंगी। वहीं, अभिभावकों में यह संदेश जाएगा कि बेटी चाहे विवाहित हो या अविवाहित उसके सुख-दुख में उसका साथ देना हर माता-पिता का कर्तव्य है। अगर ससुराल वाले उनकी बेटी के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो वे उसे नजरअंदाज न करें।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

चीनी खतरे से निपटने के उपाय

'तकनीकी क्षेत्र में चीनी वर्चस्व का खतरा' शीर्षक से लिखे आलेख में शिवकांत शर्मा चीन के तकनीकी वर्चस्व के खतरे को रेखांकित करते हुए भारत को अनुसंधान एवं विकास में निवेश बढ़ाने, स्वदेशी तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने और साइबर सुरक्षा नीतियों को सख्त करने की सलाह दे रहे हैं। चीन की तकनीकी बढ़त केवल व्यापारिक या औद्योगिक सफलता नहीं है, बल्कि यह वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित करने वाला कारक बन चुका है। 5जी नेटवर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपरकंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर उत्पादन में चीन की अग्रणी स्थिति उसे एक निर्णायक शक्ति प्रदान करती है। भारत के लिए यह स्थिति केवल एक प्रतिस्पर्धात्मक चुनौती नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक संप्रभुता से जुड़ा गंभीर विषय है। भारत की सबसे बड़ी समस्या अनुसंधान एवं विकास में निवेश की कमी और स्वदेशी तकनीकी उद्यमों को उचित समर्थन न मिल पाना है। चीन जहां अपनी जीडीपी का लगभग 2.4 प्रतिशत आरएंडडी पर खर्च करता है, वहीं भारत इस मामले में मात्र 0.7 प्रतिशत तक सीमित है। यह अंतर वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की पिछड़ी स्थिति को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, चीन ने अपने उद्योगों को सरकारी संरक्षण और सब्सिडी देकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में एक मजबूत आधार प्रदान किया है, जबकि भारत में अभी भी टेक्नोलाजी स्टार्टअप्स के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और वित्तीय सहायता की कमी बनी हुई है। तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए भारत को दीर्घकालिक नीतियों की आवश्यकता है। हमें सेमीकंडक्टर निर्माण, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा में नवाचार बढ़ाना होगा। इसके अलावा, भारत को अपनी डाटा सुरक्षा नीतियों को मजबूत करते हुए साइबर खतरों से निपटने के लिए एक संगठित रणनीति अपनानी होगी। तकनीकी वर्चस्व केवल आर्थिक समृद्धि का माध्यम नहीं, बल्कि भविष्य की भू-राजनीतिक शक्ति का आधार भी है।

awanishg30@gmail.com

मेलबाक्स

रेवड़ी बांटने की प्रवृत्ति

आजकल की राजनीति में रेवड़ी बांटने की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करना आवश्यक है। यह प्रवृत्ति न केवल हमारे लोकतंत्र को कमजोर करती है, बल्कि यह हमारे देश के भविष्य को भी खतरे में डालती है। रेवड़ी राजनीति के कारण न केवल हमारे देश और राज्य की आर्थिक स्थिति खराब होती है, बल्कि यह हमारे समाज में भी विभाजन पैदा करती है। लोगों को आकर्षित करने के लिए राजनीतिक दल विभिन्न प्रकार की योजनाएं और लाभ प्रदान करते हैं, लेकिन यह योजनाएं अक्सर अल्पकालिक लाभ प्रदान करती हैं और देश के दीर्घकालिक विकास को नजरअंदाज करती हैं। इसलिए, यह आवश्यक है कि हम अपने नेताओं से मांग करें कि वे इस प्रकार की राजनीति को त्यागें और देश के विकास पर ध्यान केंद्रित करें। हमें अपने नेताओं को यह याद दिलाना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के विकास और समृद्धि के लिए काम करना भी है।

रूपाल, फरीदाबाद

दुखद घटना

विश्व के सबसे बड़े आयोजन प्रयागराज महाकुंभ में अत्यधिक भीड़ होने के कारण जो हादसा हुआ, उसमें 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। जिससे पूरा देश भावुक होकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहा है। विपक्ष का सरकार के साथ खड़े होने की जगह राजनीतिक बयानबाजी करना उचित नहीं है। सपा के प्रमुख एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि कुंभ की व्यवस्थाओं की सच्चाई सामने आ गई है। शिवपाल यादव ने तो मुख्यमंत्री योगी का इस्तीफा ही मांग लिया है। आप नेताओं ने भी राजनीतिक तंज कसे हैं। कुंभ पर अंगुली उठाने वाले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी हादसे पर दुख जताने की जगह अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी शुरू कर दी। हादसे की वास्तविकता को समझने की कोई भी नेता कोशिश नहीं कर रहा। आगामी दिनों में ऐसी घटना न घटे, उसके लिए काम किया जाए।

ललित शंकर, गाजियाबाद

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचंद्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेंद्र मोहन, पूर्व एमडी-स्व. महेंद्र मोहन, प्रकाशक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेश श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

95 प्रतिशत किशोर और युवा ईश्वर में विश्वास करते हैं अमेरिका में, गैलप और बेंगेला द्वारा किए गए एक सर्वे अध्ययन के अनुसार। वहीं धार्मिक आयोजनों में भागीदारी को व्यक्ति का समाज के प्रति जोड़ने के विकास का एक महत्वपूर्ण आयाम मानता है।

ब्र. संजय वर्मा
एसोसिएट प्रोफेसर, वेनेट यूनिवर्सिटी, सेंटर नोएडा

आजकल

रील की चकाचौंध के बीच रियल दुनिया

प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ की इन दिनों देश-दुनिया में चर्चा है। देश-दुनिया से इसे डिजिटल कुंभ की संज्ञा भी दी जा रही है। वस्तुतः इस बार कुंभ के आयोजन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं अन्य उन्नत तकनीकों के उपयोग को मोबाइल और इंटरनेट से जोड़कर सुविधाजनक बना दिया गया है ताकि श्रद्धालुओं को कोई जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई न हो। ऐसे में बड़ी संख्या में युवा भी इस कुंभ से जुड़ तो रहे हैं, परंतु इंटरनेट पर रील्स के जरिये जो दिखाया जा रहा है उससे आध्यात्मिक आभा और संस्कृति पर आघात हो रहा है

प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में अब तक 25 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पुण्य डुबकी लगा ली है। यह क्रम निरंतर जारी है। उम्मीद है कि महाकुंभ की समाप्ति तक 45 करोड़ लोग पुण्य डुबकी लगाएंगे। महाकुंभ कई रूपों में चर्चा में है। इस महाकुंभ के डिजिटल स्वरूप की एक अन्य झलक मोबाइल से बनाई जा रही इंटरनेट मीडिया रील्स के रूप में मिल रही है- जिनसे इसमें शामिल होने आए साधु-संतों और विशिष्ट अतिथियों की चर्चा मिली है। इन्हीं की बदौलत युवाओं की आध्यात्मिकता का प्रसंग उठा है और आइआइटी वाले बाबा की अध्यात्म संबंधी व्याख्याओं ने लोगों का ध्यान खींचा है। इससे एक सवाल यह उठा है कि क्या ये रील्स और ये व्याख्याएं सच में युवाओं के आध्यात्मिक रुझान की सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत कर रही हैं।

निश्चय ही इसमें पहला प्रसंग आइआइटी वाले बाबा का उठता है, क्योंकि दावा है कि आइआइटी बांबे से डिग्री ले चुके और एक कंपनी में सवालाना लाखों का वेतन पाने वाले युवा संन्यासी बन गए और एक बाबा के रूप में महाकुंभ में शामिल होकर आध्यात्मिकता का नया पहलू लोगों के सामने रख रहा है। हालांकि यह तथ्य किसी को भी हैरान कर सकता है कि आखिर क्यों आइआइटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से निकला और महत्वपूर्ण पद पर काम कर रहा एक शख्स अचानक कथित सांसारिकता से विमुख हो जाता है और अध्यात्म की ओर मुड़ जाता है। कुछ लोगों को आइआइटी बाबा की वह आध्यात्मिकता प्रभावित कर रही है जिसमें वह अपने माता-पिता और गुरुओं तक को कोस रहे हैं और स्वयं को एक किस्म की मानसिक हिंसा का शिकार बता रहे हैं। हालांकि तमाम यूट्यूबरों और टीवी चैनलों को दिए गए साक्षात्कारों में आइआइटी बाबा ने असंगत सी बातें कही हैं, लेकिन साधु बने आइआइटी डिग्रीधारी जैसे पढ़े-लिखे व्यक्ति के मुंह से अध्यात्म की बातें सुनना युवाओं को खूब भा रहा है। अपनी जटिल बातों से आइआइटी बाबा भले ही लोगों को अध्यात्म की कोई सीख नहीं दे पाए हैं, लेकिन इससे युवाओं की यह जिज्ञासा सामने आ गई है कि आखिर अध्यात्म में ऐसा क्या है कि वह तमाम पढ़े-लिखे लोगों को अपनी ओर खींच लेता है। साथ ही, क्या दुनिया के युवाओं के लिए आध्यात्मिकता का वास्तव में कोई अर्थ है या फिर यह केवल रील्स बनाने जैसे एक तमाशे तक सीमित है।

दूरयों-सूचनाओं की बौछार : इंटरनेट मीडिया ने हमारी नई दुनिया में जो बड़े बदलाव किए हैं, उनमें एक परिवर्तन तो युवाओं में एकाग्रता की कमी (अटेंशन डेफिसिट) की शक्ल में किया है। मोबाइल इंटरनेट की तकनीक ने युवाओं के दिमाग को उलझाने के लिए इतनी तेज गति से दृश्यों और सूचनाओं की बौछार शुरू की है जिसमें युवाओं को हर क्षण स्वयं को व्यस्त रखने के लिए कुछ नया और रोमांचक चाहिए होता है। इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय रहने वाले आज के युवा किसी एक चीज से बड़ी जल्दी ऊब जाते हैं। वे किसी एक मुद्दे पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। उन्हें नशीले पदार्थों की तलब की तरह थोड़ी-थोड़ी देर में कुछ अप्रत्याशित और आवेगपूर्ण सामग्री (कंटेंट) की जरूरत होती है। इससे युवा दुनिया में एक नए किस्म के मनो-समाजिक विकास का चरण कायम हुआ है, जिसमें वे अपनी एक मुकम्मल पहचान बनने के संकट से जूझ रहे हैं। इसमें कभी उनके साथियों और माता-पिता की अपेक्षाओं का दबाव झेलना पड़ता है तो कभी डिजिटल स्क्रीनों पर दिख रहे वे तेजी से बदल रहे दृश्यों और सूचनाओं से तालमेल बिठाने की जरूरत महसूस होती है।

अगर युवाओं का यह व्यवहार जारी रहता है, तो यह उन्हें एक छद्म किस्म की आत्म-अस्वीकृति और आत्म-धोखे की ओर ले जा सकता है। इन दबावों में वे यह सीख नहीं पाते हैं कि स्वयं के प्रति सच्चा होना क्या होता है और अपनी कमजोरियों को व्यक्त करना व उन्हें स्वीकारते हुए कैसे आगे बढ़ा जाता है। ऐसे में वे आइआइटी बाबा के नाम से मशहूर हुए शख्स की तरह व्यक्तित्व-विकारों वाले जटिल व्यक्ति बन सकते हैं। ऐसे युवाओं में सतत चिंता और अवसाद के लक्षण विकसित हो जाते हैं। यह दशा उनके स्वाभाविक विकास, करियर, रिश्तों और उनकी सामाजिक हैसियत को प्रभावित करती है। इनसे बचाव के लिए युवाओं को एक ऐसे सुरक्षात्मक माहौल की जरूरत होती है, जिसमें उनका परिवार, दोस्त, योग शिक्षक, एक संरक्षक या आध्यात्मिक गुरु उनका सही मार्गदर्शन कर सकता है। लेकिन इस मामले में विडंबना यह है कि इसके लिए भी युवा इंटरनेट मीडिया की शरण में जा रहे हैं।

रील-प्रेरित आध्यात्मिकता का जाल : यहां यह जानना महत्वपूर्ण है कि आखिर युवाओं की रील वाली आध्यात्मिकता में फंसने से कैसे बचाया जाए। यह कैसे बताया जाए कि वह कौन सी आध्यात्मिकता है जिसको उन्हें सच में जरूरत है। इस संबंध में पहली जिज्ञासा यह है कि क्या आध्यात्मिकता वास्तव में युवाओं के लिए जरूरी है। असल में, युवा आध्यात्मिकता ईश्वर में आस्था से जुड़ी है। 'गैलप' और 'बेंजिला' द्वारा किए गए एक शोध अध्ययन में बताया गया कि अमेरिका में 95 फीसद किशोर और युवा ईश्वर में विश्वास करते हैं। सबसे दिलचस्प आंकड़े 'द प्रोजेक्ट टीन कनाडा' में मिले। अध्ययन में शामिल 60 प्रतिशत युवाओं ने आध्यात्मिकता को महत्वपूर्ण माना, जबकि 48 प्रतिशत युवाओं ने ऐसे संकेत दिए कि उनकी आध्यात्मिक जरूरतें हैं।

आध्यात्मिकता का वास्तविक अर्थ : ये अध्ययन निश्चय ही आध्यात्मिकता को लेकर युवाओं के रुझान को स्पष्ट करते हैं, लेकिन समस्या यह है कि इनमें से ज्यादातर से यह पता नहीं चलता है कि आखिर ये किस आध्यात्मिकता की बात कर रहे हैं या जिसे वे आध्यात्मिकता कह रहे हैं, क्या वास्तव में वह अवधारणा इसकी परिभाषाओं से मेल खाती है। किशोरों और युवाओं के लिए आध्यात्मिकता के अर्थ इंटरनेट मीडिया या रील-प्रेरित हैं और सतही हैं। वे जीवन के लक्ष्यों, समाज और परिवार से संबंधों के बारे में अमूर्त ढंग से सोचते हैं और ऐसे समाधानों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं जो अव्यवहारिक हैं। ऐसे युवाओं को कुछ देर सांस रोककर ध्यान में बैठ जाना ही आध्यात्मिकता लगता है। इस आध्यात्मिकता में न तो उन्हें अपने चित्त-मन को शांत करना सिखाया जाता है और न ही यह बताया जाता है कि जीवन का असली मतलब क्या है। जिंदगी के बारे में उन्हें अपने सवालों के उत्तर नहीं मिलते हैं। इसमें युवा अपनी प्राथमिकताएं तय कर सकते हैं और लक्ष्यों के साथ सटीकता से जुड़ सकते हैं। लेखक स्टीफन कोवे ने अपनी किताब 'द सेवन हैबिट्स आफ हाइली इफेक्टिव पीपल' में इसे एक लकड़हारे के उदाहरण से समझाया है। उन्होंने लिखा कि लकड़हारा पेड़ों को काटने में इतना व्यस्त रहता है कि उसके पास अपनी कुल्हाड़ी और आरी की धार को तेज करने का समय नहीं होता है। इससे भोथरी धार वाली कुल्हाड़ी या आरी से पेड़ों को काटने में अतिरिक्त श्रम और समय लगता है। इस कारण लकड़हारा अपनी क्षमता खो देता है और लक्ष्य हासिल करने में नाकाम होता है।

तीसरा कारण यह है कि आध्यात्मिकता की मदद से युवाओं के चारित्रिक गुणों का विकास होता है जो मन को शांत करते हैं। इससे व्यक्ति दयालु, विनम्र, धैर्यवान और क्षमाशील बनता है। चौथी वजह यह है कि आध्यात्मिकता की मदद से व्यक्ति अपनी सकारात्मक आत्म छवि बना पाता है। तब भलाई की हमारी भावना इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि दूसरे हमें कैसे देखते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हम स्वयं को कैसे देखते हैं। पांचवां कारण यह है कि आध्यात्मिक जागरण संबंधों को बेहतर बनाता है। इससे व्यक्ति को यह समझने में मदद मिलती है कि हम सभी में से प्रत्येक एक आत्मा है। यह समझ किसी दूसरे के बारे में कोई कठोर फैसला लेने से बचाती है। छठी वजह यह है कि इससे जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए आंतरिक शक्ति का विकास होता है। सातवीं वजह यह है कि आध्यात्मिकता हमारे जीवन को एक उच्च अर्थ और उद्देश्य देती है। सफलता बाहरी उपलब्धियों में निहित नहीं है। यह समझ विकसित होती है कि अगर किसी के पास मन की शांति, अच्छा स्वास्थ्य और परिवार और दोस्तों से सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं हैं, तो पैसे, प्रसिद्धि और ताकत से मिली सफलता बेमानी है। (डा. संजय वर्मा)

प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में प्रतिदिन पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या करोड़ तक पहुंच चुकी है। प्रेट्र

युवाओं के लिए आध्यात्मिकता क्यों आवश्यक

बहुत से लोगों का मत है कि आध्यात्मिकता को जानने, समझने और हासिल करने की एक उम्र होती है जो बुढ़ापे की ओर अग्रसर व्यक्तियों के लिए जरूरी है। जबकि सच यह है कि आध्यात्मिकता युवाओं के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है जितनी कि किसी अन्य आयु वर्ग के लिए। जबकि किशोरावस्था या युवावस्था में आध्यात्मिकता की सहज खोज का फायदा यह है कि कम उम्र में ही उन मुद्दों और तत्वों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है जो किसी के जीवन को और जिंदगी जीने के नजरिये को और बेहतर बना सकते हैं। युवाओं के लिए आध्यात्मिकता से जुड़ाव का पहला विशेष कारण यह है कि इससे युवा अपनी मानसिक क्षमताओं का सही दिशा में इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। कई बाहरी और आंतरिक दबाव झेल रहे और भय, चिंता, पछतावे, बेचैनी एवं अति-उत्साह से भरी जिंदगी में आध्यात्मिक चेतना युवाओं को सही रास्ता दिखा सकती है।

दूसरी बड़ी वजह यह है कि इससे युवा अपनी प्राथमिकताएं तय कर सकते हैं और लक्ष्यों के साथ सटीकता से जुड़ सकते हैं। लेखक स्टीफन कोवे ने अपनी किताब 'द सेवन हैबिट्स आफ हाइली इफेक्टिव पीपल' में इसे एक लकड़हारे के उदाहरण से समझाया है। उन्होंने लिखा कि लकड़हारा पेड़ों को काटने में इतना व्यस्त रहता है कि उसके पास अपनी कुल्हाड़ी और आरी की धार को तेज करने का समय नहीं होता है। इससे भोथरी धार वाली कुल्हाड़ी या आरी से पेड़ों को काटने में अतिरिक्त श्रम और समय लगता है। इस कारण लकड़हारा अपनी क्षमता खो देता है और लक्ष्य हासिल करने में नाकाम होता है।

तीसरा कारण यह है कि आध्यात्मिकता की मदद से युवाओं के चारित्रिक गुणों का विकास होता है जो मन को शांत करते हैं। इससे व्यक्ति दयालु, विनम्र, धैर्यवान और क्षमाशील बनता है। चौथी वजह यह है कि आध्यात्मिकता की मदद से व्यक्ति

खरी-खरी

बजट पूर्वानुमान

डा. प्रदीप मिश्र

सभी आम और खास को सूचित किया जा रहा है कल केंद्र सरकार का बजट प्रस्तुत होगा। इसमें कई वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। कुछ की कीमतों में कमी भी आएगी। लेकिन कीमत में बढ़ोतरी, दूसरे दिन से ही दिखने लगेगी, जबकि कमी इतनी नगण्य होगी कि उसे दूरबीन से ही देखा जा सकेगा।

बजट के बाद कारपोरेट जगत और ज्यादा महंगी कारें से चलेंगे एवं कारपेट पर उतरकर, भरपेट भोजन करेंगा। फिर बिना मिस्टेक, आगे बढ़ जाएगा। नेता, गिव एंड टेक से कुर्सी सेट करेंगे। अफसर, विकास को लेट करके मटियामेट करने का कार्य करेंगे।

बजट के बाद नौकरियां बढ़ेंगी, परंतु बेकार लोगों की तादाद भी बढ़ेगी। ग्रह-नक्षत्र अमीरों पर कृपा बरसाएंगे जिससे वे और भी ज्यादा अमीरी की प्राप्त होगी। जबकि सभी ग्रह-नक्षत्रों की कुदृष्टि पड़ने के कारण गरीब, ममांतक गरीबी का आलिंगन करेंगे। तरह-तरह की सरकारें, बजट के आते ही नई-नई रेवड़ियों का ऐलान करेंगी और अपनी सत्ता को साल भर के लिए एक बार फिर फिक्स करेंगी। बजट आते ही, कुछ पुल टूटने का और टूटने के बाद फिर से बनकर टूटने का इंतजार करेंगी।

बजट से उम्मीद-पालकों के व्यवसाय में वृद्धि होगी। मुंगेरीलालनुमा लोग महंगाई कम होने की उम्मीदें पालेंगे, जबकि कुछ बजट से टैक्स कम होने की उम्मीदों का पालन करेंगे। कई शेख चिल्ली, बजट से कमाई बढ़ने की उम्मीद से होंगे, जबकि कई उम्मीद-पालक बजट से गरीबी दूर होने की उम्मीद पालते नजर आएंगे।

हमारे लोकतंत्र में क्योंकि वाणी, विचार, विवेक सब तयशुदा होते हैं। इसलिए सत्ताधारी और विपक्षी नेता, बजट पर क्या बोलेंगे, कोई भी पहले से बता सकता है। सत्ता पक्ष और विपक्षी अर्थशास्त्री भी अपने हित-अनहित की विवेचना पहले हुए, हिसाब से बोलेंगे। तमाम राजनीतिक दलों के निष्पक्ष विश्लेषकों की वाणी, बसुंधरा में किस रूप में फैलेगी, यह उन्हें दिखो ही पता चल जाएगा।

बहरहाल, नया बजट, नए जूते सरीख होगा। दो-चार दिन तो काटेगा, फिर धीरे-धीरे एडजेस्ट हो जाएगा।

पोस्ट

महाकुंभ दिव्य अनुभव है, जिसे शब्दों में बांधना लगभग असंभव है। बस आंखें मूंद लो और प्रार्थना में डूब जाओ। यह विज्ञान से परे एक गूढ़ रहस्य है, जो सदियों पुराने शास्त्रों, वेदों और संतों में बसा है।
हरिवर ए्स. सिक्का@sikka_harinder

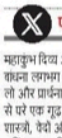

बेहद कम लागत और चुनिंदा लोगों के दम पर बना चीनी एआइ डीएसीआर असल में भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। भारत को एआइ में प्रगति के लिए अब अत्यधिक महंगे जीपीयू पर खर्च करने की जरूरत नहीं है। एआइ के मोर्चे पर अभी बढ़ने की राह में बरसों बड़ी बाधा लगता ही रही है। अब ऐसा नहीं दिखता। इसके लिए डीएसीआर से मिले सबक उपयोगी हो सकते हैं।
मिन्हाज मर्चंट @MinhazMerchant

राहुल गांधी अब चुनावी मंच से कह रहे है कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे तब यही कांग्रेस शिकायत कर रही थी कि मोदी तानाशाही के जरिये विपक्षी नेताओं को जेल में डाल रहे है। शराब घोटाला हुआ है तो केजरीवाल के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव क्यों लड़े थे?
सुशांत सिन्हा @SushantBSinha

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या चीन तकनीक के क्षेत्र में अमेरिका को पछाड़ सकता है?

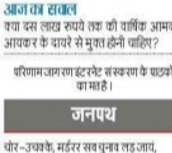

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या दस लाख रुपये तक की वार्षिक आमदनी आयकर के दायरे से मुक्त होनी चाहिए?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

चोर-उचक्के, मर्डरर सब चुनाव लड़ जाय,
फिर प्रचार की छुट पाकर की चुप्पी खाय।
घर की चुप्पी खाय कोर्ट से पाकर छुट्टी,
यदि फंस जाय शरीफ लहेगम रिट्टी-पिट्टी।
बिना किये अपराध लोग खाते हैं धक्के,
नेता मनकर मौज उड़ाते चोर-उचक्के!
- ओमप्रकाश तिवारी

झारखंड डायरी

प्रदीप सिंह
राज्य ब्यूरो प्रमुख, झारखंड

सियासी उथल-पुथल में बढ़ी स्वीकार्यता

यह संयोग ही है कि आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी द्वारा गिरफ्तारी के एक वर्ष पूरे हो रहे हैं। पिछले वर्ष 31 जनवरी को उन्हें ईडी ने जब गिरफ्तार किया था तो राज्य में सियासी उथल-पुथल का दौर आरंभ हुआ। चूंकि हेमंत सोरेन और उनके रणनीतिकारों को गिरफ्तारी का आभास पहले से ही था, इसलिए आनन-फानन में अपनी अनुपस्थिति में उन्होंने सरकार को बचाए रखने की पूरी तैयारी भी समय रहते कर ली थी। गिरफ्तारी के पहले उनके दिल्ली प्रवास के दौरान ईडी की छापेमारी से अनुमान लग गया था कि प्रतिकूल परिस्थितियां दस्तक देने वाली हैं। अनुमान के मुताबिक ही सबकुछ हुआ भी। हेमंत सोरेन की दिल्ली से वापसी के बाद तेजी से घटनाक्रम बदले। एक हद तक इस एक वर्ष के दौरान राज्य में जितनी राजनीतिक घटनाएं हुईं, उतना पहले कम देखने को कम मिला है। आश्चर्यजनक तौर पर चम्पाई सोरेन का मुख्यमंत्री बनना, लोकसभा चुनाव के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन का बेहतर प्रदर्शन, हेमंत सोरेन की जेल से वापसी, फिर से उनका मुख्यमंत्री बनना, पहले सीता सोरेन और बाद में चम्पाई सोरेन का भाजपा में शामिल होना, विधानसभा चुनाव में फिर से हेमंत सोरेन का अधिक मजबूती के साथ सत्ता में वापस लौटना आदि ऐसे घटनाक्रम हैं, जो इस दौरान घटित हुए।

राजनीतिक उथल-पुथल के इस दौर में जहां हेमंत सोरेन की लगभग पांच माह जेल में गुजारने पड़ा, वहीं उनके विश्वस्त चम्पाई सोरेन की अग्निपरीक्षा भी हो गई। हेमंत सोरेन की जेल से रिहाई के बाद सत्ता वापसी के दौरान चम्पाई सोरेन असहज हुए। हालांकि उन्होंने तत्काल विद्रोह का बिगुल नहीं फूंका। वे हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनी सरकार में मंत्री बने, लेकिन ज्यादा दिनों तक साथ नहीं चल पाए। विधानसभा चुनाव के पहले उन्होंने पाला बदलने का निर्णय किया। कुछ दिनों तक उहापोह के बाद वे भाजपा में शामिल हो गए। इसी दौरान हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन राजनीतिक क्षितिज पर उभरकर सामने आईं।

हेमंत सोरेन। पाइल

पति की अनुपस्थिति में घर से बाहर निकलकर उन्होंने राजनीतिक मोर्चा संभाला। चुनाव में जिम्मेदारी निभाने के साथ-साथ विधानसभा उपचुनाव में भी जीत हासिल की। इस दौरान हेमंत सोरेन की परिवार में भी अलगाव का सामना करना पड़ा। विधायक रहीं बड़ी भाभी सीता सोरेन पार्टी छोड़कर चली गईं और लगातार विरोध में अभियान भी चलाया।

पृथक राज्य आंदोलन के क्रम में अस्तित्व में आए झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक सच इतनी प्रतिकूल परिस्थिति पहले कभी भी नहीं आई। हालांकि नेताओं के आने-जाने का सिलसिला बना रहा। कई बार ऐसी परिस्थिति भी आई, जब पार्टी के अवसान की अटकलें राजनीतिक गलियारे में लगाई जाने लगी। आगामी दो फरवरी को झारखंड की उप-राजधानी दुमका में पार्टी का 45वां स्थापना दिवस मनाने को जब समर्थक जुटेंगे तो इसका पुनरावलोकन अवश्य होगा। इस खास मौके पर बड़ा जुटान करने की तैयारी है तो इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि अनुकूल परिस्थिति में उन मुद्दों पर काम आगे बढ़ाया जाए, जिसके कारण पार्टी की जमीन बरकरार है।

दरअसल प्रतिकूल परिस्थिति में फिर से मजबूत होकर झामुमो के उभरने के पीछे की वजह भी यही है। दुमका संताल परगना प्रमंडल का मुख्यालय है और यह क्षेत्र झामुमो के अभेद्य गढ़ के तौर पर जाना जाता है। मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन ने विभिन्न आंदोलन के क्रम में यहां मजबूत पैठ बनाई है। हेमंत सोरेन इसी प्रमंडल के साहिबगंज के बरहेट से चुनाव जीतते हैं। उनके अनुज बसंत सोरेन का विधानसभा क्षेत्र दुमका ही है।

हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद हेमंत सोरेन जब कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए तो उन्होंने यही संदेश दिया कि संघर्ष की जमीन पर हमेशा टिके रहना है। उन मुद्दों पर भी झामुमो ने सरकार बनने के बाद प्रतिबद्धता दिखाई है, जो उसके राजनीतिक आधार बढ़ने का स्रोत बने हैं। दुमका में जुटान के दौरान जो संदेश दिए जाएंगे, उस पर आगे की दिशा का निर्धारण होगा। 34 विधायक, तीन लोकसभा सांसद, तीन राज्यसभा सदस्यों वाली पार्टी के लिए यह चिंतन का एक बड़ा मंच होगा, जहां सभी आगे की रणनीति बनाकर उत्सर काम आरंभ करेंगे। पार्टी के आगामी केंद्रीय महाधिवेशन के निमित्त भी यह महत्वपूर्ण होमवर्क होगा, क्योंकि झारखंड से आगे पड़ोसी राज्यों के उन जिलों में भी झामुमो के विस्तार की कवायद आरंभ होगी, जहां आदिवासी बहुतायत में हैं। हालांकि दल के रणनीतिकार भी जानते हैं कि यह इतना आसान नहीं है। विपरीत परिस्थितियों में मजबूती से सत्ता में वापसी करने के पीछे कहीं न कहीं पिछले वर्ष हुई उन घटनाओं को भी कारक माना जा सकता है, जो प्रभाव बनाने में मददगार साबित हुए। ऐसे में आगामी वर्षों की दल के अहम नीति-निर्धारण के लिए इन आयोजनों पर निगाह रहेगी।

मंथन

एआइ से बढ़ते अवसर

राजकुमार जैन
एआइ विशेषज्ञ

एआइ यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी निरंतर नवोन्मेष हो रहा है। कार्यक्षेत्र में बदलाव लाने के साथ ही एआइ हमारी जीवनशैली को अधिक आसान बनाने के प्रयासों में भी जुटा है

हाल ही में चैटजीपीटी की निर्माता कंपनी ओपन-एआइ ने 'आपरेटर' नामक अपने पहले मानव एजेंट सदृश्य टूल की घोषणा की, जिसके बारे में बताते हुए कंपनी के बताया कि यह टूल वेबसाइट पर नेविगेट करने और बटन पर क्लिक करने जैसे आनलाइन कार्य बगैर किसी मानवीय दखल के संपादित कर सकता है। गूगल, एंथ्रोपिक और सेल्सफोर्स ने भी एजेंटों यानी एआइ सिस्टम के लिए अपने अपने प्लेटफार्म लांच किए हैं जो स्वायत्त रूप से कार्य कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक ग्राहक सेवा 'बाट' की कल्पना करें जो न केवल जानकारी उत्पन्न करता है, बल्कि अपाइंटमेंट बुक भी कर सकता है या शिकायत दर्ज कर सकता है। मेटा के मार्क जुकरबर्ग का कहना है कि इस साल ये एजेंट मध्यम श्रेणी के साफ्टवेयर इंजीनियरों की जगह ले लेंगे।

जैसे-जैसे एजेंटिक एआइ सिस्टम और अधिक परिष्कृत होते जा रहे हैं, एआइ के साथ संवाद करने के तरीके में आमूलचूल परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। केवल कमांड देने और वांछित परिणाम प्राप्त करने के बजाय अब एआइ सिस्टम के साथ अधिक सहयोगात्मक संबंध विकसित हो रहा है। ये एजेंट हमारे साथ वास्तविक वातालाप में संलग्न हो सकते हैं, वैकल्पिक समाधान प्रस्तावित कर सकते हैं, और यहां तक कि उपयुक्त अवसर पर हमारी धारणाओं को चुनौती भी दे सकते हैं। यह विकास मानव-मशीन तालमेल को एक ऐसे नवीन स्तर की ओर ले जा सकता है, जहां एआइ एक उपकरण से अधिक समस्या समाधान एवं नवाचार में मनुष्य का जोड़ीदार बन जाता है।

पुराने चैटबाट्स के विपरीत, एजेंटिक एआइ अधिक जटिल कार्यों को संभाल सकता है और वास्तविक जरूरतों के आधार पर उत्तर प्रदान कर सकता है। यह अपने उपयोगकर्ताओं को मानव सदृश्य अनुभव प्रदान करता है। एजेंटिक एआइ मानव स्वायत्ता के बिना डाटा विश्लेषण, रिपोर्ट निर्माण और निर्णय लेने का कार्य कर लेता है और इसके बाद मनुष्यों को केवल इसे प्रोसेस करना होता है। इसमें मौजूद धारणा परत डाटा को इकट्ठा करने, व्यवस्थित करने और व्याख्या करने के लिए उत्तरदायी है जो निर्णय लेने के लिए आधार का निर्माण करती है। इसके डाटा अधिग्रहण वाले प्रथम चरण में विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करना शामिल है, जैसे सेंसर, आनलाइन डाटा फीड या उपयोगकर्ता द्वारा दिया गया इनपुट। उदाहरण के लिए, स्वचालित वाहनों के लिए कैमरे या वित्तीय अनुप्रयोगों के लिए एपीआइ द्वारा एकत्रित की गई जानकारी। एक बार डाटा एकत्र करने के बाद इसे उपयोगी बनाने के लिए विश्लेषित और संसाधित किया जाता है। इसमें अप्रासंगिक जानकारी को हटाना, प्रारूपों को मानकीकृत करना और महत्वपूर्ण विशेषताओं को उजागर करना शामिल है। पर्यावरणीय जागरूकता से लैस संदर्भात्मक समझ एआइ को डाटा की अधिक प्रभावी ढंग से व्याख्या करने में सक्षम बनाती है। उदाहरण के लिए, यह अप्रत्याशित यातायात पैटर्न या असामान्य बाजार उतार-चढ़ाव जैसी विसंगतियों का पता लगा सकता है।

संज्ञान परत लक्ष्यों को निर्धारित करने, निर्णय लेने और भविष्य के उपयोग के लिए ज्ञान संग्रहीत करने पर केंद्रित है। क्रिया परत एआइ प्रणाली को वास्तविक या आभासी दुनिया में निर्णयों को निष्पादित करने में सक्षम बनाता है। सहयोग परत एआइ प्रणालियों, मनुष्यों और नैतिक ढांचों के बीच सार्थक संवाद पर जोर देता है। फीडबैक लूप सुनिश्चित करता है कि प्रणाली नए डाटा और अनुभवों से सीखकर विकसित होती है। निरंतर सीखकी रहकर एआइ नई जानकारी का सामना करते समय अपनी रणनीतियों को अपडेट करता है। वह सुनिश्चित करता है कि प्रणाली प्रासंगिक और प्रभावी बनी रहे। इसके साथ प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली नियमित रूप से अपने प्रदर्शन का आकलन करती है, सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करती है और विश्वसनीयता बनाए रखती है। एजेंटिक एआइ की तैनाती में परिवर्तनशीलता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए त्रुटि प्रबंधन पर जोर दिया जाता है। प्रक्रिया निष्पादन के दौरान यदि अप्रत्याशित समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो एआइ उन्हें संबोधित करने के लिए पूर्वनिर्धारित रणनीतियों का उपयोग करता है या हस्तक्षेप के लिए मनुष्यों को सतर्क करता है।

प्रतीकात्मक

तमाम चुनौतियों के बावजूद एजेंटिक एआइ का उदय कार्यक्षेत्र में नए अवसर खोल रहा है। एआइ एजेंट प्रशिक्षकों जैसी भूमिकाएं उभर रही हैं। कार्यप्रवाह समन्वयक भी मांग में हैं। हालांकि कुछ मौजूदा कार्य स्वचालित हो सकते हैं, लेकिन कई अनिवार्य मानवीय भूमिकाएं विकसित होंगी, जिसमें मानव एआइ के साथ मिलकर काम करेंगे। जो लोग इस परिवर्तन को जल्दी अपनाते हैं, वे दक्षता और नवाचार में सुधार का अनुभव कर सकते हैं। उन व्यवसायों के लिए जो अभी भी पहले के एआइ माडलों पर निर्भर हैं, यह एजेंटिक एआइ की संभावनाओं और क्षमताओं का पता लगाने का एक अवसर है। इससे मानव और एआइ के बीच एक सहज एकीकरण को बढ़ावा मिल सकता है।

****

भारतीय अर्थव्यवस्था

वैश्विक योगदान

भारत की अर्थव्यवस्था सारी दुनिया की प्रगति में अपना योगदान कर रही है। यह गति बनाए रखने के लिए आगामी बजट में सही नीतियों की आवश्यकता है। विश्व बाजारों में बाधाओं के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से प्रगति कर रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गतिशीलता बनाए रखी है और वह अगले दो साल तक इसे बरकरार रखेगी। विश्व बैंक की जनवरी, 2025 में प्रस्तुत 'ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट' के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेज प्रगति करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था का अपना दर्जा बनाए रखेगा। वित्त वर्ष 26 और 27 में उसके 6.7 प्रतिशत की शानदार वृद्धि दर प्राप्त करने की आशा है। यह उल्लेखनीय मार्ग न केवल 2.7 प्रतिशत की वैश्विक वृद्धि दर से आगे जाता है, बल्कि विश्व आर्थिक परिदृश्य में भारत का महत्वपूर्ण देश के रूप में स्थान बनाए रखता है। भारत का जीवन्त आर्थिक प्रदर्शन कई प्रमुख कारणों से है। सेवा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है जो सकल घरेलू उत्पाद-जीडीपी तथा रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान करता है। आईटी सेवायें, वित्त तकनीक तथा स्वास्थ्यरक्षा प्रगति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 'मेक इन इंडिया' तथा 'प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटिव'-पीएलआई योजना जैसी सरकारी पहलों ने विनिर्माण में सहायता देने के साथ ही खोज को बढ़ावा दिया है तथा घरेलू और विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया है। ढांचागत संरचना, जैसे सड़कों, रेलवे व

डिजिटल कनेक्टिविटी में निवेशों ने आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया है तथा उत्पादकता बढ़ाई है।

भारत की आर्थिक प्रगति वैश्विक संदर्भ में उल्लेखनीय है जहां वृद्धि बहुत मामूली है। अगले वर्ष चीन की वृद्धि दर धीमी होकर 4 प्रतिशत रहने का अनुमान है, ऐसे में भारत का लगातार विस्तार उसके बढ़ते महत्व को रेखांकित करता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष की 'वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक' विश्व बैंक के अनुमानों की तरह है जिसने 2025 और 2026 में भारत की 6.5 प्रतिशत वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। इससे देश के स्थिर आर्थिक मूलाधार और मजबूत होते हैं। लेकिन इस शानदार प्रदर्शन के बावजूद भारत को अनेक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है जिन पर खासकर वित्त वर्ष 26 के आगामी बजट में ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि, वृद्धि दर जीवन्त है, पर हमें तत्काल भारत की बढ़ती युवा जनसंख्या के लिए उपयुक्त रोजगार अवसर सृजित करने की आवश्यकता है। विश्व स्तर पर वस्तुओं की बढ़ती कीमतें तथा घरेलू सप्लाई श्रृंखला की बाधाओं को संबोधित करने की आवश्यकता है जो मूल्य स्थिरीकरण के लिए खतरा पैदा करती हैं। आर्थिक वृद्धि को प्रभावित किए बिना मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए प्रभावी मौद्रिक और राजकोषीय उपायों की जरूरत है। ढांचागत संरचना और समाज कल्याण पर खर्च बढ़ाने के साथ राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना नीति निर्माताओं के लिए संतुलनकारी काम होगा। कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन यह अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है जिनमें मानसूनों की अनियमितता, कम उत्पादकता तथा बाजार विसंगतियां शामिल हैं। इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण व स्थिरीकरण के लिए समग्र सुधारों की जरूरत है। भू-राजनीतिक तनाव, व्यापार विवाद, अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाने का खतरा तथा जलवायु परिवर्तन जैसे बाहरी जोखिमों का भी भारत की आर्थिक वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। इन अनिश्चितताओं का मुकाबला करने के लिए आर्थिक मजबूती बढ़ाना जरूरी है। बजट पेश करने की तैयारी कर रही वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण को भारत की तेज आर्थिक वृद्धि दर बनाए रखने के लिए इन चुनौतियों को संबोधित करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से शिक्षा, स्वास्थ्यरक्षा तथा कौशल विकास में निवेशों से सुनिश्चित होगा कि देश की आर्थिक वृद्धि के लाभ सारी जनता तक पहुंचेंगे।

वर्तमान विश्व में गांधी जी की विरासत

वर्तमान समय में अनेक समाज असहमति और विभाजन के शिकार हैं। ऐसे में गांधीजी की विरासत हमें संवाद, सद्भावना व एकता के लिए प्रेरित करती है।

राजदीप पाठक
(लेखक, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति से संबद्ध हैं)

30 जनवरी, 1948 को तीन गोलियों ने महात्मा गांधी के शरीर का अंत कर दिया, पर उनके आदर्श आज भी हमारे साथ बने हुए हैं और पूर्णतः प्रासांगिक हैं। गांधीजी के भौतिक मौन ने उनके अहिंसा, सुलह-समझौते व समझदारी के संदेशों को अमर बना दिया है। निधन के 75 साल बाद भी उनकी शिक्षायें पहले की तरह जीवन्त बनी हुई हैं तथा वे लगातार अधैर्य, असहिष्णुता व ध्रुवीकरण का सामना कर रही दुनिया में तेजी से अपना महत्व प्रकट कर रही हैं। उनकी गूंज हर जगह सुनाई दे रही है। दुनिया के समक्ष उपस्थित इन चुनौतियों को देखते हुए गांधीजी का जीवन और उनके कार्य लगातार मानवता को प्रेरित कर रहे हैं कि वह धैर्य, संवेदना तथा रचनात्मक संवाद के मूल्यों की पुनः खोज करे। हमारे ध्रुवीकृत वैश्विक समाज में जहां विभाजन और गहरे होते जा रहे हैं, वहीं असहमतियां अक्सर शत्रुता में बदलती दिख रही हैं। ऐसे में गांधीजी का दर्शन हमारे सामने आशा की किरण की तरह सामने आता है। गांधीजी के नश्वर शरीर पर चलाई गई तीन गोलियों के बाद पैदा मौन हमारे सामने एक महत्वपूर्ण सवाल छोड़ता है। क्या मानवता आज बिना हिंसा का रास्ता अपनाए अपने भीतर व्याप्त विभाजनों को दूर कर सकती है? हालांकि गांधीजी का संदेश एक विशिष्ट ऐतिहासिक संदर्भ में उभरा था, पर उसकी प्रासांगिकता ने समय की सीमायें पार की हैं और वह आज अधीरता और असहमतियों का प्रभावी जवाब है जो हमारी साझा मानवता के समक्ष गंभीर खतरा पैदा कर रही हैं। इनसे निपटने के लिए हमें गांधीजी के आदर्शों को शिक्षा में पुनर्जीवित करना होगा। युवा पीढ़ियों की शिक्षा में धैर्य, संवाद और संवेदना जैसे मूल्यों को तत्काल स्थापित करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

इन सिद्धान्तों से जल्दी परिचय भविष्य के नेताओं को स्वरूप दे सकता है। 'टेक गांधी टू स्कूल्स' जैसी पहलों का उद्देश्य गांधीवादी दर्शन को बच्चों के

जीवन में कहानियों, चर्चाओं तथा प्रायोगिक शिक्षण के माध्यम से जोड़ना है। ये कार्यक्रम उपदेश देने से आगे जाते हैं और छात्रों में अहिंसा तथा सह-अस्तित्व की भावनायें पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए, कक्षा में होने वाले टकरावों के प्रबंधन से छात्र संवेदना तथा ध्यान से सुनने के माध्यम से असहमतियों से निपटने के सबक सीखते हैं। बाद में वे ये कौशल सारी दुनिया में फैलाते हैं। शिक्षक व समुदायों के नेता भी इन मूल्यों को प्रसारित करते हैं।

अहिंसक संवाद, ध्यान व टकराव समाधान पर कार्यशालाओं से ये अमूर्त अवधारणायें कारगर व्यवहारों में बदल जाती हैं। इन उपकरणों का प्रयोग विविधतापूर्ण स्थितियों में किया गया है जिनमें घरेलू विवादों के समाधान से लेकर टकराव-ग्रस्त समुदायों में विश्वास बहाली तक शामिल हैं। सुलह-समझौते की गांधीवादी भावना की जड़ें क्षमा करने, अहिंसा और संवाद में निहित हैं जो सर्वाधिक गंभीर विभाजनों से निपटने और घावों पर मरहम लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका करते हैं।

सुलह-समझौते की परिवर्तनकारी शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। सुलह-समझौते के प्रति गांधीजी का दृष्टिकोण केवल टकरावों का समाधान न होकर संबंधों की पुनः बहाली तक विस्तारित था। उनका

> **हमारे ध्रुवीकृत वैश्विक समाज में जहां विभाजन और गहरे होते जा रहे हैं, वहीं असहमतियां अक्सर शत्रुता में बदलती दिख रही हैं। ऐसे में गांधीजी का दर्शन हमारे सामने आशा की किरण की तरह सामने आता है। गांधीजी के नश्वर शरीर पर चलाई गई तीन गोलियों के बाद पैदा मौन हमारे सामने एक महत्वपूर्ण सवाल छोड़ता है।**

विश्वास था कि साहस के साथ अन्याय का सामना किया जाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद गलत काम करने वाले के प्रति कोई घृणा नहीं होनी चाहिए। यह गांधीवादी दर्शन बदले पर सामंजस्य को प्राथमिकता देता है तथा समझदारी व सामूहिक बेहतरी पर जोर देता है। आर्चबिशप डेसमंड टुटू ने इस विश्वास को स्पष्ट करते हुए कहा था, 'सच्चा सुलह-समझौता गलतियों, विसंगतियों, आघात एवं सच्चाई को उजागर करता है।' इसी प्रकार गांधीजी के विचारों से प्रभावित नेल्सन मंडेला ने क्षमा को स्थाई शांति के लिए एक उपकरण माना है। उन्होंने जोर देकर कहा, 'साहसी लोग शांति स्थापना के उद्देश्य से क्षमा करने से डरते नहीं हैं।'

इन सिद्धान्तों को शिक्षा और सामाजिक विमर्श में समाहित कर गांधीजी की विरासत एक समारोह से आगे जाती है और हमारे सामने जीवन्त यथार्थ बन जाती है। क्षमा, अंतर-धार्मिक सामंजस्य, आदि विषयों पर सेमिनारों और चर्चाओं के साथ ही प्रतिभागियों के बीच संवाद से इन मूल्यों की गहराई से अंगीकार करने की भावना पैदा होती है। इस प्रकार के गहन अनुभव युवा मस्तिष्कों में परिवर्तन के महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में अहिंसा की भावना स्थापित करने में सहायक सिद्ध होते हैं। गांधीजी की विरासत को स्थाई बनाने के दृष्टिकोण से 'गांधी स्मृति' एक जीवन्त श्रद्धांजलि के रूप में सामने आती है। 'गांधी स्मृति' गांधीजी की स्थाई विरासत के केन्द्र में है और वहां स्थापित है जहां गांधीजी ने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए थे। दिल्ली में 5, तीस जनवरी मार्ग पर स्थित यह ऐतिहासिक स्थान पहले बिड़ला हाउस था। इसका बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान है। गांधीजी यहां 9 सितंबर, 1947 को आए थे क्योंकि इसके पहले उनके लक्षित आवास पर विभाजन के बाद पश्चिम पंजाब से आए शरणार्थियों ने कब्जा कर लिया था। आज गांधी स्मृति एक राष्ट्रीय स्मारक है जिसमें संग्रहालय, गांधीजी का संरक्षित कमरा और वह प्रार्थना स्थल है जहां वे शाम को बैठकें करते थे।

यह दुनिया भर के आगंतुकों को अपनी ओर आकर्षित करता है और तीर्थस्थल के रूप में सम्मानित है। यह उस त्रासदी की याद दिलाता है जिसने गांधीजी के भौतिक जीवन को समाप्त कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद 'गांधी स्मृति' एक विरासती स्थल से आगे जाता है। यह एक शैक्षणिक केन्द्र है जहां सभी आयुवर्ग के लोग, खासकर बच्चे साहस, संवेदना और जिम्मेदार नागरिकता के सबक सीखते हैं। हर वर्ष गांधीजी की जन्म जयंती और पुण्य तिथि के अवसर पर बच्चे शाम की प्रार्थना बैठक में संगीतमय श्रद्धांजलि देते हैं। इन आयोजनों से गांधीजी का यह विश्वास मूर्त रूप लेता है कि शांति का प्रारंभ बच्चों से होता है। गांधीजी ने कहा था, 'यदि हम दुनिया में असली शांति सिखाना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत हमें बच्चों से करनी चाहिए।'

आज गांधीजी के सिद्धान्तों पर अमल की आवश्यकता है। गांधीजी ने अहिंसा, सुलह-समझौते तथा समझदारी की पैरवी की थी। ये केवल अतीत की सजावटी चीजें न होकर आधुनिक चुनौतियों से निपटने के महत्वपूर्ण हथियार हैं। उनकी शिक्षायें हमें याद दिलाती हैं कि परिवर्तन की शुरुआत दया, संवेदना तथा रचनात्मक संवाद से होती है। बच्चों के मन में इन मूल्यों को पोषित करने से हम ज्यादा सामंजस्यपूर्ण भविष्य की नींव डालते हैं।

गांधीजी के जीवन और दर्शन की याद करते हुए हमें स्मरण रखना चाहिए कि गांधीजी के शरीर का अंत करने वाली तीन गोलियां एक समाप्ति न होकर प्रारंभ था। इससे हमें विभाजनों को एकता, दुश्मनी को समझदारी तथा निराशा को आशा में बदलने की प्रेरणा मिलती है। शांति का मार्ग लंबा और थका देने वाला है, पर इसकी शुरुआत इस साहसी विश्वास से होती है कि अहिंसा की शक्ति तथा अगली पीढ़ी के दिलों में आशा की किरण पैदा करने से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं।

पवित्र भावनाओं का सृजन

> **हमारी भावनाएं शुद्ध होती हैं, तो शुभकामनाएं और अच्छा व्यवहार स्वाभाविक रूप से आते हैं। हमें खुद को किसी के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहने की ज़रूरत नहीं है।**

ब्रह्मकुमार निकुंज
(लेखक, आध्यात्मिक उपदेशक हैं)

बचपन से ही हमें दूसरों के साथ विनम्र और अच्छा व्यवहार करना सिखाया जाता है। एक तरह से, यह महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जो देते हैं, वही आपको मिलता है, और अगर हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, तो उनके प्रति हमारा व्यवहार भी वैसा ही होना चाहिए, है न? लेकिन! अगर हमारा तथाकथित अच्छा व्यवहार सतही है, जो अच्छी भावनाओं को छिपाने का काम करता है, तो इससे हमें बदले में कोई सद्भावना नहीं मिलेगी, क्योंकि कर्म का नियम सबसे सूक्ष्म स्तर पर भी काम करता है, जो कहता है: जैसा बोओगे, वैसा ही पाओगे।

इसलिए, दूसरों के प्रति वास्तव में अच्छी भावना रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हमारी भावनाएं शुद्ध होती हैं, तो शुभकामनाएं और अच्छा व्यवहार स्वाभाविक रूप से आते हैं। हमें खुद को किसी के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहने की जरूरत नहीं है या, अधिक सूक्ष्म स्तर पर, किसी को देखकर उठने वाले नकारात्मक विचारों को दबाने या खारिज करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर भावनाएं शुद्ध हैं, तो हमारे भीतर से ऐसी नकारात्मकता कभी पैदा नहीं होगी। हम अपने प्रियजनों के प्रति शुद्ध भावनाएं और प्यार रखते हैं। हम अपने दिल की गहराइयों से उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और उनकी सफलताओं का जश्न मनाते हैं। यहां तक कि जब वे असफल होते हैं, तब भी हम उन्हें उम्मीद देते हैं और उन्हें बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं।

लेकिन हमारे परिवार और दोस्तों के घेरे से बाहर के लोगों के बारे में क्या? उनके प्रति हमारी भावनाएँ इस बात के अनुसार बदलती रहती हैं कि हम उन्हें कैसे देखते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से बुरा होता है, लेकिन यह हमारी धारणा ही है जो हमें अलग तरह से प्रतिक्रिया करने के लिए

प्रेरित करती है जब वही गलती किसी प्रियजन या किसी और द्वारा की जाती है। एक के प्रति हम सहानुभूति और समझ दिखाते हैं, और दूसरे के प्रति हम चिड़चिड़ाहट और गुस्सा दिखा सकते हैं। हम दूसरों पर नकारात्मक लेबल लगाने में जल्दी करते हैं जैसे- स्वार्थी, आलसी, मूर्ख, अहंकारी, आदि। उस व्यक्ति के प्रति हमारे विचार, शब्द और व्यवहार उस लेबल से आकार लेते हैं। इस प्रकार, हम खुद को कुछ लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने में असमर्थ पाते हैं। हालाँकि, यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमारी धारणा अक्सर हमारे अपने पूर्वाग्रहों और पूर्वाग्रहों से घिरी हो सकती है। हम हमेशा अपने निर्णयों के पीछे के कारणों से अवगत नहीं हो सकते हैं, और ये निर्णय हमें ऐसे तरीकों से कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं जो वास्तव में हमारे मूल्यों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। इसे स्वीकार करके, हम अपनी धारणाओं को चुनौती देना शुरू कर सकते हैं और अधिक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण की दिशा में काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो शुरू में अप्राप्य या मुश्किल लगता है, तो अपनी शुरुआती धारणा को अपनी बातचीत को निर्धारित करने देने के बजाय, हमें उन अंतर्निहित कारकों की संभावना पर विचार करने के लिए एक पल लेना चाहिए जो उनके व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं।

माईंडफुलनेस हमें वर्तमान में मौजूद रहने और प्रत्येक बातचीत को खुले दिमाग और दिल से करने के लिए प्रोत्साहित करती है। जब हम माईंडफुल होते हैं, तो हम आवेगपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया करने या अपने निर्णयों को अपनी बातचीत को प्रभावित करने की अनुमति देने की संभावना कम होती है। यह हमें अधिक गहराई से सुनने और अधिक सहानुभूति के साथ प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। यह प्रशंसा स्वाभाविक रूप से दूसरों तक फैलती है, जिससे हमें उनमें अच्छाई देखने में मदद मिलती है, भले ही यह उनके कार्यों या व्यवहार से अस्पष्ट हो। इसके अलावा, मजबूत, प्रामाणिक संबंध बनाने के लिए प्रयास और इरादे की आवश्यकता होती है। इसमें न केवल आसान क्षणों में दयालु होना शामिल है, बल्कि चुनौतीपूर्ण समय के दौरान समझ और समर्थन बढ़ाना भी शामिल है। इसका मतलब है खुले और ईमानदार संचार में शामिल होने और प्रतिक्रिया के लिए ग्रहणशील होना। संक्षेप में, हर व्यक्ति को दया और करुणा से देखने की आदत से गहरा परिवर्तन हो सकता है - न केवल उनमें, बल्कि हममें भी।

जब हम लगातार दूसरों में अच्छाई देखना चुनते हैं और अपना समर्थन देते हैं, तो हम एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहाँ उपचार और विकास संभव है। इन दृष्टिकोणों और प्रथाओं को विकसित करके, हम एक अधिक दयालु और समझदार दुनिया में योगदान करते हैं। याद रखें!

हममें से प्रत्येक के पास अपने कार्यों और दृष्टिकोणों के माध्यम से अपने परिवेश को प्रभावित करने की शक्ति है, और दूसरों के साथ सार्थक और सहायक तरीके से जुड़ने का विकल्प चुनकर, हम वास्तविक सद्भावना और सद्भाव की विशेषता वाले समुदाय का निर्माण करने में मदद करते हैं।

आप की बात

भावनाओं पर नियंत्रण जरूरी

देश आस्थावानों से भरा पड़ा है। छोटे-मोटे पर्वों पर भी लोग धार्मिक स्थलों और नदी क्षेत्रों में बड़ी तादाद में उमड़ पड़ते हैं। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ दुखद और चिंताजनक तो है ही धार्मिक आयोजनों में बढ़ती भीड़ प्रबंधन के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है। पिछले दो कुंभ आयोजनों 1954 और 2013 में अप्रत्याशित हादसों के बाद सुधार के लिए अमल में लायें गए उपाय बढ़ती आबादी के आगे छोटे साबित हो रहे हैं। चाहे कोई बड़ा धार्मिक आयोजन हो या कुंभ अथवा सिंहस्थ भीड़ के रेले में अनियंत्रित भीड़ के कारण अव्यवस्था के शिकार हो जाते हैं जो बड़ी जन-धन हानि की वजह बनते है।इस भीड़ में जब विशिष्ट सरकारी अतिथि, कोई बड़ी हस्ती की उपस्थिति हो तो सुरक्षा को ठेंगा अवश्य देखने में आता है। हादसा भीड़ में आत्मसंयम की बड़ी कमजोरी से होना माना जाता है जो छोटे से कार्यक्रम में भी जरूरी होती है। लोग आगे आने के लिए संयम तोड़ बैठते हैं और नतीजन हादसे हो जाते है। अक्सर धार्मिक आयोजनों में ऐसे स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था केवल नियंत्रण भर की होती है लेकिन इस हादसे के बाद अब उसका सख्त होना बहुत जरूरी हो गया है। भीड़ प्रबंधन के माकूल इंतजाम एक व्यवहारिक आधार सहिता के जरिए तय किए जाने चाहिए जिससे धार्मिक आयोजन सुरक्षित और गरिमापूर्ण बने रहें ही और हादसों से उन्हें कलंकित होने से भी बचाया जा सके।

– **अमृतलाल मारू**, इंदौर

केजरीवाल का चरित्र

शीला दीक्षित से रॉबर्ट वाड्रा सहित कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति भ्रष्टाचार के आरोपों की झड़ी, जनलोकपाल से लेकर कांग्रेस से कैसा भी गठजोड़ नहीं करने के लिए अपने ही बच्चों की शपथ, सरकारी गाड़ी, सुरक्षा और निवास न लेने का संकल्प, नितिन गडकरी पर आरोप मढ़ने से बाद में क्षमायाचना की कथा, पंजाब विधानसभा चुनाव में अकाली नेता विक्रम मजीठिया पर पंजाब में नशा व्यापार का आरोप फिर माफी। आम आदमी पार्टी के नेता अरविन्द केजरीवाल का यही चरित्र है इसलिए जब उसने हरियाणा द्वारा दिल्ली के पानी को विषैला बनाने का दावा किया तो आश्चर्यचकित होने की अपेक्षा ऐसे राजनेता को राजनीति से विलग कर देना मतदाता का दायित्व है और चुनाव आयोग का भी । झूठ, पाखण्ड, अराजकता, धूर्तता, कुटिलता ही केजरीवाल के राजनीतिक उपकरण हैं । प्रारम्भ से ही इसकी कोई भी बात विश्वसनीय नहीं है। बस कुछ (बिजली, पानी आदि) मुफ्त बांटने के अतिरिक्त। दुर्भाग्य से भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोपों के रहते भी सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल व उसके गिरोह जनों को जेल से बाहर निकाल दिल्ली के सामाजिक राजनैतिक वातावरण में प्रदूषण को बनाए रखने का काम किया है। सब जानते हैं कि सुप्रीम जज किस आधार पर निर्णय लेते हैं, सब जानते हैं सुप्रीम जजों और अभिषेक मनु सिंघवी – कपिल सिब्बल का गठजोड़ ।

– **डॉ जय प्रकाश**, अंबाला छावनी

मिलावटखोरी की समस्या

भारत अपनी प्रगति, सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक विकास के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है, लेकिन मिलावटखोरी जैसी कुप्रथाएं इसकी छवि को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा रही हैं। हाल ही में, मध्य प्रदेश में मिलावटी दूध और उससे बने उत्पादों की आपूर्ति से जुड़ा मामला सामने आया, जिसमें डेंडी ने नौ स्थानों पर छापेमारी की। चौंकाने वाली बात यह है कि इन मिलावटी उत्पादों की आपूर्ति न केवल देश में, बल्कि विदेशों तक भी की जा रही थी। इससे आम जनता के स्वास्थ्य के साथ-साथ भारत की वैश्विक साख को भी खतरा है। मिलावटी खाद्य पदार्थों, विशेषकर दूध और दुग्ध उत्पादों, का सेवन अत्यंत हानिकारक होता है। इनमें मिलाए गए रसायन गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। यदि भारत से निर्यात किए गए उत्पादों में मिलावट पाई जाती है, तो इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय खाद्य उद्योग की विश्वसनीयता को गहरा आघात लगेगा। यह समस्या सिर्फ दूध तक सीमित नहीं है, बल्कि मसाले, मिठाइयां और अन्य खाद्य पदार्थ भी इसकी चपेट में हैं। मिलावट का यह जाल जितना विस्तृत होता जा रहा है, उतना ही यह देश की साख और आम जनता के स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। सरकार कड़े कदम उठा रही है, लेकिन जब तक जनता जागरूक नहीं होगी और सख्त कार्रवाई नहीं होगी, यह बुरी प्रथा जारी रहेगी।

– **आर के जैन**, बड़वानी

इस ओर भी ध्यान दें!

समय के साथ सुविधाओं के तौर तरीके बदले हैं अब लगभग सामान्य जरूरत की सभी चीजें होम डिलीवरी के लिए उपलब्ध हैं। बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और प्रतिस्पर्धा में भी सबसे तेज पहुंचने की होड़ में लगभग हर कोई आगे निकलना चाहता है। पिज्जा तीस मिनट में आपके घर पहुँचने की गारंटी दी जाती है , अगर थोड़ी सी भी देर हो जाए तो हम डिलीवरी पहुंचाने वाले व्यक्ति पर नाराजगी जाहिर करते हैं लेकिन क्या हमने समय पर हर चीज पहुंचाने वाले इन लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के बारे में कभी सोचा है ? आजकल डिलीवरी सेवा देने वाले कर्मचारियों पर दबाव बढ़ चुका है। उन्हें समय पर हर चीज पहुंचाने की जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन इस प्रक्रिया में उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। अक्सर देखा जाता है कि इन डिलीवरी कर्मचारियों को ट्रैफिक, मौसम, या अन्य जोखिमों का सामना करते हुए तेजी से पहुंचने की कोशिश करनी पड़ती है, जिससे उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। अगर किसी डिलीवरी कर्मचारी को चोट लगती है या वह थकान ग्रस्त होता है, तो उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता।

– **नितिन रावत**, फिरोज़ाबाद

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से **responsemail.hindipioneer@gmail.com** पर भी भेज सकते हैं।

किसी बुरे कानून को निरस्त करवाने का सबसे अच्छा तरीका है, उसे सख्ती से लागू करना। -अब्राहम लिंकन

श्रद्धा व अनुशासन का संगम होना ही चाहिए। महाकुंभ में करोड़ों लोगों का प्रबंधन एक दुष्कर कार्य है और यह संतोष की बात है कि एक आसन्न त्रासदी पर समय रहते नियंत्रण पा लिया गया। फिर भी इससे सबक जरूर लेना चाहिए, ताकि ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

श्रद्धा और अनुशासन

करोड़ों लोगों के आने के बावजूद अब तक बेहद शांति व कुशलता के साथ प्रबंधित हो रहे महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन मची भगदड़ के बाद के दृश्य वाकई परेशान करने वाले हैं और सवाल उठाते हैं कि देश में धार्मिक आयोजनों में ऐसे दृश्य बार-बार खुद को क्यों दोहराते हैं, जिनमें आस्था अव्यवस्था के आगे बेबस नजर आने लगती है। कुछ समय पहले हाथरस में एक सत्संग में बाबा की चरण-धूलि लेने के लिए मची भगदड़ में सौ से भी ज्यादा लोगों की जानें चली गई थीं। इसी तरह, कुछ दिनों पहले बागपत में जैन निर्वाण महोत्सव के दौरान लकड़ी की सीढ़ियां टूटने से हुए हादसे में भी कुछ ऐसा ही दिखा। गनीमत है कि कुंभ के दौरान हुआ हादसा एक सीमित क्षेत्र में हुआ और समय रहते इस पर काबू पा लिया गया, जो एक बड़ी त्रासदी भी हो सकता था। फिर भी इसने कुछ चीजों की ओर तो ध्यान दिलाया ही है। धार्मिक आयोजनों में भीड़ तो होती ही है, जिनमें प्रशासन की तैयारियां अक्सर नाकाफी ही साबित होती हैं। पिछले कुंभ में भी कुछ ऐसे ही दृश्य दिखे थे और तब भी प्रशासन को खरी-खोटी सुनाकर सबने हाथ धो लिए थे। प्रशासन को तो हमेशा ही कह सकते हैं कि उसे ध्यान देना चाहिए, जो सही भी है। लेकिन जब भी धार्मिक आयोजन होते हैं, जिसमें ज्यादा संख्या में लोग आने हों, तो भक्तों का अति उत्साह अपने आप में भीड़ के स्व-नियंत्रण का मसला भी बन जाता है। महाकुंभ जैसे इतने बड़े आयोजन पर सहज-स्वाभाविक है कि लोग स्नान करना चाहेंगे, क्योंकि यह उनके जीवन में एक अपूर्व अवसर की तरह होता है और यह बिल्कुल स्वाभाविक भी है। लेकिन यह भी समझना चाहिए कि अव्यवस्थित भीड़ और अफवाहें कई बार त्रासदी को जन्म देती हैं। अतिरिक्त उत्साह और व्यावहारिकताओं पर ध्यान दिया जाए, तो बहुत सारी चीजों को रोका जा सकता है। आस्था एक व्यक्तिगत विषय है, लेकिन जब यह सार्वजनिक रूप लेता है, तो

इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, जितना प्रशासन का दायित्व है, उतना ही समाज के अंग के तौर पर हमारा भी। यह समझने की बात है कि भक्ति का अर्थ केवल श्रद्धा प्रकट करना नहीं, बल्कि दूसरों की सुरक्षा व जीवन के प्रति संवेदनशील होना भी है। सैलाब को उसकी सीमाओं के साथ भी देखना चाहिए। श्रद्धा व अनुशासन का संगम होना ही चाहिए। करोड़ों लोगों का प्रबंधन एक दुष्कर कार्य है और यह संतोष की बात है कि समय रहते इस पर नियंत्रण भी पा लिया गया, फिर भी इससे सबक जरूर लेना चाहिए, ताकि ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

वक्फ कानून में बदलाव संविधान के अनुरूप

जेपीसी में बहुमत से मंजूर वक्फ के संशोधित विधेयक में जो बदलाव प्रस्तावित हैं, उनसे मुसलमानों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति मजबूत ही होगी। लेकिन इसे समझने के लिए धर्म और सियासत के आधार पर हल्ला करने के बजाय बिल के कानूनी बिंदुओं पर गंभीर विमर्श जरूरी है।

जेपीसी में बहुमत से मंजूर वक्फ के संशोधित विधेयक पर विपक्षी नेताओं और उलेमाओं की आलोचना के दो बड़े बिंदु हैं। पहला, संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में विधायी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ और विपक्षी सांसदों को पर्याप्त समय नहीं मिला। दिल्ली चुनाव और सियासी लाभ के लिए संसद के बजट सत्र में आपाधापी में बिल पेश करने की कोशिश हो रही है। दूसरा, इन बदलावों से मुस्लिम समुदाय के मौलिक अधिकारों का हनन होगा, जिनका संविधान के अनुच्छेद-13, 25, 26 और 29 में विशेष तौर पर जिक्र है। धर्म और सियासत के आधार पर हल्ला करने के बजाय बिल के कानूनी बिंदुओं पर गंभीर विमर्श जरूरी है।

चिराग गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट के वकील

नेहरू सरकार ने 1954 में, नरसिम्हा राव सरकार ने 1995 में और फिर मनमोहन सिंह सरकार ने 2013 में वक्फ कानून में बड़े बदलाव किए थे। इन बदलावों से वक्फ बोर्ड को मनमानी अधिकार मिलने के साथ सिविल अदालतों का क्षेत्राधिकार खत्म हो गया था। वक्फ की संपत्ति का मदरसा, कब्रिस्तान, मस्जिद, अनाथालय और इस्लामिक धर्मार्थ कार्यों में इस्तेमाल होता है। वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया ऑनलाइन डाटा पोर्टल के नवीनतम डाटा के अनुसार, वक्फ के पास 8.65 लाख संपत्तियों के तहत लगभग 9.4 लाख एकड़ जमीन है। 50 फीसदी वक्फ संपत्तियों के बारे में सही जानकारी उपलब्ध नहीं है और नौ फीसदी संपत्तियों में अवैध निर्माण से जुड़े 32 हजार मामले चल रहे हैं। वक्फ प्रशासन को पारदर्शी और कानून सम्मत बनाने के लिए 1969 में संसद में जोरदार मांग की गई थी। कई दशक पहले राज्यसभा में बहस के दौरान विपक्ष के नेता और भाजपा सांसद सिकंदर बख्त ने कहा था कि वक्फ संपत्तियां गरीब मुसलमानों की बेवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और यतीम बच्चों की अमानत हैं, जिनमें खयानत हो रही है। जायदाद को महफूज रखने और लूटमार से बचाने के लिए पारदर्शिता, ऑडिट और कुशल प्रशासन जरूरी है। 2006 में सच्चर समिति की

रिपोर्ट में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने, अभिलेखों की देखरेख और ऑडिट की सिफारिश की गई थी। 2008 में राज्यसभा में पेश संसदीय समिति की रिपोर्ट में वक्फ बोर्डों में सीईओ के तौर पर वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मुतवल्लियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के प्रावधान की सिफारिश की गई थी। बरेलवी मौलाना के अनुसार, वक्फ बोर्ड के रहनुमाओं ने भू-माफिया से मिलकर करोड़ों रुपये की जमीन बेच दी। इस बिल के आने के बाद भ्रष्टाचार कम होने के साथ मुसलमानों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति मजबूत होगी।

संसद के कानून से जमींदारी और राजाओं का प्रिवी पर्स खत्म हो गया। पर वक्फ कानून से हासिल मनमाने अधिकारों की आड़ में वक्फ बोर्ड पुरातत्व विभाग के अधीन 120 प्राचीन स्मारकों, मंदिरों और किलों पर दावा ठोक रहे हैं। सनद रहे कि काबरी मस्जिद मामले में वक्फ बोर्ड पक्षकार था और अब मथुरा व काशी जैसे अनेक स्थानों में चल रही मुकदमेबाजी में वक्फ का दावा है। संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची के अनुसार अनुसूचित जनजाति के लोगों की भूमि की सुरक्षा का विशेष प्रावधान है, पर उन संपत्तियों पर भी वक्फ बोर्ड के दावे हैं। कर्नाटक में वक्फ बोर्ड अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर लोगों को मैरिज सर्टिफिकेट देने लगे, जिस पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने नवंबर, 2024 में रोक लगा दी।

विवादित संपत्ति के दान और संपत्ति के लिए अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए प्रस्तावित कानून में प्रावधान हैं। उनके अनुसार, कम से कम पांच साल से इस्लाम का पालन करने वाले वैध संपत्ति के मालिक ही वक्फ बना सकते हैं। वेबसाइट पर वक्फ संपत्ति का विवरण घोषित करना अनिवार्य होगा। स्वतंत्र ऑडिट और केंद्रीय पोर्टल के माध्यम से संपत्तियों के अनिवार्य पंजीकरण के प्रावधान से वक्फ के मौखिक दावों पर लगाम के साथ मुकदमेबाजी में कमी आएगी। ये बदलाव संपत्ति पंजीकरण, स्टांप ड्यूटी और लिमिटेशन कानून के भी अनुरूप हैं।

शाहबानो मामले में कट्टरपंथी ताकतों के दबाव की वजह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राजीव गांधी सरकार ने संसद से बदल दिया था। इतिहास से सबक लेते हुए यह समझने की जरूरत है कि तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति से दूसरे समुदायों में कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा मिलता है। दिल्ली और दूसरे राज्यों में वक्फ बोर्ड के माध्यम से इमाम और मौलवियों को वेतन मिलता है। अब उसी तर्ज पर हिंदू पुजारियों के लिए वेतन के साथ सनातन बोर्ड के गठन की मांग हो रही है। ईसाइयों की धार्मिक संपत्तियों के लिए मद्रास हाई कोर्ट ने नियामक बनाने की बात कही है। संविधान में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है, पर मुस्लिम समुदाय अभी भी शरिया कानूनों से संचालित है। इसलिए धर्म-निरपेक्षता की आड़ में वक्फ कानून में हो रहे बदलावों का विरोध ठीक नहीं है।

हिंदू धर्म में दलित और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए आरक्षण का प्रावधान है। नए बिल के अनुसार केंद्रीय वक्फ बोर्ड, राज्य वक्फ बोर्ड और वक्फ न्यायाधिकरणों में महिलाओं और गैर-मुस्लिमों के साथ शिया, दाऊदी बोहरा, अहमदियों, आगखानी जैसे मुस्लिम संप्रदायों का प्रतिनिधित्व होगा। वक्फ कानूनों में बदलाव से मुस्लिम समाज के पसमांदा और ओबीसी जातियों को वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में बेहतर भूमिका के साथ आमदनी में सही हिस्सेदारी मिलेगी। इस्लामिक देशों में कई दशक पहले फैमिली वक्फ खत्म कर दिया गया था। नए बिल में फैमिली वक्फ में महिलाओं को प्रगतिशील तरीके से अधिकार दिए गए हैं। पुरानी सरकारों ने वक्फ कानून में जो बदलाव किए थे, उनके अनुसार सरकारी या गैर-मुस्लिम की संपत्ति के गलत अधिग्रहण होने पर वक्फ ट्रिब्यूनल के पास ही अपील करनी पड़ती है। नए बिल के अनुसार, कानून बनने पर अदालतों का अधिकार बहाल होगा, जो पूरी तरह से संविधान के प्रावधानों के अनुकूल है। भूमि राज्यों का विषय है, इसलिए वक्फ कानून में बदलाव से पहले सभी राज्यों के साथ पर्याप्त विमर्श होना चाहिए। विपक्षी सांसदों ने अनेक बिंदुओं पर आपत्तियां दर्ज कराई हैं। कानून पारित होने से पहले इन सभी बातों का ध्यान नहीं रखा गया, तो कानून बनने के बाद वक्फ मामला अदालतों में उलझ सकता है।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

जेम्स ऐलन

अहंकार, लालसाओं पर विजय, मायामोह का त्याग और अंतःकरण की शुद्धि करना ही स्थायी शांति का मार्ग है। अपनी इच्छाएं और भावनाएं अपने वश में रखिए। इसके अलावा शांति का कोई दूसरा मार्ग नहीं है।

स्वार्थ से छुटकारा पाने पर ही जीवन जीने योग्य होगा

इस दुनिया में हर जगह कलह-क्लेश और अशांति देखने में आती है। किंतु इनके मध्य भी शांति का निवास है। जिस प्रकार समुद्र में बहुत-से ऐसे गहरे स्थान हैं, जहां तेज से तेज तूफान नहीं पहुंच सकता, उसी प्रकार मनुष्य के हृदय में भी शांति का नीरव स्थान है, जिस पर पाप और दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। इस स्थान पर पहुंचकर शांति का अनुभव करने और बाहरी दुनिया के झगड़ों के बीच निर्लिप्त होकर काम करने का नाम शांति है। जब मनुष्य मानसिक विकारों से और संस्कार के कलह-क्लेशों से ऊब जाता है, तो वह निष्कलंक जीवन की ओर बढ़ने लगता है। इस प्रकार जीवन व्यतीत करने का नाम ही शांति है। घृणा से मनुष्य, मनुष्य से विमुख हो जाता है और वह दूसरों से दुर्व्यवहार करने लगता है। घृणा से दो जातियों में अथवा दो राष्ट्रों में क्रूर युद्ध होता है। लेकिन तब भी मनुष्य पूरी तरह से यह जानते हुए भी कि ऐसा क्यों हो रहा है, पूर्ण प्रेम की छाया में थोड़ा-सा विश्राम रखता है। प्रेम की सृष्टि करके इसी आधार पर जीवन बिताना ही सच्ची शांति है। हृदय की शांति और हृदय का प्रेम ही स्वर्ग का राज्य है। किंतु लोगों को यह इस कारण कठिन मालूम होता है, क्योंकि वे अपने स्वार्थों को न तो छोड़ने के लिए तैयार हैं और न वे छोटे बच्चों की तरह एक-दूसरे से प्रेम ही कर सकते हैं। स्वर्ग का द्वार बड़ा तंग और छोटा है। दुनिया के धर्मों में पड़े मूढ़ इसे नहीं देख सकते। अहंकार, लालसा, लोभ और विलासिता इससे दूर ले जाने वाले हैं। मनुष्य शांति-शांति चिल्लाता है, किंतु उसके स्थान में उसे अशांति और लड़ाई-झगड़े दिखलाई पड़ते हैं। त्याग और विश्व-प्रेम से ही स्थायी शांति मिल सकती है, और दूसरे स्थानों में शांति नहीं मिल सकती। सुख-सुविधा, इच्छा-पूर्ति और सांसारिक सफलताओं से जो शांति मिलती है, वह असली शांति नहीं है। अग्नि-परीक्षा के समय वह कपूर की भांति उड़ जाती है। केवल हृदय की सच्ची शांति ही जीवन की कठिन घड़ियों में रह सकती है। ऐसी शांति का अनुभव वही लोग कर सकते हैं, जिन्होंने अपने हृदय से स्वार्थ को निकाल दिया है। पवित्र जीवन ही सच्ची शांति का मूल है, जो आत्मसंयम से प्राप्त होती है। आत्मसंयम से मनुष्य की बुद्धि प्रखर होती है और वह उससे प्रगति करता चला जाता है। ज्यों ही मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलना शुरू करता है, उसे कुछ शांति मिलने लगती है, किंतु उसे पूर्ण रूप से शांति तभी मिल पाती है, जब वह अहं को छोड़कर निर्दोष जीवन व्यतीत करने लगता है। अहंकार पर विजय, जीवन की लालसाओं पर विजय, मायामोह का त्याग और अंतःकरण की शुद्धि करना ही स्थायी शांति प्राप्त करना है। अपनी इंद्रियों को अपने वश में कीजिए और अपनी इच्छाएं और भावनाएं वश में रखिए। इसे छोड़कर शांति पाने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यदि आप पवित्र और संयमित जीवन नहीं बिताएंगे, तो चाहे आप जितने देवी-देवताओं की पूजा करें और जितनी धार्मिक पुस्तकें पढ़ें, आपका यह सब काम व्यर्थ जाएगा।

दिशा स्वयं निर्धारित करें

आपके पाप, दुख, भय और चिंता-यह सब आपके ही उत्पन्न किए हुए हैं। आप चाहें उनसे चिपके रहें या छोड़ दें। जीवन के झगड़ों से, मानसिक विकारों से अपने को अलग कीजिए, तभी आप सुखदायी शांति पा सकेंगे। हृदय के भीतर विश्राम-स्थल में प्रवेश कीजिए, जहां आप सुखमय शांति पा सकेंगे। अपने जीवन की दिशा खुद निर्धारित कीजिए।

सूत्र

दूसरा पहलू

पिछले साल मैंने एस्टोनिया के तार्तू में एक संगोष्ठी में हिस्सा लिया, जिसका विषय था-रूसी सीमा पर जीवित रहने की कला।

जंग का मैदान बन रही है भाषा और संस्कृति

लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया एक बार फिर पड़ोसी रूस से खौफ में हैं। 20वीं सदी में इन बाल्टिक गणराज्यों को अपने अस्तित्व के लिए रूस से लड़ना पड़ा था। अब इस इतिहास की विरासत समकालीन क्षेत्रीय भू-राजनीति पर भारी पड़ रही है। वर्ष 2014 में क्रीमिया पर रूसी कब्जे और फिर यूक्रेन पर हमले ने तीनों देशों को फिर से डरा दिया है। इन तीनों बाल्टिक देशों ने अब अपना रक्षा खर्च बढ़ाया है और एक साझा बाल्टिक रक्षा मोर्चा भी बना रहे हैं। तार्तू एस्टोनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो रूसी सीमा से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। रूस का यहां दखल बना रहता है। पिछले साल मई में एस्टोनिया ने रूस पर उसके विमानों के जीपीएस सिग्नल बाधित करने का आरोप लगाया था। सिग्नलों में बाधा की वजह से तार्तू हवाई अड्डे पर उड़ानें निलंबित करनी पड़ीं। इससे साफ है कि रूस कितनी आसानी से एस्टोनिया के रोजमर्रा के जीवन में दखल डाल सकता है। फिर भी तार्तू में लोगों का जीवन सामान्य रूप से ही चल रहा है।

जूलियट ब्रेटन

पिछले साल एस्टोनिया ने रूस पर प्रियन्तों के जीपीएस सिग्नल बाधित करने का आरोप लगाया था, जिससे उसे उड़ानें निलंबित करनी पड़ी थीं।

पिछले साल मैं एस्टोनिया के तार्तू शहर में थी। यूरोपीय संस्कृति की राजधानी के रूप में यहां उत्सवों का दौर था। मैंने भी एक संगोष्ठी में हिस्सा लिया था, जिसका विषय था-रूसी सीमा पर जीवित रहने की कला। चर्चा में प्रमुख फोकस पहचान, युद्ध और संस्कृति के बदलते विचारों पर था। इस कार्यक्रम से एक मुद्दा जो उभरा, वह यह था कि एस्टोनिया को साझा बाल्टिक और रूसी सांस्कृतिक विरासत तार्तू और देश भर में रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे प्रभावित करती है? सामान्य तौर पर संस्कृति, विशेष रूप से भाषा, एस्टोनिया में युद्ध का मैदान बनती जा रही है। यहां तीन लाख से ज्यादा लोग मूल रूसी भाषी हैं, जो एस्टोनियाई आबादी का लगभग 27 फीसदी हैं। एस्टोनियाई सरकार चिंतित है कि पुतिन इन रूसी भाषियों के बचाव में आने का दावा करके देश पर हमले को उचित ठहरा सकते हैं, जैसा कि 2022 में यूक्रेन पर हमले के दौरान उन्होंने किया था। एस्टोनिया ने देश के सभी स्कूलों में एस्टोनियाई भाषा में पढ़ाई शुरू कर दी। एस्टोनिया के नागरिकों में राष्ट्रीय पहचान और देश की उपलब्धियों को लेकर गर्व की भावना व्यापक रूप से बढ़ रही है। एस्टोनियाई समाज अब यूरोपीय पहचान के पक्ष में रूसी साम्राज्यवाद की अभिव्यक्तियों को खारिज कर रहा है। एस्टोनिया में रूसी संस्कृति का विरोध हो रहा है। अपने आक्रामक रूसी पड़ोसी के बढ़ते दबाव को देखते हुए एस्टोनिया में संस्कृति की भूमिका महत्वपूर्ण है। *(द कन्वर्सेशन से)*

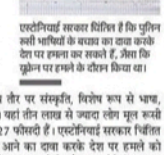

एस्टोनियाई सरकार चिंतित है कि पुतिन रूसी भाषियों के बचाव का दावा करके देश पर हमला कर सकते हैं, जैसा कि यूक्रेन पर हमले के दौरान किया था।

आंकड़े

चांदी अयस्क भंडार

भारत के चांदी अयस्क भंडार में सर्वाधिक हिस्सेदारी राजस्थान की है। मात्र पांच फीसदी हिस्सेदारी के साथ कर्नाटक दूसरे स्थान पर है।

राजस्थान	85%
कर्नाटक	5%
झारखंड	4%
आंध्र प्रदेश	3%
अन्य	3%

स्रोत : Mines Bureau

सिंगाजी एक दिन हरसूद-निमाड़ के रास्ते से जा रहे थे। रास्ते में ब्रह्मगीर महाराज के शिष्य गीत गा रहे थे। उस गीत ने उनके जीवन को बदल दिया।

आध्यात्मिक चेतना का जागरण

सिंगाजी का जन्म रियासत बड़वानी (मध्य भारत) के खजूरी गांव में हुआ था। पिताजी का नाम भीमा और माता का गौरबाई था। सिंगाजी के जन्म के पांच-छह साल बाद इनके पिता हरसूद जाकर बस गए। बड़े होने पर सिंगाजी निमाड़ के राव साहब के यहां एक रुपया मासिक वेतन पर नियुक्त हुए। राव साहब का सिंगाजी पर बड़ा विश्वास था। लेकिन सिंगाजी का मन संसार की ओर से विरक्त था। उनके आध्यात्मिक जीवन का श्रीगणेश तब हुआ, जब एक दिन वह हरसूद-निमाड़ के रास्ते से जा रहे थे। भैंसवा ग्राम में ब्रह्मगीर महाराज के शिष्य मनरंगीर जी गा रहे थे- *समुझि लेओ रे मना भाई, अंत न होय कोई आपणा, यहीं माया के फंदे में तर आन भुलाणा।।* सिंगाजी की हृदय-वीणा इस मार्मिक गीत की चोट से झनझना गई। वैराग्य जाग पड़ा। 'अरे! इस कोलाहलमय विराट संसार में, जहां क्षण भर के लिए भी जीवन के व्यापार बंद नहीं होते, मोह, माया और तृष्णा में ही आयु बीत जाती है, वहां अंत में ईश्वर के सिवाय कोई भी अपना नहीं होता।'

अंतर्व्यथा संकलित

सिंगाजी तत्क्षण मनरंगीर जी के चरणों में गिर पड़े और उन्हें अपना गुरु बना लिया। राव साहब की नौकरी छोड़कर प्रभु के चाकर बन गए। राव साहब ने बहुत समझाया, वेतन बढ़ाने का प्रलोभन दिया, लेकिन सिंगाजी ने एक न मानी और नौकरी छोड़कर पीपल्या के जंगलों में रहने लगे। इस दौरान ही उन्होंने *अनहद की नाद* में आठ सौ भजनों की रचना की।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 11 फरवरी, 1964

पाकिस्तान शांतिपूर्ण समझौते का इच्छुक नहीं

पाकिस्तान भारत से शांतिपूर्ण समझौते का इच्छुक नहीं

दोनों देशों के सम्बन्धों में कश्मीर सिवाय

राष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन ने बताया कि पाकिस्तान भारत से 'न्यायसंगत और व्यावहारिक आधार' पर समझौता करने का कोई इरादा नहीं है। यह मतभेदों को तथ्यों के आधार पर हल करने को उत्सुक प्रतीत नहीं होता।

पाकिस्तान के लिए परेशानी न बन जाएं ट्रंप

ट्रंप और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे होंगे, यह इस पर निर्भर है कि वह चीन के साथ कैसे संबंध रखते हैं और अफगानिस्तान को कैसे संभालते हैं।

मरियाना बाबर, वरिष्ठ पाकिस्तानी पत्रकार — पड़ोस

अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पद संभाले अभी एक महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। दुनिया का हर मुल्क बेचैनी से इंतजार कर रहा है कि वह आगे क्या करने वाले हैं। दक्षिण एशिया के देश भी इसका अपवाद नहीं हैं। उनके आदेश पाकिस्तान समेत इस क्षेत्र के अन्य मुल्कों को भी प्रभावित कर रहे हैं।

पाकिस्तान के पूर्व विदेश और रक्षा मंत्री इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर-खान कहते हैं, 'प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनकी टीम को अमेरिका का समर्थन बनाए रखने में काफी मशक्कत करनी होगी। प्रधानमंत्री को पाकिस्तानी हितों की रक्षा और प्रसार के लिए गैर-पारंपरिक व बहुआयामी कूटनीति का इस्तेमाल करना होगा, यानी अमेरिका को पाक निर्यात का सबसे बड़ा गंतव्य बनाए रखना होगा और पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिकी आर्थिक दांव को रोकना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात मौजूदा कार्यक्रम को जारी रखने के लिए

आईएमएफ में आवश्यक समर्थन बनाए रखना होगा।'

व्यक्तिगत रूप से, मुझे लगता है कि ट्रंप पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती बनने वाले हैं और इसी से जुड़ा सवाल है कि पाकिस्तान के चीन से कैसे संबंध रहते हैं और ट्रंप अफगानिस्तान को कैसे संभालते हैं। ट्रंप ने पदभार संभालने से पहले और बाद में भी चीन से संपर्क साधने की कोशिश की है। उन्होंने चीनी राष्ट्रपति को अपने शपथ ग्रहण समारोह में भी बुलाया था और संकेत दिए हैं कि ट्रंप के नए कार्यकाल में दोनों मुल्कों के बीच तालमेल हो सकता है। लेकिन अभी शुरुआती दिन हैं।

पाकिस्तान के लिए अच्छी बात यह होगी कि अगर चीन और अमेरिका के संबंध काफी हद तक संतुलित हो जाएं, तो चीन से उसके द्विपक्षीय रिश्तों पर कम दबाव पड़ेगा। हमने देखा है कि ट्रंप कूटनीतिक चैनलों को दरकिनार करके विश्व नेताओं से व्यक्तिगत संबंध बनाना चाहते हैं। ट्रंप और इमरान खान की पहली मुलाकात में ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। हालांकि 2019 में उन्होंने अपने कार्यालय में इमरान खान से बातचीत के दौरान एक धमाका करते हुए कश्मीर पर इमरान खान को बेवकूफ बना दिया था।

उन्होंने इमरान खान से कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें कश्मीर मसले पर मध्यस्थता करने के लिए कहा है। इस पर खुश होते हुए इमरान खान ने कहा कि अगर वह कश्मीर के लिए कुछ कर सकें, तो लाखों लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे। यह वास्तव में एक कूटनीतिक झांसा था और जब भारत ने ट्रंप की टिप्पणी का खंडन किया, तब ट्रंप चुप हो गए और फिर कभी कश्मीर का जिक्र नहीं किया।

ट्रंप की नई पारी की शुरुआत में पाकिस्तान के सामने एक चुनौती ट्रंप की शरणार्थी नीति भी है, क्योंकि ट्रंप ने बाइडन युग के शरणार्थी कार्यक्रम को निलंबित कर दिया है, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान में फंसे हजारों अफगानों को फिर से बसाना है। पाकिस्तान में अस्थायी तौर पर रह रहे 25,000 अफगान अमेरिकी शरणार्थी कार्यक्रम के तहत अमेरिका भेजे जाने के पात्र हैं। यहां तक कि बाइडन प्रशासन भी इससे पीछे हट रहा था और उन्हें वापस लेने की जल्दी में नहीं था। ये 25,000 अफगान वर्षों से पाकिस्तान में रह रहे हैं, जिन्हें काबुल पर कब्जे के बाद वाशिंगटन के अनुरोध पर पाकिस्तान सरकार द्वारा यहां लाया गया था। उन्होंने अफगानिस्तान में नाटो और अमेरिकियों के साथ काम किया था, इसलिए यदि ये तालिबान शासन में अफगानिस्तान लौट गए, तो कभी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे।

चूंकि ट्रंप प्रशासन आव्रजन के मामले में सख्त रुख अपना रहा है, इसलिए पाकिस्तान को यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी कूटनीतिक लड़ाई लड़नी होगी कि ट्रंप अपने पूर्ववर्ती के निर्णय का सम्मान करें।

इसके अलावा, अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जाने वाली विदेशी सहायता को पुनर्मूल्यांकन के लिए रोक दिया है। यह रोक 90 दिनों की है। वर्तमान में दुनिया की कई राजधानियों की तरह इस्लामाबाद में भी कोई पूर्णकालिक अमेरिकी राजदूत नहीं है और यह भी नहीं पता कि कब किसी को नामित किया जाएगा। इससे स्वास्थ्य क्षेत्र से लेकर कृषि और शिक्षा तक कई परियोजनाएं रुक गई हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे आर्थिक विकास से जुड़ी चार परियोजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। यह देखना भी दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान और अमेरिका के सैन्य संबंध किस तरह से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अमेरिका के अफगानिस्तान से चले जाने के बाद से ही उसकी इस क्षेत्र में कोई खास दिलचस्पी नहीं रही है। अफगान युद्ध के दौरान दोनों देशों के सैन्य संबंध मजबूत हुए थे। लेकिन अब पाकिस्तान को कोई सैन्य सहायता नहीं मिल रही है। लगता है कि शुरुआत में ट्रंप का सैन्य नेतृत्व सतर्क रुख अपनाएगा, क्योंकि बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि राजनीतिक संबंध कैसे उभरते हैं।